QuizHat

जून -2024 मूल्य ₹ 95/-

करेंट अफेयर्स

जून 2024 करेंट अफेयर्स पर प्रामाणिक संकलन

- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम
- टॉपिक वाइज वर्गीकरण
- वन लाइनर महत्त्वपूर्ण तथ्य
- परीक्षाओं के लिए अभ्यास प्रश्न

अपडेट्स एवं क्विज़ के लिए

डाउनलोड ऐप

मुख्य आकर्षण

18वीं लोक सभा का चुनाव

ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024

पुष्पक : आरएलवी LEX-03

ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024

संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग सहित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी

QuizHat

प्रिय अभ्यर्थी,

जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने की पहली शर्त यह है कि पाठ्यक्रम के अनुरूप अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास किया जाए।

इसी बिंदु को ध्यान में रखते हुए हमने क्विज़हैट ऐप तैयार किया है जो अभ्यर्थियों को अभ्यास के लिए पाठ्यक्रम के अनुरूप महत्त्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध कराता है।

प्रश्नों की सम्पूर्ण श्रृंखला विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों के साथ ही नवीन प्रश्नों के समावेश से तैयार की गयी है। इन प्रश्नों का बार-बार अभ्यास महत्त्वपूर्ण विषयों पर आपकी समझ को बढ़ायेगा और परीक्षा में अच्छे अंक लाने में सहायक होगा।

मोबाइल पर प्रश्नों का अभ्यास करना बोझिल न हो इसलिए ऐप में केवल 10-10 प्रश्नों के सेट तैयार किये गये हैं, जिनका आप जितनी बार चाहे उतनी बार अभ्यास कर सकते हैं।

हम आशा करते हैं कि यह ऐप आपकी तैयारी का सही मूल्यांकन करके आपको और बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगा।

शुभकामनाओं सहित क्विज़हैट

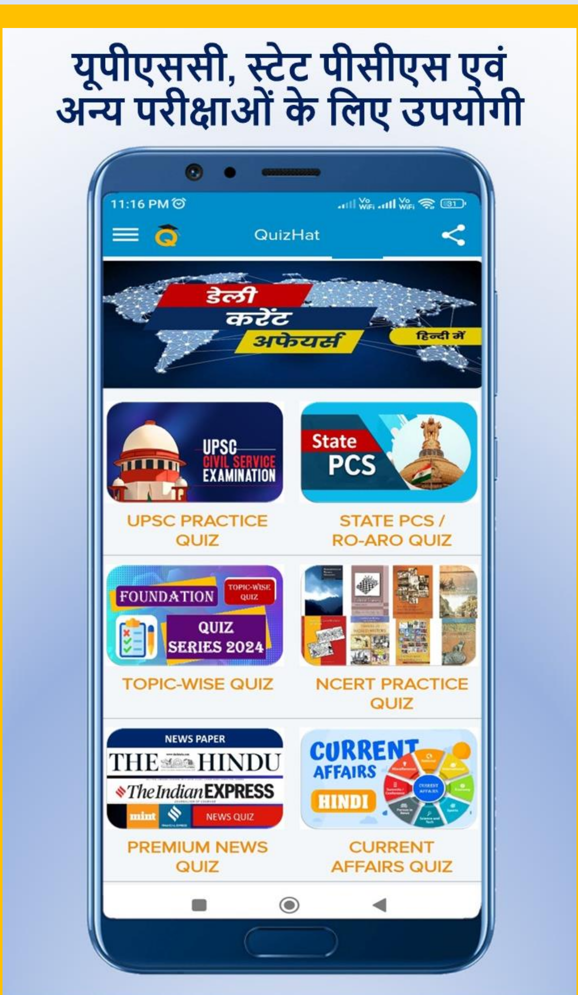

QuizHat ऐप

- UPSC, UPPCS एवं अन्य परीक्षाओं के लिये महत्वपूर्ण प्रश्न
- UP RO/ARO 2023 के लिए अभ्यास प्रश्न
- प्रतिदिन टॉपिक-वाइज अभ्यास प्रश्न
- NCERT पर आधारित अभ्यास प्रश्न
- दैनिक करेंट अफेयर्स एवं संबंधित प्रश्न
- द हिन्दू, इंडियन एक्सप्रेस पर आधारित प्रश्न
- कुल 3000 से अधिक प्रश्न
- उत्तर व्याख्या सहित टेस्ट के PDF

गूगल प्ले स्टोर से QuizHat ऐप डाउनलोड करें

GET IT ON Google Play

विषय

1. समसामयिक मुद्दे 4
कोयला जनित बिजली में कमी से उत्पन्न चुनौती 4
भारत में रेल दुर्घटना 6
भारत की "पड़ोस पहले" नीति 7
फ्रांस में चुनाव 8
2025 तक भारत बनेगा चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 9
भारत में अनाज की मांग में परिवर्तन 10
भारत में भूजल क्षरण 11
शहरी विस्तार से दिल्ली में बाढ़ का खतरा 12
ग्रेट निकोबार परियोजना में रणनीतिक अनिवार्यता और पर्यावरण संबंधी चिंता 13
2. राष्ट्रीय घटनाक्रम 15
18वीं लोकसभा चुनाव 15
संसदीय चुनावों के साथ चार राज्यों ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हुए हैं। 15
मत्स्य प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन 15
एआईएम – आईसीडीके वाटर चैलेंज 4.0 16
डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना 16
अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम 2005 में संशोधन 16
चिनाब रेल पुल पर रेलवे का सफल ट्रायल रन 17
श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा 18
राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्द्धन योजना 18
3. अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम 19
वैश्विक एयरलाइन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत 19
भारत ने कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता संभाली 19
बायोफार्मास्युटिकल एलायंस 19
बाल पोषण रिपोर्ट 2024 20
अभ्यास रेड फ्लैग 2024 20
अभ्यास तरंग शक्ति-2024 20
ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 20
ह्यूमन अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमियासिस 21
ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 21
डेलोस पुरातात्विक स्थल के एजियन सागर में डूबने का संकट 21
पैंटानल आर्द्रभूमि में आग की घटनाएं 22
यूरोप में डेंगू का प्रसार 22
भारत द्वारा 'आईएसओ परिषद बैठक' की मेज़बानी 23
शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन 23
भारत-बंगलादेश संबंध 23
यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 24
पूर्वी तटीय रेल लिंक परियोजना 24
4. राजव्यवस्था एवं शासन 25
कैबिनेट समिति का गठन 25
आनुपातिक प्रतिनिधित्व 26
प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति 26
विपक्ष के नेता 26
लोकसभा अध्यक्ष 27
लोकसभा उपाध्यक्ष 28
केरल विधानसभा में राज्य का नाम बदलने के लिए संकल्प पारित 29

QuizHat

नवनिर्वाचित सांसदों द्वारा शपथ 29
लोकसभा चुनाव 2024 में महिला प्रतिनिधित्व 30
5. अर्थव्यवस्था 32
प्रेस्टन वक्र 32
नई गरीबी रेखा की आवश्यकता 32
ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स' रिपोर्ट 32
वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स के एक समूह में भारत शामिल 33
पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण 33
एंजेल टैक्स 33
6. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 35
पैरेंग्योडोन्टियम एल्बम 35
बायोल्यूमिनसेंट मशरूम 35
'फेनोम इंडिया' परियोजना 35
दुर्लभ संवेदी तंत्रिका श्रवण हानि (rare sensorineural nerve hearing loss) 36
पुष्पक : आरएलवी लेक्स-03 37
चंद्रयान-4 मिशन में डॉकिंग 37
चीन का चांग'ई-6 मिशन 37
7. पर्यावरण एवं परिस्थितिकी 39
स्ट्रोमेटोलाइट्स शैवाल 39
स्पॉट-बेलीड ईगल आउल 39
पैरापैराट्रेचिना नीला (Paraparatrechina neela) 39
हूलॉक गिब्बन के लिए कैनोपी पुलों के निर्माण 40
नाइट्रस ऑक्साइड (N2O) का उत्सर्जन 40
हिंदू कुश हिमालय 40
डायटम की एक नई प्रजाति की खोज 41
चीतल और सांभर का बर्दा वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरण 41
लाल सिर वाले गिद्धों के लिए संरक्षण और प्रजनन केंद्र 42
डेनमार्क द्वारा पशुपालकों पर कर लगाने की योजना 42
गैंडों के सींगों में रेडियोधर्मी पदार्थ इंजेक्ट 43
भारतीय घरेलू कौवे (Indian House Crows) 43
गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में चीतें 44
स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 44
डायरेक्ट सीडिंग ऑफ़ राइस 45
राइन नदी के जलस्तर में वृद्धि 45
मेक्सिको की खाड़ी में डेड ज़ोन 46
8. कला एवं संस्कृति 47
अहिल्या बाई होल्कर की 300वीं जयंती 47
नालंदा विश्वविद्यालय 47
9. खेल 49
ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 49
ब्रिक्स खेल 2024 50
10. महत्वपूर्ण दिवस 51
विश्व पर्यावरण दिवस 51
विश्व महासागर दिवस 51
विश्व शरणार्थी दिवस 2024 51
विश्व जल सर्वेक्षण दिवस 2024 51
11. वन लाइनर 53
12. महत्वपूर्ण शब्दावली 56
ग्लोबल साउथ 56
एंजल टैक्स 56

पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र ... 56
13. प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न ... 57
14. मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न ... 62
QuizHat

समसामयिक मुद्दे

कोयला जनित बिजली में कमी से उत्पन्न चुनौती

नेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया (NFI) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कोयले से उत्पन्न बिजली में कमी किये जाने से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को कम वेतन वाली अनियमित नौकरियों से लेकर गंभीर स्वास्थ्य स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है।

झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के छह जिलों में, जो भारत का 70 प्रतिशत कोयला उत्पादन करते हैं, कोयला खदानों और कोयला-संबंधित गतिविधियों के 10 किलोमीटर के क्षेत्र में 1,209 घरों का सर्वेक्षण किया गया।

सर्वेक्षण कोयला-संबंधित जिलों रामगढ़, रायगढ़ और जाजपुर और कोयला उत्पादक जिलों कोरिया, धनबाद और अंगुल में किया गया, जहाँ उद्योग और अन्य आर्थिक गतिविधियाँ कोयले पर निर्भर हैं। **ओडिशा का अंगुल भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक जिला** है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

रिपोर्ट में कहा गया है भारत धीरे-धीरे कोयले के इस्तेमाल को कम कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप कोयले पर निर्भर क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नौकरियां खत्म हो रही हैं और आर्थिक मंदी आ रही है। इसका प्रभाव न केवल **कोयला खनिकों और श्रमिकों पर (हाशिए पर पड़े समूहों) बल्कि व्यापक स्थानीय अर्थव्यवस्था** पर भी पड़ेगा।

संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तुत भारत द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contribution) में **2005 के स्तर से 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45 प्रतिशत तक कम करने** और **2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन पर आधारित स्रोतों से 50 प्रतिशत विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करने की प्रतिबद्धता** व्यक्त की गई है।

इसके लिए भारत कोयले के इस्तेमाल को चरणबद्ध तरीके से कम करने की योजना बना रहा है। 2021 की एनएफआई रिपोर्ट के अनुसार, कोयले के उपयोग में कमी किये जाने से 13 मिलियन लोगों पर असर पड़ने की उम्मीद है और 266 जिले इस बदलाव के प्रति संवेदनशील होंगे।

कोयले पर निर्भरता

हाल के वर्षों में **भारत ने अपने कोयला उत्पादन में लगातार वृद्धि** की है। हालाँकि, यह देश की नेट-ज़ीरो हासिल करने की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बिल्कुल विपरीत है। इसने **2030 तक अपनी विद्युत की ज़रूरतों का 50% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से और 2070 तक 100% पूरा करने का वादा** किया है।

भारत में बिजली की मांग बढ़ रही है। रॉयटर्स की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, 2022 में, आवश्यकता **लगभग 8% बढ़ी है, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र की तुलना में लगभग दोगुनी गति से, पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 149.7 टेरावाट-घंटे (TWh) से अधिक** है।

इस वृद्धि का मुख्य कारण उच्च आर्थिक गतिविधि है। औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियाँ देश में ऊर्जा के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हाल के वर्षों में **भारत में बिजली की खपत का एक चौथाई हिस्सा घरों में और छठे से ज़्यादा हिस्सा कृषि में खर्च** होता है।

इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के नवीनतम विश्व ऊर्जा परिदृश्य के अनुसार, अगले 30 वर्षों में भारत में दुनिया के किसी भी देश या क्षेत्र की तुलना में सबसे अधिक ऊर्जा मांग वृद्धि देखी जाएगी। इसमें यह भी कहा गया है कि **घरेलू एयर कंडीशनर चलाने के लिए देश की बिजली की आवश्यकता 100 मिलियन टन से अधिक है। अनुमान है कि 2050 तक इसकी क्षमता नौ गुना बढ़ जाएगी और यह आज पूरे अफ्रीका में होने वाली कुल बिजली खपत से भी अधिक** हो जाएगी।

कोयला ही एकमात्र समाधान

बिजली की बढ़ती मांग भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। इसके परिणामस्वरूप, इसने अपने कोयला उत्पादन को दोगुना कर दिया है। कोयला मंत्रालय के अनुसार, यह **2021-22 में 778 मिलियन टन से बढ़कर 2022-23 में 893 मिलियन टन हो गया, जो 14% की वृद्धि** है।

भारत ने 2024-25 के लिए 1.31 बिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य भी रखा है और 2030 तक इसे 1.5 बिलियन टन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।

लेकिन भारत की बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने के लिए कोयला ही इस समय देश में एकमात्र व्यवहार्य विकल्प है। इसके चार कारण हैं-

1. भारत हाल के वर्षों में बिजली उत्पादन में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह ज़रूरतों को पूरा करने के करीब भी नहीं है। वर्तमान में **देश में उत्पादित कुल ऊर्जा में से केवल 22% ही अक्षय स्रोतों से आता है। जीवाश्म ईंधन, मुख्य रूप से कोयला, अभी भी भारत की 75% बिजली आपूर्ति प्रदान करता** है।
2. नवीकरणीय ऊर्जा ऊर्जा उत्पादन का विश्वसनीय स्रोत नहीं है। सौर और पवन जैसे ऊर्जा स्रोत परिवर्तनशील हैं क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश, हवा और पानी की उपलब्धता जैसे प्राकृतिक कारकों पर निर्भर करते हैं। स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, भारत को बैटरी भंडारण में भारी निवेश करना होगा। "**2030 के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य की क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए इसे 60 गीगावाट से अधिक बैटरी भंडारण की आवश्यकता** है।"
3. भारत के लिए एक प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जलविद्युत की अपनी जटिलताएँ हैं। **अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम सहित हिमालयी क्षेत्र में कई जलविद्युत परियोजनाएँ निर्माणाधीन** हैं या योजना के चरणों में हैं। लेकिन वे आलोचनाओं के घेरे में आ गई हैं क्योंकि परियोजनाओं ने पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँचाया है।
4. परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की मदद से ऊर्जा पैदा करने की देश की योजना वास्तव में आगे नहीं बढ़ पाई है। लोकसभा में दिए गए एक जवाब में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि 2021-22 के दौरान, संयंत्रों ने भारत में उत्पादित कुल बिजली का लगभग 3.15% उत्पादन किया।

आगे की राह

भारत का लक्ष्य **2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता तक पहुंचना है, जो वर्तमान क्षमता 180 गीगावाट से लगभग तीन गुना है। हालांकि, अक्षय ऊर्जा से जुड़ी बाधाओं को देखते हुए, यह कोयले से पैदा होने वाली बिजली पर निर्भर रहना जारी** रखेगा।

पिछले वर्ष केंद्रीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा था कि यह उम्मीद करना गलत है कि भारत अपनी कोयला क्षमता में कटौती करना शुरू कर देगा और देश कोयले के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की नहीं, बल्कि इसे कम करने की योजना को लागू करेगा।

मुख्य परीक्षा प्रश्न : "पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव के बावजूद, कोयला खनन अभी भी विकास के लिए अपरिहार्य है"। चर्चा कीजिये। (यूपीएससी सीएसई 2017)

भारत में रेल दुर्घटना

भारतीय रेलवे रविवार **16 जून को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के पास एक मालगाड़ी और एक यात्री ट्रेन कंचनजंगा एक्सप्रेस के बीच हुई टक्कर** के बाद फिर से चर्चा में है, जिसमें कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई और 40 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं।

1995 से अब तक देश में सात घातक रेल दुर्घटनाएँ हुई हैं, जिनमें से पाँच में 200 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। इन सात हादसों में कुल मिलाकर 1,600 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी।

यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भारतीय रेलवे (आईआर), जिसका रेल परिवहन पर एकाधिकार है, एक गंभीर संकट का सामना कर रहा है-

भारतीय रेलवे की बाजार हिस्सेदारी में कमी

भारतीय रेलवे ने यात्री और माल ढुलाई दोनों ही क्षेत्रों में लगातार बाजार हिस्सेदारी खो दी है। वास्तव में, **2010-12 से माल ढुलाई और यात्री यातायात दोनों की कुल मात्रा स्थिर या घट** गई है, जबकि हवाई और सड़क साधनों में **हर साल 6-12 प्रतिशत की वृद्धि** देखी गई है। **2014-15 और 2019-20 के बीच, यात्री यातायात 995 बिलियन यात्री किमी से घटकर 914 बिलियन यात्री-किमी हो गया है और माल ढुलाई 682 और 739 बिलियन नेट टन-किमी के बीच स्थिर** रही।

रेलवे बोर्ड एक पतवारविहीन जहाज

पिछले दो दशकों में, केंद्रीय रेल मंत्री के अधीन सर्वोच्च प्रशासनिक निकाय रेलवे बोर्ड एक पतवारविहीन जहाज रहा है, जिसकी पहचान भारतीय रेलवे नेटवर्क के भविष्य के विकास और विस्तार के लिए नीतियों और योजनाओं में अचानक बदलावों से हुई है। यह अपनी **बेहद धीमी गति से चलने वाली ट्रेनों की गति बढ़ाने में विफल रहा है, ट्रेनों की समयबद्धता में कोई सुधार नहीं हुआ है और सुरक्षा चिंताजनक बनी** हुई है।

औसत गति में कोई वृद्धि नहीं

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने हाल ही में **भारतीय रेलवे पर सुरक्षा, गति और समयबद्धता पर दो महत्वपूर्ण रिपोर्ट (reports on safety, speed, and punctuality) जारी** की हैं। वर्ष 2019-20 के लिए गति और समयबद्धता पर रिपोर्ट कहती है कि **2014 से 2019 के बीच मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की औसत गति में कोई वृद्धि नहीं हुई** है। यह 50 से 51 किमी प्रति घंटे पर बनी हुई है, जो **मिशन रफ्तार के तहत 75 किमी प्रति घंटे की औसत गति हासिल करने के दावों के विपरीत** है।

मालगाड़ियों के लिए, औसत गति वास्तव में मामूली रूप से कम हुई है, जो बोर्ड के गति को दोगुना करने के दावों के विपरीत है। यह उल्लेख करना उचित है कि 20 साल पहले, भारतीय रेलवे ने अधिकतम परिचालन गति 110-130 किमी प्रति घंटे से बढ़ाकर 160-200 किमी प्रति घंटे करने के लिए कोच और लोकोमोटिव बनाने की तकनीक और विनिर्माण क्षमता हासिल की थी।

रेल दुर्घटनाओं में वृद्धि

दुर्घटनाओं पर आधारित दूसरी सीएजी रिपोर्ट भी उतनी ही चिंताजनक है। हालांकि दुर्घटनाओं की संख्या में कुछ कमी आई है, लेकिन यह काफी हद तक मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग पर कर्मियों की तैनाती का नतीजा है।

आंकड़ों से पता चलता है कि पटरी से उतरने और टकराव के मामले में बहुत कम सुधार हुआ है। रिपोर्ट में परिसंपत्तियों की विफलताओं, विशेष रूप से सिग्नल विफलताओं और रेल फ्रैक्चर की निरंतर उच्च दर के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की गई है।

भारतीय रेलवे पर सबसे खराब दुर्घटनाओं में से कुछ इन्हीं के कारण से हुई हैं। पिछले साल **बालासोर में कई ट्रेनों की टक्कर सिग्नल विफलता के कारण** हुई थी।

भारत की "पड़ोस पहले" नीति

हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की "पड़ोस पहले" नीति (Neighborhood First Policy) के तहत सात पड़ोसी देश बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, मॉरीशस और सेशेल्स शामिल हुए।

भारत की "पड़ोस पहले" नीति (Neighborhood First Policy) दक्षिण एशिया के देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित है। यह नीति भारत के विदेश नीति की प्रमुख दिशा है और इसका उद्देश्य भारत के पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्ण और सहकारी संबंध स्थापित करना है।

प्रमुख बिंदु:

1. **सामरिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना:** भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यापार, निवेश, और बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग बढ़ाना चाहता है।
2. **सुरक्षा और स्थिरता:** सीमा सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी उपायों, और क्षेत्रीय स्थिरता को सुनिश्चित करना नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
3. **सांस्कृतिक और जन-संपर्क:** सांस्कृतिक आदान-प्रदान, शिक्षा और जनसंपर्क को बढ़ावा देना ताकि लोगों के बीच संपर्क और समझ को बढ़ाया जा सके।
4. **क्षेत्रीय सहयोग:** दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (SAARC) और अन्य क्षेत्रीय मंचों के माध्यम से सहयोग को बढ़ावा देना।

हालिया पहलें और प्रयास:

भारत-भूटान संबंध: दोनों देशों के बीच जलविद्युत परियोजनाओं में सहयोग और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देना।

भारत-बांग्लादेश संबंध: द्विपक्षीय व्यापार, सीमा प्रबंधन, और जल संसाधनों के प्रबंधन में सहयोग।

भारत-नेपाल संबंध: बुनियादी ढांचे के विकास, ऊर्जा सहयोग, और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना।

भारत-श्रीलंका संबंध: आर्थिक सहयोग, मछली पालन, और सुरक्षा मामलों में सहयोग।

भारत की "पड़ोस पहले" नीति (Neighbourhood First Policy) का उद्देश्य पड़ोसी देशों के साथ मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना है। इस नीति के तहत हाल के कुछ प्रमुख पहलें निम्नलिखित हैं:

1. COVID-19 वैक्सीन डिप्लोमेसी :

भारत ने "वैक्सीन मैत्री" अभियान के तहत पड़ोसी देशों को COVID-19 वैक्सीन प्रदान की। इनमें बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, और म्यांमार शामिल हैं। इस पहल से भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ चिकित्सा सहयोग को मजबूत किया।

2. आर्थिक और विकासात्मक सहायता:

भारत ने विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के माध्यम से अपने पड़ोसी देशों को आर्थिक सहायता प्रदान की है। इसमें भूटान के लिए हाइड्रोपावर परियोजनाएं, नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, और श्रीलंका में आवासीय परियोजनाएं शामिल हैं।

3. आपदा प्रबंधन और मानवीय सहायता:

आपदाओं के समय भारत ने पड़ोसी देशों को त्वरित सहायता प्रदान की है। जैसे **2015 में नेपाल में भूकंप के दौरान भारत ने ऑपरेशन मैत्री** के तहत व्यापक राहत कार्य किए। इसी प्रकार, श्रीलंका में बाढ़ और भूटान में भूकंप के समय भी भारत ने सहायता प्रदान की है।

4. बांग्लादेश के साथ संबंध:

भारत और बांग्लादेश के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, जैसे कि **चटगांव और मोंगला बंदरगाहों के उपयोग, त्रिपुरा में अगरतला-अखौरा रेल लिंक, और बांग्लादेश में बिजली की आपूर्ति बढ़ाने के लिए सहयोग**।

5. श्रीलंका के साथ संबंध:

भारत ने श्रीलंका में आवासीय परियोजनाओं और रेल्वे विकास परियोजनाओं में निवेश किया है। इसके अलावा, श्रीलंका को COVID-19 के दौरान मेडिकल सप्लाई और वैक्सीन भी भेजी गईं।

6. मालदीव के साथ संबंध:

भारत ने मालदीव को COVID-19 महामारी के दौरान मेडिकल सहायता, आर्थिक पैकेज, और वैक्सीन भेजी। इसके अलावा, मालदीव में इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी भारत ने निवेश किया है।

7. नेपाल के साथ संबंध:

भारत ने नेपाल में हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स, सड़कों और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में सहयोग किया है। इसके अलावा, नेपाल को COVID-19 वैक्सीन और अन्य मेडिकल सप्लाई भी भेजी गईं।

8. भूटान के साथ संबंध:

भारत और भूटान के बीच हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा, भूटान को वैक्सीन और मेडिकल सप्लाई भी भेजी गईं। भारत ने भूटान के विकासात्मक लक्ष्यों को पूरा करने में भी मदद की है।

9. म्यांमार के साथ संबंध:

भारत ने म्यांमार के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया है, जिसमें कललादान मल्टी-मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट और त्रिपुरा से म्यांमार तक सड़क मार्ग शामिल हैं। इसके अलावा, म्यांमार को भी वैक्सीन और मेडिकल सहायता प्रदान की गई।

10. कनेक्टिविटी पहल:

भारत ने **BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) और BBIN (Bangladesh, Bhutan, India, Nepal) पहल के माध्यम से कनेक्टिविटी और व्यापार को बढ़ावा** दिया है।

चुनौतियां:

सीमा विवाद : कुछ पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद और जल संसाधनों का विवाद।

आंतरिक राजनीति: पड़ोसी देशों की आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता का प्रभाव।

बाहरी हस्तक्षेप: क्षेत्रीय शक्तियों जैसे चीन के हस्तक्षेप और प्रभाव को संतुलित करना।

तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में दक्षिण एशिया और हिंद महासागर के नेताओं की मौजूदगी "पड़ोस पहले" नीति के प्रति दिल्ली की निरंतर प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। "पड़ोस पहले" नीति भारत की विदेश नीति की एक महत्वपूर्ण पहल है जो दक्षिण एशिया में शांति, स्थिरता, और समृद्धि को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करती है।

फ्रांस में चुनाव

30 जून और 7 जुलाई को दो दौर के मतदान के बाद, फ्रांस एक नई नेशनल असेंबली का चुनाव करेगा। 22 वर्ष में पहली बार, **इस बात की पूरी संभावना है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक ही पार्टी से नहीं होंगे।**

इस घटना को **कोहैबिटेशन कहा जाता है, और फ्रांस के पांचवें गणतंत्रमें परिवर्तन के बाद से ऐसा केवल तीन बार हुआ** है।

इस प्रणाली से ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो सकती हैं जहाँ फ़्रांसीसी संसद पर राष्ट्रपति का विरोध करने वाले गठबंधन/पार्टी का प्रभुत्व हो। ऐसे मामलों में, राष्ट्रपति को विरोधी पार्टी के किसी नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करना पड़ता है, जिसे संसदीय बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है।

पांचवां गणतंत्र

फ्रांस एक अर्ध-अध्यक्षीय, प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र है, जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की भूमिकाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं।

वर्तमान राजनीतिक शासन, जिसे **पांचवां गणतंत्र कहा जाता है, पहली बार 1958 में लागू हुआ,** जिसने पूर्व संसदीय गणतंत्र प्रणाली को प्रतिस्थापित किया, जिसे **राजनीतिक विशेषज्ञ जीन वी. पोलार्ड ने "दोहरे सिर वाली कार्यपालिका" (double-headed executive)** कहा है।

चौथा गणतंत्र, जो 1946 से 1958 तक अस्तित्व में रहा, एक संसदीय प्रणाली थी जिसमें सत्ता प्रभावी रूप से संसद के निचले सदन में केंद्रित थी। पूर्ण बहुमत के अभाव में, गठबंधन मंत्रिमंडलों की एक श्रृंखला हर छह महीने में एक दूसरे को बदल देती थी - 12 वर्षों में, फ्रांस ने 16 प्रधानमंत्रियों को आते-जाते देखा, और कुल 24 मंत्रिमंडल बने।

1958 के नए संविधान ने पांचवें गणतंत्र की शुरुआत की, जिसमें कार्यकारी शक्ति बहाल की गई। 1962 से, फ्रांसीसी राष्ट्रपति को सीधे लोकप्रिय वोट द्वारा चुना जाता है, जबकि प्रधानमंत्री नेशनल असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी/गठबंधन का नेता होता है।

राष्ट्रपति बनाम प्रधानमंत्री

राष्ट्रपति, पांच साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं, वे राज्य के प्रमुख और सशस्त्र बलों के कमांडर के रूप में कार्य करते हैं। उन्हें विनियामक शक्ति प्राप्त है, जो विदेश नीति और रक्षा के मामलों पर सभी निर्णयों पर नियंत्रण रखते हैं। 2000 तक, राष्ट्रपति के पास सात वर्ष का कार्यकाल था, जिसे बाद में घटाकर पांच वर्ष का कर दिया गया।

इसके विपरीत, **प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली नेशनल असेंबली सभी घरेलू नीतिगत निर्णयों के लिए जिम्मेदार** होती है। फ्रांसीसी संविधान का अनुच्छेद 21 प्रधानमंत्री को "सरकार के कार्यों को निर्देशित करने" की शक्ति देता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त नहीं किया जा सकता, लेकिन उनसे इस्तीफा मांगा जा सकता है। राष्ट्रपति पर संविधान या राष्ट्रीय कानूनों का जानबूझकर उल्लंघन करने के लिए संसद द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। इसके लिए **फ्रांसीसी संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता** होती है, साथ ही दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में भी इसे पारित करना होता है।

आगामी चुनाव

फ्रांसीसी संसद एक द्विसदनीय विधायिका है जिसमें एक उच्च सदन, सीनेट और एक निचला सदन, नेशनल असेंबली शामिल है। आगामी चुनाव नेशनल असेंबली की 577 सीटों के लिए विधायकों का चुनाव करेंगे, जिसमें 13 विदेशी जिले और 11 निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं जो विदेश में फ्रांसीसी प्रवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल करने के लिए 289 सीटों की आवश्यकता होती है।

चुनाव दो चरणों में होंगे। पहला चरण 30 जून को होगा, जो उन उम्मीदवारों को बाहर कर देगा जो स्थानीय रूप से पंजीकृत 12.5% वोट जीतने में विफल रहते हैं। इसके अलावा, 50% वोट और कम से कम 25% स्थानीय चुनावी मतदान वाला कोई भी उम्मीदवार कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में स्वतः ही जीत जाता है।

7 जुलाई को होने वाले दूसरे चरण में दो से चार उम्मीदवारों के बीच कड़ी टक्कर होगी, तथा आमतौर पर इसी समय गठबंधन का निर्णय सामने आता है।

2025 तक भारत बनेगा चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

भारत के जी-20 शेरपा और नीति आयोग के पूर्व सीईओ **अमिताभ कांत ने विभिन्न मैक्रोइकोनॉमिक मापदंडों का हवाला देते हुए अनुमान लगाया कि भारत 2025 तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था** बन जाएगा।

भारत की जीडीपी का आकार **वर्तमान में अमेरिका , चीन, जर्मनी और जापान के बाद 5वें स्थान** पर है। **2022 में यह ब्रिटेन से आगे निकल** गया था।

एक दशक पहले, भारत की जीडीपी दुनिया में ग्यारहवीं सबसे बड़ी जीडीपी थी। वर्तमान में, भारत की जीडीपी लगभग 3.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है।

प्रमुख कारण

1. **उच्च जीडीपी वृद्धि दर:** भारत की अर्थव्यवस्था में स्थिरता और वृद्धि दर ने पिछले कुछ वर्षों में सकारात्मक रुझान दिखाया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर को मजबूत बताया है।

2. **जनसंख्या और उपभोग :** भारत की विशाल जनसंख्या और बढ़ती मध्यवर्गीय आबादी उपभोग में वृद्धि कर रही है, जिससे अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है।

3. **औद्योगिक और प्रौद्योगिकीय प्रगति :** विनिर्माण, सेवा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में तेजी से हो रहे विकास ने आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित किया है।

4. **सुधार और नीतियाँ :** सरकार द्वारा लागू किए गए विभिन्न आर्थिक सुधारों और नीतियों ने व्यवसाय करने की सुविधा बढ़ाई है और निवेश आकर्षित किया है।

चुनौतियाँ

हालांकि, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है:

1. **बेरोजगारी :** रोजगार सृजन और कौशल विकास के क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है।

2. **गरीबी और असमानता :** गरीबी उन्मूलन और आर्थिक असमानता को कम करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है।

3. **बुनियादी ढाँचा :** आधारभूत संरचना में सुधार और उन्नति की आवश्यकता है, जिससे लॉजिस्टिक्स और व्यापार में सुविधा हो।

निष्कर्ष

QuizHat

यदि भारत अपने वर्तमान विकास पथ पर कायम रहता है और ऊपर उल्लिखित चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करता है, तो 2025 तक जापान को पीछे छोड़ते हुए चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। यह न केवल भारत के लिए बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा।

भारत में अनाज की मांग में परिवर्तन

कृषि मंत्रालय के अनुसार, पिछले दो दशकों में **भारत का अनाज उत्पादन 1.5 गुना से अधिक बढ़** गया है। लेकिन **घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) के आंकड़ों से यह बात प्रमाणित होता है कि इसका एक बड़ा हिस्सा सीधे मानव उपभोग के लिए नहीं, बल्कि प्रसंस्कृत रूप में (जैसे ब्रेड, बिस्कुट, केक, नूडल्स, सेंवई, फ्लेक्स, पिज्जा बेस, आदि) या पशु चारा, स्टार्च, शराब और इथेनॉल ईंधन बनाने के लिए इस्तेमाल** किया जा रहा है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय की नवीनतम एचसीईएस रिपोर्ट से यह पता चलता है कि 1999-2000 और 2022-23 के बीच एक औसत व्यक्ति द्वारा प्रति माह उपभोग किए जाने वाले अनाज की मात्रा में लगातार गिरावट आई है - **ग्रामीण क्षेत्रों में यह 12.72 किलोग्राम से घटकर 9.61 किलोग्राम और शहरी भारत में 10.42 किलोग्राम से घटकर 8.05 किलोग्राम** रह गया है।

देश की आबादी के साथ 12 महीनों में उपर्युक्त भारित औसत को गुणा करने पर भारतीय परिवारों द्वारा प्रत्यक्ष या घर पर संसाधित अनाज की कुल वार्षिक खपत प्राप्त होती है। जैसा कि तालिका 1 से पता चलता है कि **1999-2000 में अनाज की कुल वार्षिक खपत 148.4 मिलियन टन (एमटी) से बढ़कर 2022-23 में 153.1 एमटी** हो गया है।

TABLE 1

INDIA'S ESTIMATED HOUSEHOLD CEREAL CONSUMPTION VERSUS PRODUCTION

Monthly per capita cereal consumption (in kg)

	1999-2K	2004-05	2009-10	2011-12	2022-23
Rural	12.72	12.12	11.35	11.23	9.61
Urban	10.42	9.94	9.39	9.32	8.05
Weighted Average#	11.78	11.33	10.54	10.44	8.97
Population##	1050.01	1145.64	1232.08	1266.1	1422.03
Annual Consumption*	148.43	155.76	155.83	158.62	153.07
Annual Production*	196.38	185.23	203.45	242.2	303.63

*#Weights based on number of sample households in consumption expenditure surveys; ##In million; *In million tonnes.*

इस प्रकार आंकड़ों से पता चलता है कि प्रत्यक्ष घरेलू खपत स्थिर हो गई है, यहाँ तक कि इसमें गिरावट भी आई है, लेकिन उत्पादन के मामले में ऐसा नहीं है, जो **1999-2000 में 196.4 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 303.6 मीट्रिक टन** हो गया है।

आधिकारिक तौर पर अनुमानित अनाज उत्पादन और एचसीईएस-आधारित घरेलू खपत के बीच का अंतर भी 1**999-2000 में मुश्किल से 48 मीट्रिक टन और 2004-05 में 29.5 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में लगभग 151 मीट्रिक टन** हो गया है।

यह अतिरिक्त उत्पादन कहां जा रहा है?

इसका **एक हिस्सा निर्यात** किया जा रहा है, यानी देश से बाहर जा रहा है। **2021-22 (अप्रैल-मार्च) में, भारत ने रिकॉर्ड 32.3 मीट्रिक टन अनाज निर्यात** किया, जिसमें 21.2 मीट्रिक टन चावल, 7.2 मीट्रिक टन गेहूं और 3.9 मीट्रिक टन अन्य अनाज (मुख्य रूप से मक्का) शामिल हैं।

2022-23 में भी, अनाज का निर्यात कुल 30.7 मीट्रिक टन रहा, जिसमें 22.3 मीट्रिक टन चावल, 4.7 मीट्रिक टन गेहूं और 3.6 मीट्रिक टन अन्य अनाज शामिल है।

अंतर का **दूसरा स्रोत घरों में प्रसंस्कृत रूप में उपभोग किए जाने वाले अनाज** होंगे - ब्रेड, बिस्कुट, नूडल्स, आदि।

तीसरा मुख्य स्रोत **फ़ीड या औद्योगिक स्टार्च का निर्माण** है। कृषि मंत्रालय ने 2022-23 में भारत के मक्का उत्पादन को 38.1 मीट्रिक टन आंका है। इसका बड़ा हिस्सा पोल्ट्री, पशुधन और एक्वा फ़ीड में प्राथमिक ऊर्जा घटक के रूप में उपयोग किया जाता है।

2022-23 में मक्का, जौ और बाजरा, ज्वार (सोरघम) और रागी (फिंगर बाजरा) जैसे मोटे अनाजों का उत्पादन 57.3 मीट्रिक टन हुआ है। इसके विपरीत, भारतीय घरों में इन मोटे अनाजों की प्रत्यक्ष खपत 5 मीट्रिक टन से कम है। इनकी अधिकांश खपत अप्रत्यक्ष रूप में होती है - गायों, भैंसों और पोल्ट्री पक्षियों को खिलाए जाने में।

चारा और स्टार्च निर्माण के अलावा, **अनाज को किण्वित कर एल्कोहल भी बनाया जाता** है और फिर आसवन करके लगभग 94% परिशोधित/औद्योगिक स्पिरिट या 99.9% इथेनॉल बनाया जाता है।

अस्पष्टीकृत अधिशेष

32 मिलियन टन निर्यात, प्रसंस्कृत खाद्य के रूप में उपयोग (38 मिलियन टन) तथा चारे, स्टार्च बनाने और किण्वन प्रयोजनों के लिए उपयोग (50-55 मिलियन टन) के बाद के अधिशेष को सरकारी एजेंसियों द्वारा इकट्ठा किया जा रहा है और भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में जमा किया जा रहा है।

2022-23 फसल वर्ष (जुलाई-जून) में, लगभग 56.9 मीट्रिक टन चावल और 26.2 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए 59-60 मीट्रिक टन की कुल वार्षिक अनाज आवश्यकता से अधिक है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, लगभग 813.5 मिलियन लोगों को पीडीएस के माध्यम से प्रति माह 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया जा रहा है (दिसंबर 2022 तक दोनों के लिए निर्गम मूल्य क्रमशः 2 रुपये और 3 रुपये प्रति किलोग्राम था)।

यदि **कृषि मंत्रालय के अनाज उत्पादन अनुमान सही हैं, तो देश में हर वर्ष कम से कम 25 मीट्रिक टन अतिरिक्त अनाज का उत्पादन हो रहा** है, जिससे सरकारी भंडार में वृद्धि न होने पर भी बाजार कीमतों पर दबाव बढ़ रहा है।

लेकिन हाल ही में **अनाज की उच्च मुद्रास्फीति (मई में 8.69% वार्षिक) के अनुभव को देखते हुए , निर्यात पर प्रतिबंधों के बावजूद, तथा सरकारी गोदामों में घटते स्टॉक (1 जून को गेहूं के लिए 16 वर्ष का निम्नतम स्तर) को देखते हुए, आधिकारिक उत्पादन अनुमानों की सत्यता पर प्रश्न** उठाए जा सकते हैं।

भारत में भूजल क्षरण

संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय - पर्यावरण एवं मानव सुरक्षा संस्थान (UNU-EHS) द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि **भारत भूजल क्षरण के चरम बिंदु पर पहुंचने के करीब** है।

'इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023', जो छह पर्यावरणीय टिपिंग पॉइंट्स - तेजी से बढ़ती विलुप्तता, भूजल की कमी, पर्वतीय ग्लेशियरों का पिघलना, अंतरिक्ष मलबा, असहनीय गर्मी और गैर बीमित भविष्य पर ध्यान केन्द्रित करती है।

भारत की स्थिति

रिपोर्ट के अनुसार, **पंजाब में 78% कुओं का अत्यधिक दोहन हो चुका** है तथा अनुमान है कि **2025 तक समूचे उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में भूजल की उपलब्धता बहुत कम हो जाएगी।**

भारत दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के संयुक्त उपयोग से भी अधिक है।

भारत का उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र देश के बढ़ते 1.4 बिलियन लोगों के लिए अन्न भंडार के रूप में कार्य करता है, पंजाब और हरियाणा राज्य देश की चावल आपूर्ति का 50% और गेहूं के 85% स्टॉक का उत्पादन करते हैं।

वैश्विक स्थिति

रिपोर्ट में कहा गया है, "भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण पृथ्वी की धुरी भी प्रति वर्ष 4.36 सेमी झुक रही है।

जिन क्षेत्रों में **भूजल में सबसे अधिक कमी आई है, उनमें भारत के कुछ हिस्से, उत्तर-पूर्वी चीन, पश्चिमी अमेरिका, मैक्सिको, ईरान, सऊदी अरब और उत्तरी अफ्रीका** के कुछ हिस्से शामिल हैं।"

"सऊदी अरब जैसे कुछ क्षेत्र पहले ही भूजल जोखिम के इस बिंदु को पार कर चुके हैं, भारत जैसे अन्य देश भी इस जोखिम बिंदु के करीब पहुंचने से ज्यादा दूर नहीं हैं।"

क्या है भूजल

भूजल एक आवश्यक मीठे पानी का संसाधन है जिसे भूमिगत जलाशयों में संग्रहित किया जाता है जिसे "एक्विफ़र्स" कहा जाता है।

ये **एक्वीफ़र दो अरब से ज़्यादा लोगों को पीने का पानी देते हैं और लगभग 70% भूजल का उपयोग कृषि के लिए किया जाता** है।

हालाँकि, दुनिया के आधे से ज़्यादा प्रमुख एक्वीफ़र्स प्राकृतिक रूप से फिर से भरने की तुलना में तेज़ी से खत्म हो रहे हैं। चूँकि भूजल हज़ारों सालों में जमा होता है, इसलिए यह अनिवार्य रूप से एक गैर-नवीकरणीय संसाधन है।

भूजल का टिपिंग पॉइंट

भूजल के संबंध में **टिपिंग पॉइंट तब आता है जब जल स्तर उस स्तर से नीचे चला जाता है जिस तक मौजूदा कुएँ पहुँच सकते** हैं। एक बार उस स्तर के पार हो जाने पर, किसानों के पास अपनी फसलों की सिंचाई के लिए भूजल तक पहुँच नहीं हो पाएगी।

इससे न केवल किसानों को अपनी आजीविका खोने का जोखिम है, बल्कि खाद्य असुरक्षा भी हो सकती है और संपूर्ण खाद्य उत्पादन प्रणाली विफल होने का जोखिम हो सकता है।

विश्व का लगभग **30% ताजा जल भूजल के रूप में संग्रहित** है तथा कभी-कभी झरनों, झीलों या नदियों के माध्यम से सतह पर लाया जाता है, या जलभृत में खोदे गए कुओं से निकाला जाता है।

कृषि गहनता एक प्रमुख कारक है जो हमें भूजल क्षरण के जोखिम की ओर धकेल रहा है, क्योंकि भूजल सिंचाई से विश्व की लगभग 40 प्रतिशत फसलों का उत्पादन होता है, जिसमें चावल और गेहूं जैसी प्रमुख फसलों का एक बड़ा हिस्सा शामिल है।

भूजल तक पहुँच ने दुनिया भर में सिंचित कृषि भूमि के विस्तार को बढ़ावा दिया है। **सिंचित कृषि भूमि 1900 में 63 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 2005 में 306 मिलियन हेक्टेयर हो गई** है।

भूजल और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं के बीच एक मजबूत संबंध भी भूजल की कमी को बढ़ावा दे रहा है। अपने भूजल संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करने वाले देशों में उगाए जाने वाले कई उत्पाद दूर-दराज के स्थानों पर बेचे और खाए जाते हैं।

उदाहरण के लिए, **अमेरिका अपने 42% फसलों का निर्यात समाप्त हो चुके भूजल से करता** है, जिनमें से ज़्यादातर मक्का है, जो मैक्सिको, चीन और जापान जैसे अन्य स्थानों को निर्यात करता है।

शहरी विस्तार से दिल्ली में बाढ़ का खतरा

अनियंत्रित और बिना सोचे-समझे किया गया शहरी विस्तार दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में लगातार शहरी बाढ़ का मुख्य कारण बनता जा रहा है।

हाल ही में, हुई भारी बारिश के कारण दिल्ली के कई हिस्से थम से गए थे। शहर भर में और एनसीआर में सड़कें जलमग्न हो गईं, जिससे कुछ जगहों पर घंटों तक यातायात जाम रहा।

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 27-28 जून को 24 घंटे की अवधि में सफ़दरजंग स्टेशन में 228.1 मिमी बारिश दर्ज की, जो 88 साल का उच्चतम स्तर है।

नालों की अपर्याप्त सफाई जैसे कारक भी इसमें भूमिका निभाते हैं, लेकिन इसके मूल में, दिल्ली का बढ़ता शहरी विस्तार है।

तेजी से बढ़ता शहर

दिल्ली दुनिया के सबसे तेज़ शहरी विस्तार में से गुज़र रही है। **नासा की अर्थ ऑब्ज़र्वेटरी के डेटा के अनुसार, 1991 से 2011 तक दिल्ली का भौगोलिक आकार लगभग दोगुना** हो गया है।

इस विस्तार का अधिकांश हिस्सा नई दिल्ली के बाहरी इलाकों में हुआ है, जहाँ पहले ग्रामीण इलाके हुआ करते थे, जो अब राजधानी के शहरी विस्तार में शामिल हो गए हैं।

दिल्ली से बाहर के शहर, लेकिन एनसीआर का हिस्सा - बहादुरगढ़, गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा और गुरुग्राम - में भी तेजी से शहरीकरण हुआ है।

संयुक्त राष्ट्र की 2018 में विश्व के शहरों की डेटा पुस्तिका के अनुसार, **2030 तक दिल्ली, टोक्यो को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर** बन जाएगा, जिसकी अनुमानित जनसंख्या लगभग 39 मिलियन होगी, जो 2000 की जनसंख्या से लगभग ढाई गुना अधिक है।

स्थलाकृति और जल निकासी

हालाँकि, इस शहरी विस्तार में दिल्ली की प्राकृतिक स्थलाकृति पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। जबकि स्थलाकृति जल निकासी पैटर्न निर्धारित करती है। दिल्ली के ऐतिहासिक शहरों - **तुगलकाबाद, महरौली और शाहजहानाबाद से लेकर सिविल लाइंस, नई दिल्ली और कैंटोनमेंट क्षेत्र** तक - सभी को ऊँची भूमि पर बनाया गया था। इससे बारिश का पानी बाहर निकल जाता था। लेकिन जैसे-जैसे शहर का विस्तार हुआ, भूमि की जल निकासी क्षमता के संबंध में निर्माण के पीछे पर्याप्त विचार नहीं किया गया।

कंक्रीटीकरण का विस्तार

शहरीकरण के कारण पानी ढलान से आसानी से नीचे नहीं बह पाता। ज़्यादातर पानी कंक्रीट के नालों में चला जाता है, जिन्हें सीवेज डंप में बदल दिया गया है।

निचले इलाकों में निर्माण कार्य से हालात और भी खराब हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, दक्षिण दिल्ली के कई नाले यमुना के बगल में दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के निचले इलाके सराय काले खां में मिलते हैं। यही कारण है कि इस व्यस्त शहरी गांव में हर साल भयंकर बाढ़ आती है।

दिल्ली के बाढ़ के मैदानों में निर्माण कार्य 1900 के दशक में ही शुरू हो गया था, जब अंग्रेजों ने नदी के किनारे रेलवे लाइन बनाने का फैसला किया था। इसके बाद, रिंग रोड का निर्माण हुआ, जो फिर से यमुना के बाढ़ के मैदान पर हुआ।

पिछले कुछ सालों में, बाढ़ के मैदान का इस्तेमाल पुलों से लेकर इमारतों के निर्माण तक सभी तरह के उद्देश्यों के लिए किया गया है।

कश्मीरी गेट के पास बाढ़ के मैदानों पर लगभग 65 हेक्टेयर भूमि को दिल्ली मेट्रो ने अपने रखरखाव शेड के लिए पुनः प्राप्त किया था।

2010 में राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान, लगभग 25 हेक्टेयर भूमि पर एक बस रखरखाव सुविधा का निर्माण किया गया था, जो बाढ़ के मैदान पर बनाया गया था। आईटीओ-प्रगति मैदान क्षेत्र, जो वर्षों से बाढ़ का सामना कर रहा है, कभी एक निम्न आर्द्रभूमि थी।

इस **कंक्रीटीकरण से बारिश के पानी को मिट्टी में रिसने के लिए बहुत कम जगह मिलती है, जिससे बाढ़ आती** है।

कोई 'वाटर मास्टरप्लान' नहीं

शहरी योजनाकारों को एक "जल मास्टरप्लान" बनाने की जरूरत है। वर्तमान में भूमि को रियल एस्टेट के रूप में देखा जाता है। नियोजन संसाधन के रूप में पानी की लगातार उपेक्षा की गई है, जबकि किसी भी मास्टरप्लानिंग के पीछे पानी प्राथमिक प्रेरक कारक होना चाहिए।

यही कारण है कि, उदाहरण के लिए, **2022 में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया जाने वाला नया प्रगति मैदान सुरंग प्रत्येक मानसून में बाढ़ से भर जाता** है।

बाढ़ को नियंत्रित करने में मदद करने वाले जल निकायों को भी व्यवस्थित तरीके से नष्ट कर दिया गया है। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, दिल्ली में करीब 1,000 जल निकाय हैं। लेकिन ज़मीन पर इनकी संख्या 400 से ज़्यादा नहीं है। ये 600 'गायब' जल निकाय जो शहर में बाढ़ को नियंत्रित कर सकते थे, उन्हें भर दिया गया है और उन्हें रियल एस्टेट में बदल दिया गया है।

आगे की राह

जब तक हम निचले इलाकों में निर्माण कार्य बंद नहीं करेंगे, हमारे लॉन और फुटपाथों को कंक्रीट मुक्त नहीं करेंगे और ठोस कचरे से नालियों को अवरुद्ध करना बंद नहीं करेंगे, तब तक बाढ़ नहीं रुकेगी। निचले इलाकों में जलभृतों तक पानी पहुंचाने के लिए उचित निस्पंदन गड्ढे स्थापित किया जाना चाहिए।

ग्रेट निकोबार परियोजना में रणनीतिक अनिवार्यता और पर्यावरण संबंधी चिंता

हाल ही में, कांग्रेस पार्टी ने **ग्रेट निकोबार द्वीप पर प्रस्तावित 72,000 करोड़ रुपये के बुनियादी ढांचे के उन्नयन को द्वीप के मूल निवासियों और सुभेद्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए "गंभीर खतरा"** बताया है, और "सभी मंजूरियों को तत्काल निलंबित करने" और "संबंधित संसदीय समितियों सहित प्रस्तावित परियोजना की गहन, निष्पक्ष समीक्षा" की मांग की है।

बुनियादी ढांचा परियोजना

मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना, जिसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम (ANIIDCO) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, में एक **अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (ICTT), 4,000 यात्रियों को संभालने की क्षमता वाला एक ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा** शामिल करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा इस परियोजना के तहत एक **टाउनशिप, और 16,610 हेक्टेयर में फैला एक गैस और सौर आधारित बिजली संयंत्र का प्रस्ताव** है।

नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद ग्रेट निकोबार द्वीप के "समग्र विकास" के लिए परियोजना को क्रियान्वित किया गया।

रणनीतिक स्थिति

यह **द्वीप दक्षिण-पश्चिम में श्रीलंका के कोलंबो और दक्षिण-पूर्व में पोर्ट क्लैंग (मलेशिया) और सिंगापुर से लगभग समान दूरी पर** है।

यह **मलक्का जलडमरूमध्य के करीब है, जो हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाला मुख्य जलमार्ग** है।

प्रस्तावित आईसीटीटी और बिजली संयंत्र का स्थान ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिण-पूर्व में गैलाथिया खाड़ी है, जहां कोई मानव निवास नहीं है।

परियोजना को अक्टूबर 2022 में सैद्धांतिक रूप से वन मंजूरी और पर्यावरण मंजूरी दी गई थी।

सामरिक महत्व

बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर क्षेत्र भारत के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक और सुरक्षा हित में है। भारत इंडो-पैसिफिक के चोक पॉइंट्स, खासकर मलक्का, सुंडा और लोम्बोक में चीनी समुद्री बलों के जमावड़े से चिंतित है।

क्षेत्र में अपना विस्तार करने के चीन के प्रयासों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तर में सिर्फ 55 किलोमीटर दूर स्थित कोको द्वीप (म्यांमार) में एक सैन्य सुविधा का निर्माण करना शामिल है।

पर्यावरणीय चिंता

प्रस्तावित बुनियादी ढांचे के उन्नयन का विरोध इस आधार पर किया गया है कि इससे **द्वीपों की पारिस्थितिकी को खतरा** है।

कांग्रेस के अलावा वन्यजीव संरक्षण शोधकर्ताओं, मानवविज्ञानियों, विद्वानों और नागरिक समाज द्वारा किया गया विरोध शोम्पेन पर संभावित विनाशकारी प्रभाव पर केंद्रित है, जो **विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह (PVTG) है, जिसकी अनुमानित आबादी कुछ सौ व्यक्तियों की** है जो द्वीप पर एक आदिवासी रिजर्व में रहते हैं।

यह परियोजना आदिवासी आबादी के अधिकारों का उल्लंघन करती है और लगभग दस लाख पेड़ों की कटाई के साथ द्वीप की पारिस्थितिकी को प्रभावित करेगी।

यह आशंका है कि बंदरगाह परियोजना स्थानीय समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव डालते हुए प्रवाल भित्तियों को नष्ट कर देगी, और **गैलेथिया खाड़ी क्षेत्र में घोंसला बनाने वाले स्थलीय निकोबार मेगापोड पक्षी और कछुओं के लिए खतरा पैदा** करेगी।

ग्रेट निकोबार द्वीप के बारे में

ग्रेट निकोबार निकोबार द्वीपसमूह का **सबसे दक्षिणी और सबसे बड़ा द्वीप** है, जो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्वी भाग में मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय वर्षावन का 910 वर्ग किलोमीटर का एक विरल आबादी वाला क्षेत्र है। **द्वीप पर इंदिरा पॉइंट, जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है**, इंडोनेशियाई द्वीपसमूह के सबसे बड़े द्वीप सुमात्रा के उत्तरी सिरे पर स्थित सबंग से केवल 90 समुद्री मील (170 किमी से कम) की दूरी पर है।

ग्रेट निकोबार में दो राष्ट्रीय उद्यान, एक बायोस्फीयर रिजर्व, शोम्पेन और निकोबारी जनजातीय लोगों की छोटी आबादी और कुछ अन्य गैर-आदिवासी निवासी हैं।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 836 द्वीपों का एक समूह है, जो 150 किलोमीटर चौड़ी 10 डिग्री चैनल द्वारा दो समूहों - उत्तर में अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह में विभाजित है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न : भारत ग्रेट निकोबार को क्यों विकसित करना चाहता है, और प्रस्तावित ग्रेट निकोबार परियोजना को संरक्षणवादियों, वन्यजीव जीवविज्ञानियों, प्रकृतिवादियों और कुछ स्थानीय जनजातीय परिषदों की ओर से लगातार आलोचना का सामना क्यों करना पड़ रहा है?

राष्ट्रीय घटनाक्रम

18वीं लोकसभा चुनाव

भारत में **18वीं लोकसभा चुनाव अप्रैल और मई 2024 में कुल सात चरणों में** आयोजित हुए। पहला चरण 19 अप्रैल 2024 को जबकि सातवाँ चरण 01 जून 2024 को संपन्न हुआ। इसके अलावा **मतगणना 4 जून 2024 को** किया गया। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून, 2024 को समाप्त हुआ है।
केवल **तीन ऐसे राज्य हैं, जहां सात चरणों में चुनाव हुए हैं। ये राज्य हैं- उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल**। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, बिहार में 40 और पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं।

इस लोकसभा चुनाव में कुल **96.8 करोड़ पंजीकृत मतदाता** शामिल हुए हैं, इनमें **47.1 करोड़ महिलाएं और 49.7 करोड़ पुरुष मतदाता** हैं। इनमें **1.89 करोड़ पहली बार वोट** दे रहे हैं और **19.74 करोड़ युवा मतदाता** हैं, जिनकी उम्र 20 से 29 साल की है।
इस चुनाव में **6 राष्ट्रीय दल ने भाग लिया** हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी (BJP), कांग्रेस (Congress), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI(M), बहुजन समाज पार्टी (BSP), नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP) और आम आदमी पार्टी (AAP) शामिल है।
इस बार **लोकसभा में विपक्ष की कुल संख्या 234 है। इनमें से 99 सांसद कांग्रेस के है। वहीं सदन में सत्ता पक्ष की संख्या 293 है, जिनमें से भाजपा के 240 सांसद** शामिल हैं।

संसदीय चुनावों के साथ चार राज्यों ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव **भी हुए हैं।**

मत्स्य प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन

असम में स्थित 2000 मेगावाट की सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना (एसएलपी) में व्यापक मत्स्य प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

यह समझौता मत्स्य विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार और एनएचपीसी लिमिटेड के बीच औपचारिक रूप से संपन्न हुआ।

मत्स्य प्रबंधन योजना का उद्देश्य गोल्डन महसीर, स्नो ट्राउट और इंडियन मेजर और माइनर कार्प जैसी प्रजातियों के मछली के बीज पालन के लिए हैचरी विकसित करके नदी पारिस्थितिकी को बढ़ाना है।

यह परियोजना **नदी पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित रखने के लिए** एक सहयोगात्मक प्रयास का प्रतीक है, जो सुबनसिरी नदी के निरंतर पारिस्थितिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करती है।

सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना के बारे में

यह **अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर सुबनसिरी नदी पर निर्माणाधीन बांध** है, जिसकी क्षमता 2000 मेगावाट (8x250 मेगावाट) है।

पूर्ण होने पर यह भारत का सबसे बड़ा जलविद्युत संयंत्र होगा और यह एक रन ऑफ़ रिवर परियोजना है।

इस परियोजना का विकास **राज्य सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एनएचपीसी)** द्वारा किया जा रहा है।

सुबनसिरी नदी के बारे में प्रमुख तथ्य:

यह **एक ट्रांस-हिमालयी नदी है, और ब्रह्मपुत्र नदी की दाहिनी तट पर स्थित सहायक नदी** है। यह नदी **असम, अरुणाचल प्रदेश और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र** से होकर बहती है।

यह नदी **असम के लखीमपुर जिले में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती** है। यह **ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी** है।

उच्च स्थलाकृतिक विविधता इस नदी को जलविद्युत के लिए एक महत्वपूर्ण संभावित क्षेत्र बनाती है।

एआईएम – आईसीडीके वाटर चैलेंज 4.0

हाल ही में, **अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग (एआईएम) ने भारत में नवाचार और स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दो महत्वपूर्ण पहलों को लॉन्च करने की घोषणा** की है: **'एआईएम – आईसीडीके वाटर चैलेंज 4.0' और 'इनोवेशन फॉर यू' पुस्तिका का पांचवां संस्करण।**

एआईएम-आईसीडीके वाटर चैलेंज 4.0 नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) द्वारा शुरू की गई एक पहल है , जिसका उद्देश्य नवीन समाधानों के माध्यम से जल संबंधी महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करना है।

यह चैलेंज **भारत स्थित रॉयल डेनिश दूतावास में इनोवेशन सेंटर डेनमार्क (ICDK)** के साथ एक सहयोगात्मक प्रयास है।

डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना

हाल ही में, केंद्र सरकार ने डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना (DHIS) को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। **1 जनवरी, 2023 को शुरू की गई यह योजना अब 30 जून, 2025 तक प्रभावी** रहेगी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने मरीजों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के लिए डीएचआईएस शुरू किया है। इसका लक्ष्य मरीजों की **स्वास्थ्य जानकारी को डिजिटल बनाना और उन्हें आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य खाते (ABHA ID) से जोड़ना** है।

यह पहल **सार्वजनिक और निजी अस्पतालों के साथ-साथ डिजिटल समाधान कंपनियों (DSCs)** पर भी लागू होती है जो डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाते हैं।

यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) द्वारा डिजिटल स्वास्थ्य लेनदेन को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को डिजिटल स्वास्थ्य अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शुरू की गई थी।

यह विस्तार स्वास्थ्य सुविधाओं को उनके संचालन के लिए आवश्यक डिजिटल आवश्यकताओं को अपनाने में और अधिक प्रेरित करेगा।

अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम 2005 में संशोधन

वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंडे में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए, **77वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में कोविड-19 महामारी के बाद सदस्य देशों द्वारा दिए गए 300 प्रस्तावों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (आईएचआर 2005) में संशोधनों के पैकेज पर सहमति** व्यक्त की गई।

इस संशोधनों का उद्देश्य **महामारी जैसी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए तैयार रहने और उनसे निपटने की देशों की क्षमता में सुधार करना** है।

इनमें स्वास्थ्य आ**पात स्थितियों के दौरान उपयुक्त स्वास्थ्य उत्पादों तक समान पहुँच की सुविधा प्रदान करने का प्रावधान शामिल** होने के, साथ ही आईएचआर के तहत आवश्यक मुख्य क्षमताओं के निर्माण, सुदृढ़ीकरण और रखरखाव में **विकासशील देशों की सहायता करने के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना** शामिल है।

1 जून, 2024 को आईएचआर (2005) के संशोधन का प्रस्ताव 77वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में सर्वसम्मति से अपना लिया गया।

चिनाब रेल पुल पर रेलवे का सफल ट्रायल रन

भारतीय रेलवे ने हाल ही में **दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब रेल ब्रिज** पर पहला ट्रायल रन किया, जो **रामबन जिले के संगलदान को रियासी से जोड़ता** है।

प्रमुख बिंदु

उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (यूएसबीआरएल) परियोजना पर 46 किलोमीटर लंबे मार्ग के साथ नवनिर्मित विद्युतीकृत लाइन खंड (रियासी-सांगलदान) पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (MEMU) ट्रेन का ट्रायल रन किया गया।

यह ट्रायल रन कश्मीर में रियासी-बारामुल्ला मार्ग पर रेल परिचालन शुरू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यह **डुग्गा और बक्कल स्टेशनों के बीच चेनाब नदी पर बने प्रतिष्ठित पुल** पर पहली पूर्ण रेल क्रॉसिंग है, जो **विश्व में सबसे ऊंचा मेहराबदार रेलवे पुल** है।

जम्मू और कश्मीर में चेनाब नदी से **359 मीटर ऊपर बना 1,315 मीटर लंबा** यह चेनाब रेल पुल, एफिल टॉवर से 35 मीटर ऊंचा है।

चिनाब नदी के बारे में मुख्य तथ्य

यह **भारत और पाकिस्तान के मध्य प्रवाहित** होने वाली एक प्रमुख नदी है। यह **सिंधु नदी की एक सहायक नदी** है।

यह नदी **हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के ऊपरी हिमालय में तांडी नामक स्थान पर दो धाराओं, चंद्रा और भागा के संगम** से बनती है। ऊपरी भाग में इसे **चंद्रभागा** के नाम से भी जाना जाता है।

यह जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से होकर पश्चिम की ओर बहती है, जो शिवालिक पर्वतमाला (दक्षिण) और लघु हिमालय (उत्तर) की खड़ी चट्टानों के बीच स्थित है।

त्रिम्मु के पास **झेलम नदी से मिलने के बाद चिनाब नदी सिंधु नदी की सहायक नदी सतलुज में मिल जाती** है।

श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा

श्रीनगर विश्व शिल्प परिषद (डब्ल्यूसीसी) द्वारा 'विश्व शिल्प शहर' के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है।

जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर अन्य भारतीय शहर हैं जिन्हें पहले विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता दी जा चुकी है।

विश्व शिल्प परिषद एक गैर-सरकारी संगठन है जो कारीगरों को सशक्त बनाने और वैश्विक स्तर पर शिल्प विरासत की रक्षा करने के लिए काम करता है।

4,000 से अधिक वर्षों के लिखित इतिहास वाले शहर को मिली नई पहचान ने एक ऐसे स्थान को सुर्खियों में ला दिया है, जिसने विभिन्न कला क्षेत्रों, विशेष रूप से **शॉल, कालीन, पेपर माचे** आदि में उत्कृष्ट कृतियों का निर्माण किया है।

2021 में श्रीनगर को शिल्प और लोक कला के तहत यूनेस्को क्रिएटिव सिटी का खिताब भी मिला।

राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्द्धन योजना

आपराधिक मामलों में बेहतर सजा दर हासिल करने के लिए **देश भर में अधिक वैज्ञानिक जांच करने के प्रयास में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में, राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्द्धन योजना (National Forensic Infrastructure Enhancement Scheme : NFIES) को मंजूरी** दे दी है।

2024-25 से 2028-29 की अवधि के लिए 2,254.43 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य देश भर में **राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU)** के परिसरों की स्थापना करने के अलावा NFSU, दिल्ली के मौजूदा बुनियादी ढांचे को बढ़ाते हुए अधिक **केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं** स्थापित करना है।

आवश्यकता

एक जुलाई से लागू होने वाले नए आपराधिक कानूनों के लागू होने से, जिसमें 7 साल या उससे अधिक की सज़ा वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक जांच अनिवार्य है, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के कार्यभार में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।

इसके अलावा, **देश में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (FSL) में प्रशिक्षित फोरेंसिक जनशक्ति की काफी कमी** है।

योजना के लाभ

यह योजना एक कुशल आपराधिक न्याय प्रक्रिया के लिए साक्ष्य की समय पर और वैज्ञानिक जांच में उच्च गुणवत्ता वाले, प्रशिक्षित फोरेंसिक पेशेवरों के महत्व को रेखांकित करती है।

राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के अतिरिक्त ऑफ-कैंपस और नई केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना से प्रशिक्षित फोरेंसिक जनशक्ति की कमी दूर होगी।

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

वैश्विक एयरलाइन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत

भारत **वर्ष 2025 में 42 वर्षों के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (IATA) की वार्षिक आम बैठक (AGM) की मेजबानी** करेगा।

1958 और 1983 के बाद यह तीसरी बार होगा जब IATA AGM की मेजबानी भारत द्वारा की जायेगी। इस **बैठक का आयोजन दिल्ली में** किया जाएगा।

लगभग सभी वैश्विक एयरलाइनों, विमान निर्माताओं और अन्य विमानन क्षेत्र के हितधारकों के प्रमुख और विभिन्न अन्य शीर्ष अधिकारी वैश्विक विमानन क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वर्ष में एक बार IATA की वार्षिक आम बैठक में एकत्रित होते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के बारे में:

IATA विश्व की एयरलाइनों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ है, जिसकी स्थापना **1945 में हवाना, क्यूबा** में 57 संस्थापक सदस्यों के साथ हुई थी।

लगभग 330 एयरलाइन्स, जो वैश्विक हवाई यातायात का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा हैं, IATA की सदस्य हैं।

मुख्यालय: मॉन्ट्रियल, कनाडा।

भारत ने कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता संभाली

हाल ही में, भारत ने **2024-26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता** संभाली है। भारत 2003 में इसकी स्थापना के बाद पहली बार क्षेत्रीय समूह कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है।

क्या है कोलंबो प्रोसेस

कोलंबो प्रक्रिया दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के प्रवासी श्रमिकों के लिए एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है, जो एशिया में विदेशी रोजगार और संविदात्मक श्रम के प्रबंधन पर परामर्श के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती है।

यह विदेशों में रोजगार के संबंध में सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

सदस्यता :

इसमें एशिया के **12 सदस्य देश (प्रवासी श्रमिकों के मूल देश)** शामिल हैं।

सदस्य : **अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, कंबोडिया, भारत, इंडोनेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम**।

भारत 2003 में इसकी स्थापना के बाद से कोलंबो प्रक्रिया का सदस्य रहा है ।

सचिवालय:

अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM) कोलंबो प्रक्रिया को तकनीकी और प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है।

> अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम) **संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का एक हिस्सा है, जो 1951 से सभी के लाभ के लिए मानवीय और व्यवस्थित प्रवासन को बढ़ावा देने वाला अग्रणी अंतर-सरकारी संगठन** है। **इसके 175 सदस्य देश हैं और 171 देशों में इसकी उपस्थिति** है।

बायोफार्मास्युटिकल एलायंस

हाल ही में, **भारत, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और यूरोपीय संघ (ईयू)** ने बायोफार्मास्युटिकल क्षेत्र में एक लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए संयुक्त प्रयास करने हेतु बायोफार्मास्युटिकल गठबंधन को शुरू किया है।

बायोफार्मास्युटिकल एलायंस का उद्घाटन हाल ही में **सैन डिएगो, कैलिफोर्निया में बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 के दौरान** किया गया, जो दुनिया की सबसे बड़ी बायोफार्मास्युटिकल प्रदर्शनी है।

गठबंधन की आवश्यकता

इस गठबंधन को **कोविड-19 महामारी के दौरान दवा आपूर्ति में हुई कमी** को देखते हुए शुरू किया गया है।

एलायंस में शामिल देशों ने एक **विश्वसनीय और टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखला के महत्व** पर जोर दिया और संबंधित देशों की जैव नीतियों, विनियमों और अनुसंधान एवं विकास सहायता उपायों को समन्वित करने पर सहमति व्यक्त की।

दवा निर्माण में आवश्यक कच्चे माल और अवयवों का उत्पादन कुछ ही देशों तक सीमित है और एक विस्तृत दवा आपूर्ति श्रृंखला बनाने हेतु देशों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है।

बाल पोषण रिपोर्ट 2024

यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार, **विश्व भर में 5 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक चार बच्चों में से एक गंभीर खाद्य गरीबी** का सामना कर रहा है तथा जीवन के लिए खतरा बने कुपोषण का शिकार है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

5 वर्ष से कम आयु के लगभग **27% या 181 मिलियन बच्चे प्रतिदिन यूनिसेफ द्वारा मान्यता प्राप्त आठ खाद्य समूहों में से दो से अधिक नहीं खाते** हैं, जिसे एजेंसी गंभीर खाद्य गरीबी के रूप में वर्गीकृत करती है।

जब बच्चे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का सेवन नहीं कर रहे होते हैं, तो उनमें कुपोषण का सबसे गंभीर रूप, वेस्टिंग का अनुभव होने की अधिक संभावना होती है।

गंभीर खाद्य गरीबी में रहने वाले **181 मिलियन युवा बच्चों में से दो तिहाई से अधिक दक्षिण एशिया और उप-सहारा अफ्रीका में रहते** हैं, जिनमें से 20 देशों में गंभीर खाद्य गरीबी में रहने वाले 65% बच्चे रहते हैं।

यूनिसेफ ने रिपोर्ट में कहा कि **पश्चिम और मध्य अफ्रीका में छोटे बच्चों में गंभीर खाद्य गरीबी 2012 में 42% से घटकर 2022 में 32% हो गई** है।

रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि गरीब और गैर-गरीब दोनों तरह के परिवारों के बच्चे गंभीर खाद्य गरीबी का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, **गंभीर खाद्य गरीबी में रहने वाले लगभग आधे (97 मिलियन) बच्चे मध्यम और उच्च आय वाले परिवारों में** रहते हैं।

अभ्यास रेड फ्लैग 2024

भारतीय वायु सेना (IAF) की एक टुकड़ी ने **04 जून से 14 जून 2024 तक संयुक्त राज्य वायु सेना के एइलसन एयर फोर्स बेस, अलास्का में आयोजित अभ्यास रेड फ्लैग 2024** में भाग लिया।

यह एक उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास है, जिसे **अमेरिकी वायु सेना द्वारा वर्ष में चार बार आयोजित** किया जाता है। इस अभ्यास में **भारतीय वायु सेना के साथ-साथ रिपब्लिक ऑफ़ सिंगापुर एयर फ़ोर्स (आरएसएएफ), यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयर फ़ोर्स (आरएएफ), रॉयल नीदरलैंड एयर फ़ोर्स (आरएनएलएएफ), जर्मन लूफ़्टवाफ़े और यूएस एयर फ़ोर्स (यूएसएएफ)** ने भाग लिया।

इस वर्ष के अगस्त माह में भारतीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति-2024 की मेजबानी करने हेतु उत्साहित है, जो भारत का पहला भारतीय बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है।

अभ्यास तरंग शक्ति-2024

अगस्त माह में भारतीय वायु सेना वायु अभ्यास, तरंग शक्ति-2024 की मेजबानी करेगी। यह **भारतीय वायु सेना द्वारा आयोजित पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास** है। यह अभ्यास **दो चरणों में आयोजित** किया जाएगा।

पहला चरण अगस्त के पहले दो सप्ताह में दक्षिण भारत में आयोजित किया जाएगा, तथा दूसरा चरण अगस्त के अंत से सितम्बर के मध्य तक पश्चिमी क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा।

भाग लेने वाले देश: **ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका।**

ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024

हाल ही में, **विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024** के अनुसार भारत दो स्थान गिर कर **146 देशों में से 129 वें स्थान पर आ गया है। पिछले वर्ष, यह 127 वें स्थान** पर था।

आइसलैंड (93.5%) लगातार 15वें वर्ष दुनिया का सबसे लैंगिक समानता वाला देश बना हुआ है। इसके बाद **फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और स्वीडन का स्थान** हैं।

अपने दक्षिण एशियाई पड़ोसियों में, **भारत का स्थान बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान के बाद** है, लेकिन पाकिस्तान से आगे है, जो तीन पायदान खिसक कर 145वें स्थान पर आ गया है। **वैश्विक स्तर पर, सूडान 146 देशों के सूचकांक में सबसे निचले स्थान पर** है।

इस रिपोर्ट को 2006 में पहली बार जारी किया गया। यह चार अलग-अलग उप-सूचकांकों का संयोजन है - आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक उपलब्धि, स्वास्थ्य और अस्तित्व तथा राजनीतिक सशक्तिकरण। सूचकांक 0 और 1 के बीच होता है, जिसमें 1 पूर्ण समानता को दर्शाता है।

ह्यूमन अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमियासिस

एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में, **चाड 2024 में ह्यूमन अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमियासिस (HAT) नामक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (Neglected Tropical Disease : NTD) के गैम्बिएन्स रूप को समाप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश और विश्व स्तर पर 51वां देश** बन गया है।

इसे **स्लीपिंग सिकनेस (निद्रा रोग)** के नाम से भी जाना जाता है। यह **प्रोटोजोआ परजीवी के कारण** होता है जो **संक्रमित त्सेत्से मक्खियों (tsetse flies) द्वारा फैलता** है।

त्सेत्से मक्खियाँ **उप-सहारा अफ्रीका में स्थानिक** हैं। ग्रामीण आबादी जो कृषि, मछली पकड़ने, पशुपालन या शिकार पर निर्भर है, वे सबसे अधिक इसके संपर्क में हैं।

आज तक, WHO ने सात देशों में HAT के गैम्बिएन्स रूप के उन्मूलन को मान्य किया है: **टोगो (2020), बेनिन (2021), आइवरी कोस्ट (2021), युगांडा (2022), इक्वेटोरियल गिनी (2022), घाना (2023) और चाड (2024)**।

एनटीडी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई जारी है, जिसका **लक्ष्य 2030 तक इनमें से कम से कम 100 बीमारियों को खत्म करना** है।

ऊर्जा संक्रमण सूचकांक

विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक (Energy Transition Index) में 120 देशों में से भारत को 63वां स्थान दिया गया है।

इस सूचकांक में यूरोपीय देशों का दबदबा रहा, जिसमें **स्वीडन सूचकांक में शीर्ष स्थान** पर रहा, उसके बाद **डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और फ्रांस ने क्रमशः स्थान प्राप्त** किया। **चीन 20वें स्थान** पर रहा।

विश्व आर्थिक मंच ने स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना में भारत द्वारा की गई प्रगति की भी सराहना की, जहां **नवीकरणीय ऊर्जा और बायोमास इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता का 42% हिस्सा है, जिससे यह विश्व स्तर पर चौथा सबसे बड़ा नवीकरणीय बाजार** बन गया है।

लगभग **10 बिलियन डॉलर के वार्षिक निवेश** के साथ, भारत **इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने और हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा** दे रहा है।

भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन **1.7 टन CO2 है, जो वैश्विक औसत 4.4 टन CO2 प्रति व्यक्ति से पहले ही 60% कम** है।

डेलोस पुरातात्विक स्थल के एजियन सागर में डूबने का संकट

हाल ही में, वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि **ग्रीस के साइक्लेड्स द्वीपसमूह में स्थित यूनेस्को विश्व विरासत स्थल डेलोस ग्लोबल वार्मिंग के कारण एजियन सागर** में डूब सकता है।

ग्रीक द्वीप डेलोस पर स्थित यह पुरातात्विक स्थल **बढ़ते समुद्री स्तर और भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के कारण** कुछ ही दशकों में लुप्त हो जाएगा। डे**लोस का पुरातात्विक स्थल 1990 से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल** है।

यह पुरातात्विक स्थल **हेलेनिस्टिक और रोमन काल के दौरान दैनिक जीवन की जानकारी** प्रदान करती हैं।

एजियन सागर

एजियन सागर **भूमध्य सागर की एक शाखा** है। यह पूर्वी भूमध्य सागरीय बेसिन में स्थित है, जिसके **पश्चिम में ग्रीक प्रायद्वीप और पूर्व में अनातोलिया (तुर्की के एशियाई भाग से मिलकर बना) स्थित** है।

एजियन सागर **डार्डेनेल्स जलडमरूमध्य, मरमारा सागर और बोस्फोरस के माध्यम से काला सागर से जुड़ा** हुआ है , जबकि **क्रेते द्वीप** को दक्षिण में इसकी सीमा के रूप में लिया जा सकता है।

पैंटानल आर्द्रभूमि में आग की घटनाएं

ब्राजील के **पैंटानल आर्द्रभूमि में आग की घटनाएं इस वर्ष अब तक लगभग दस गुना बढ़ गई** हैं, जो 2020 के बाद से उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं।

पैंटानल वेटलैंड के बारे में:

यह **विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि** है।

यह **ऊपरी पैराग्वे नदी बेसिन** में स्थित है। पैंटानल **बोलीविया और पैराग्वे के साथ ब्राजील की सीमा पर फैला** हुआ है। पैंटानल का **लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा ब्राज़ील** में है।

इसका विकास एण्डीज पर्वत के उत्थान से निर्मित संरचनात्मक बेसिन में हुआ है।

2000 में, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने पैंटानल के एक छोटे हिस्से को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया ।

यूरोप में डेंगू का प्रसार

यूरोपीय संघ की स्वास्थ्य एजेंसी के अनुसार **यूरोप की गर्म परिस्थितियां एडीज एल्बोपिक्टस मच्छर को पनपने में मदद कर रही हैं, जो डेंगू, चिकनगुनिया और जीका वायरस** फैलाता है।

प्रमुख बिंदु

जलवायु परिवर्तन से यूरोप में डेंगू के प्रसार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की आशंका है। **बढ़ते तापमान और अधिक वर्षा** से रोग फैलने के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां पैदा होती हैं, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां एडीज एल्बोपिक्टस मच्छर मौजूद होते हैं।

दक्षिणी यूरोप में , विशेष रूप से **स्पेन, इटली और फ्रांस में, एडीज एल्बोपिक्टस की उपस्थिति और बढ़ते तापमान एवं आर्द्रता के कारण डेंगू का खतरा बढ़ने की उम्मीद** है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार डेंगू के मामले 2**000 में वैश्विक स्तर पर लगभग 500,000 मामलों से बढ़कर 2019 में 5.2 मिलियन हो गए। अब तक, 2023 में कुल 4.5 मिलियन से अधिक मामले रिपोर्ट** किए गए हैं।

एडीज़ एल्बोपिक्टस मच्छर:

एडीज एल्बोपिक्टस मच्छर, जिसे आमतौर पर **एशियाई टाइगर मच्छर** के रूप में जाना जाता है , एक अत्यधिक आक्रामक प्रजाति है जो अपनी विशिष्ट **काली और सफेद धारीदार उपस्थिति** के लिए जानी जाती है।

मच्छरों के पनपने के लिए तापमान का उच्च होना आवश्यक है - **15 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच** - इसलिए **खतरा केवल गर्म महीनों तक ही सीमित** है।

यह मच्छर कई बीमारियों का ज्ञात वाहक है, जिनमें **डेंगू बुखार, चिकनगुनिया, जीका वायरस और पीत ज्वर** शामिल हैं।

एडीज एल्बोपिक्टस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए खुले स्थानों पर एकत्रित पानी को हटाना चाहिए जहां वे प्रजनन कर सकते हैं, कीट विकर्षकों का उपयोग करना चाहिए, तथा समुदाय-व्यापी मच्छर नियंत्रण कार्यक्रमों को लागू करना चाहिए।

अन्य प्रकार के मच्छरों के विपरीत, एडीज अपने पूरे जीवनकाल में अपने प्रजनन क्षेत्र से बहुत दूर नहीं जाता है - केवल लगभग **100 मीटर** - जिसका अर्थ है कि इसे अन्य क्षेत्रों में फैलने में अधिक समय लग सकता है।

भारत द्वारा 'आईएसओ परिषद बैठक' की मेज़बानी

भारत 24 से 28 जून, 2024 तक नई दिल्ली में चीनी क्षेत्र के वैश्विक कार्यक्रम 'आईएसओ परिषद बैठक' की मेज़बानी कर रहा है। इस कार्यक्रम में 30 से अधिक देशों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।

अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का **मुख्यालय लंदन में है, आईएसओ के 87 सदस्य देश** (2022 के आंकड़ों के आधार पर) निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व करते हैं:

विश्व चीनी उत्पादन का 87%

विश्व की 64% चीनी खपत

विश्व आयात का 34%

विश्व निर्यात का 92%

आईएसओ का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत के माध्यम से 1992 में किए गए अंतर्राष्ट्रीय चीनी समझौते (आईएसए) को लागू करना है।

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वर्ष शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। बल्कि विदेश मंत्री **एस जयशंकर 3-4 जुलाई को कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में** होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।

कजाकिस्तान द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन में पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भाग लेने की उम्मीद है।

पिछले वर्ष एससीओ की अध्यक्षता भारत ने की थी। **भारत जुलाई 2023 में एससीओ शिखर सम्मेलन की वर्चुअल मेज़बानी** कर चुका है।

भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान और ईरान से मिलकर बना एससीओ एक प्रभावशाली आर्थिक और सुरक्षा समूह माना जाता है।

शंघाई सहयोग संगठन के बारे में

एससीओ की स्थापना 2001 में शंघाई में रूस, चीन, किर्गिज़ गणराज्य, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान द्वारा की गई थी।

2017 में अस्ताना शिखर सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान इसके स्थायी सदस्य बन गए, जिसके बाद इसके सदस्यों की संख्या 8 हो गई।

2023 में भारत में हुए एससीओ शिखर सम्मेलन में ईरान को नए सदस्य के रूप में एससीओ में शामिल कर लिया गया है, जिसके बाद इसके सदस्यों की संख्या 9 हो गयी है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न : SCO के उद्देश्यों और लक्ष्यों की आलोचनात्मक जाँच करें। भारत के लिए इसका क्या महत्व है? (UPSC CSE 2021)

भारत-बंगलादेश संबंध

हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच हैदराबाद हाउस में हुई वार्ता के दौरान **भारत और बांग्लादेश ने 10 समझौतों पर हस्ताक्षर** किए।

लोकसभा चुनावों के बाद नई सरकार के गठन के बाद किसी विदेशी नेता की यह पहली द्विपक्षीय राजकीय यात्रा है।

भारत और बांग्लादेश ने एक **व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) पर वार्ता शुरू करने का संकल्प** लिया है; बांग्लादेशी नागरिकों के लिए **मेडिकल ई-वीजा** सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है; **तीस्ता नदी जल बंटवारे पर चर्चा के लिए एक तकनीकी टीम** भेजने पर सहमति व्यक्त की है तथा **रंगपुर में एक सहायक उच्चायोग (Assistant High Commission) खोलने** की घोषणा की।

बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है और भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। भारत एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत को बांग्लादेशी निर्यात लगभग 2 बिलियन डॉलर का हुआ।

प्रमुख बिंदु

मेडिकल ई-वीजा सुविधा उन बांग्लादेशी नागरिकों को राहत पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है जो भारतीय अस्पतालों में इलाज के लिए भारत आते हैं। **2023 में बांग्लादेश के लोगों को लगभग 16 लाख वीजा जारी किए गए और अनुमान है कि उनमें से लगभग 20-30 प्रतिशत वीजा इलाज के** उद्देश्य से जारी किए गए थे। मेडिकल ई-वीजा प्रक्रिया को सरल और तेज करेगा।

बांग्लादेश के अंदर तीस्ता नदी के संरक्षण और प्रबंधन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक भारतीय तकनीकी दल को भेजने का निर्णय लिया गया है।

उत्तर-पश्चिम बांग्लादेश के रंगपुर में एक सहायक उच्चायोग (एएचसी) स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। यह **राजशाही, खुलना, चटगाँव और सिलहट के अलावा पाँचवाँ एएचसी** होगा।

PT FACT

तीस्ता नदी **पहुनरी ग्लेशियर से निकलती है (ब्रह्मपुत्र के समान स्रोत से नहीं)। ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश पर्वत के निकट आंगसी ग्लेशियर से निकलती** है।

तीस्ता **ब्रह्मपुत्र की दाहिनी सहायक नदियों में से एक** है। बांग्लादेश से होकर बंगाल की खाड़ी में जाने से पहले **तीस्ता पश्चिम बंगाल और सिक्किम से होकर बहती** है।

रंगीत नदी सिक्किम से निकलती है जो **सिक्किम की सबसे बड़ी नदी है और तीस्ता नदी की सहायक नदी** भी है।

यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन

स्विट्ज़रलैंड में आयोजित यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 15-16 जून, 2024 को बर्गनस्टॉक रिज़ॉर्ट में हुआ। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन स्विस राष्ट्रपति वियोला अम्हेर्ड ने किया था और इसका उद्देश्य यूक्रेन में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के लिए एक ढांचा तैयार करना था। इस सम्मेलन में **92 देशों और 8 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग** लिया, हालांकि रूस की अनुपस्थिति उल्लेखनीय थी।

सम्मेलन के अंत में **84 देशों और छह संगठनों ने एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर** किए, जिसमें परमाणु सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और कैदियों एवं निर्वासितों के साथ व्यवहार जैसे मुद्दों को संबोधित करने के कदम शामिल थे।

इस दस्तावेज़ में यूक्रेन की परमाणु सुविधाओं पर संप्रभुता के महत्व पर जोर दिया गया और परमाणु खतरों के उपयोग की निंदा की गई। इसमें यूक्रेनी कृषि उत्पादों के सुरक्षित और स्वतंत्र वितरण और सभी युद्ध कैदियों और बंदी नागरिकों की रिहाई की भी अपील की गई।

सभी आमंत्रित देशों ने इस वक्तव्य का समर्थन नहीं किया; **दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब , मेक्सिको और भारत** जैसे देशों ने हस्ताक्षर करने से परहेज किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने उम्मीद जताई कि सम्मेलन एक व्यापक शांति प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त करेगा, हालांकि सम्मेलन में रूस के साथ प्रत्यक्ष बातचीत नहीं हुई

विदेश मंत्रालय के सचिव श्री पवन कपूर ने शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि, भारत ने सम्मेलन के अंत में जारी संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर नहीं किए।

भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि वह सभी पक्षों के साथ बातचीत और कूटनीति के माध्यम से यूक्रेन संघर्ष के स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में प्रयासरत रहेगा। भारत का मानना है कि केवल उन विकल्पों को स्वीकार करने से ही स्थायी शांति प्राप्त हो सकती है, जो दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य हों।

शिखर सम्मेलन से पूर्व रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि रूस युद्ध तभी समाप्त करेगा जब कीव अपनी नाटो महत्वाकांक्षाओं को छोड़ने और मास्को द्वारा दावा किए गए चार प्रांतों को सौंपने के लिए सहमत हो, लेकिन ऑस्ट्रिया ने तुरंत इन मांगों को आत्मसमर्पण के समान बताते हुए खारिज कर दिया।

पूर्वी तटीय रेल लिंक परियोजना

हाल ही में, चीन ने कहा कि **वह मलेशिया की 10 अरब डॉलर की पूर्वी तटीय रेल लिंक (ईसीआरएल) को लाओस और थाईलैंड में चीन समर्थित अन्य रेलवे परियोजनाओं से जोड़ने की योजना** का अध्ययन करने के लिए तैयार है, जिससे संभवतः **दक्षिण-पूर्व एशिया में बीजिंग की बेल्ट एंड रोड पहल का विस्तार** हो सकेगा।

ईसीएलआर **665 किलोमीटर लंबा रेलमार्ग है, जो 2026 के अंत तक प्रायद्वीपीय मलेशिया के पूर्वी और पश्चिमी तटों को जोड़ेगा**।

चीन 2009 से मलेशिया का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है, और विदेश मंत्रालय ने कहा कि 2023 में कुल व्यापार का मूल्य 98.9 बिलियन डॉलर था।

राजव्यवस्था एवं शासन

कैबिनेट समिति का गठन

हाल ही में, **प्रधानमंत्री मोदी ने नई गठबंधन सरकार के 71 मंत्रियों के साथ शपथ** ली। इनमें से **30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री** हैं।

कैबिनेट समितियां क्या हैं?

केंद्रीय मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण करने और मंत्रिस्तरीय विभागों के आवंटन के बाद, अगला महत्वपूर्ण कार्य कैबिनेट समितियों का गठन करना है।

प्रधानमंत्री कैबिनेट के चयनित सदस्यों के साथ इन समितियों का गठन करते हैं और इन समितियों को विशिष्ट कार्य सौंपते हैं।

प्रधानमंत्री समितियों की संख्या में बदलाव कर सकते हैं और उन्हें सौंपे गए कार्यों में संशोधन कर सकते हैं।

प्रत्येक समिति की सदस्य संख्या 3 से 8 तक होती है। आमतौर पर इन समितियों के सदस्य केवल कैबिनेट मंत्री ही होते हैं।

हालांकि, गैर-कैबिनेट मंत्रियों का समितियों में सदस्य या विशेष आमंत्रित सदस्य होना असामान्य नहीं है। **यदि प्रधानमंत्री स्वयं ऐसी किसी समिति के सदस्य हैं, तो वे उस समिति के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं।**

ये समितियां मुद्दों का समाधान करती हैं और मंत्रिमंडल के विचारार्थ प्रस्ताव तैयार करती हैं तथा उन्हें सौंपे गए मामलों पर निर्णय लेती हैं। मंत्रिमंडल को ऐसे निर्णयों की समीक्षा करने का अधिकार है।

वर्तमान में कुल 8 कैबिनेट समितियाँ हैं:

आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ।

राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ।

निवेश और विकास पर कैबिनेट समिति ।

केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति ।

संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति ।

रोजगार और कौशल विकास पर कैबिनेट समिति ।

आवास संबंधी कैबिनेट समिति ।

मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति।

कैबिनेट समितियों से संबंधित अन्य तथ्य-

कैबिनेट समितियों का भारतीय संविधान में उनका उल्लेख नहीं है।

इन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल पर बोझ कम करने के लिए तैयार किया गया है।

इनका गठन या पुनर्गठन तब किया जाता है जब **नई सरकार सत्ता में आती है या मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है।**

आवास संबंधी कैबिनेट समिति और संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति को छोड़कर सभी समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।

सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (CCS) के बारे में-

इसका **अध्यक्ष प्रधानमंत्री** होता है।

यह समिति राष्ट्रीय सुरक्षा निकायों में अधिकारियों की नियुक्तियों के संबंध में चर्चा और बहस करती है।

यह रक्षा नीति और व्यय तथा सामान्यतः भारत की सुरक्षा के सभी मामलों पर सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेता है ।

सदस्य : प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री , गृह मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री।

कार्य :

यह **राष्ट्रीय सुरक्षा निकायों में बहस, चर्चा और नियुक्तियों के लिए जिम्मेदार** है।

QuizHat

महत्वपूर्ण नियुक्तियों, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों, भारत के रक्षा व्यय के संबंध में प्रमुख निर्णय सीसीएस द्वारा लिए जाते हैं।

भारत की **रक्षा और सुरक्षा से संबंधित सभी मुद्दों से निपटता** है।

सीसीएस **भारत की कानून-व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित सभी मुद्दों से निपटता** है।

इसमें भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले विभिन्न कदमों पर चर्चा की जाती है।

यह विदेशी मामलों के नीतिगत मामलों से भी निपटता है जिनका आंतरिक या बाह्य सुरक्षा निहितार्थों पर असर हो सकता है, जिसमें सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर अन्य देशों के साथ समझौतों से संबंधित मामले भी शामिल हैं।

समिति उन राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करती है जो हमारे राष्ट्र की सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं।

यह परमाणु ऊर्जा से संबंधित मामलों पर भी विचार करती है।

आनुपातिक प्रतिनिधित्व

सत्तारूढ़ एनडीए ने 43.3% वोट शेयर के साथ 293 सीटें जीती हैं, जबकि विपक्षी दल इंडिया ने 41.6% वोट शेयर के साथ 234 सीटें हासिल की हैं। अन्य क्षेत्रीय दलों और निर्दलीयों को लगभग 15% वोट मिले, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें केवल 16 सीटें ही मिलीं।

आनुपातिक प्रतिनिधित्व (पीआर) प्रणाली सभी दलों का उनके वोट शेयर के आधार पर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है।

आनुपातिक प्रतिनिधित्व के प्रकार:

फर्स्ट पास्ट द पोस्ट: भारत में वर्तमान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट (एफपीटीपी) प्रणाली लागू है, जिसके तहत किसी निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार जीतता है। एफपीटीपी प्रणाली सरल है और कार्यपालिका को स्थायित्व प्रदान करती है , लेकिन इससे गैर-प्रतिनिधित्व वाली सरकारें बन सकती हैं।

पार्टी लिस्ट पीआर: सबसे अधिक प्रयुक्त पीआर प्रणाली 'पार्टी लिस्ट पीआर' है , जहां मतदाता पार्टी को वोट देते हैं (न कि व्यक्तिगत उम्मीदवार को) और फिर पार्टियों को उनके वोट शेयर के अनुपात में सीटें मिल जाती हैं।

मिश्रित सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व (Mixed Member Proportional Representation): मिश्रित सदस्य आनुपातिक मतदान प्रणाली या एमएमपी मतदान प्रणाली के तहत, मतदाता दो वोट डालते हैं - एक 'पार्टी वोट' जो संसद की समग्र संरचना को निर्धारित करता है और एक 'मतदाता वोट' जो उनके भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए स्थानीय सांसद का चुनाव करता है।

प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने **कटक से सात बार सांसद रहे भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त** किया गया है।

राष्ट्रपति, **संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त** करते हैं, ताकि वे अध्यक्ष के चुनाव तक अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें।

18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्य प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब के समक्ष शपथ लेंगे।

परंपरा के अनुसार, **सबसे अधिक कार्यकाल पूरा करने वाले सांसद को पहले दो दिनों के लिए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त** किया जाता है, जब सभी नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाती है।

18वीं लोकसभा में सबसे वरिष्ठ सांसद कोडिकुन्निल सुरेश (कांग्रेस) और वीरेंद्र कुमार (भाजपा) हैं, जो अपना आठवां कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। इसके बजाय, **7 बार के सांसद रहे भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त** किया गया है। वे 6 बार बीजू जनता दल के सांसद रहे और अब भाजपा के सांसद हैं।

18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा, जिसमें 25 जून तक नवनिर्वाचित सदस्य शपथ लेंगे। अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होगा।

विपक्ष के नेता

रायबरेली के सांसद राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। यह पद 10 वर्षों तक रिक्त रहा, क्योंकि किसी भी पार्टी के पास सदन की संख्या के दसवें हिस्से के बराबर संख्या नहीं थी।

2014 और 2019 के चुनावों के बाद 543 सदस्यीय सदन में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने क्रमशः 44 और 52 सीटें जीती थीं। पार्टी ने इस चुनाव में 2019 की तुलना में लगभग दोगुनी 99 सीटें जीती हैं।

विपक्ष के नेता की व्यावहारिक भूमिका और जिम्मेदारी क्या है?

विपक्ष का नेता, सीबीआई निदेशक, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों तथा लोकपाल जैसे प्रमुख पदों पर नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समितियों में विपक्ष का प्रतिनिधि होता है।

वरीयता क्रम में, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के साथ **सातवें स्थान** पर आते हैं।

लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन बन सकता है?

विपक्ष के नेता की स्थिति को आधिकारिक तौर पर संसद में विपक्ष के नेताओं के **वेतन और भत्ते अधिनियम, 1977 में वर्णित** किया गया है।

अधिनियम में विपक्ष के नेता को "राज्य सभा या लोक सभा का सदस्य, जैसा भी मामला हो, के रूप में वर्णित किया गया है, जो उस समय, सरकार के विपक्षी दल का उस सदन में नेता होता है, जिसके पास **सबसे अधिक संख्याबल (सदन की संख्या का 10%)** होता है और जिसे राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त होती है।"

सदन में विपक्ष के नेता की स्थिति

विपक्ष का नेता अध्यक्ष के बाईं ओर अगली पंक्ति में बैठता है, और उसे औपचारिक अवसरों पर कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे कि निर्वाचित अध्यक्ष को मंच तक ले जाना।

विपक्ष का नेता संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान भी अगली पंक्ति में सीट पाने का हकदार है।
विपक्ष के नेता का मुख्य कर्तव्य सदन में विपक्ष की आवाज़ बनना है। लोकसभा में विपक्ष के नेता को "एक **छाया प्रधानमंत्री** के रूप में माना जाता है, जिसके पास एक छाया मंत्रिमंडल होता है, जो सरकार के इस्तीफ़ा देने या सदन में हारने की स्थिति में प्रशासन संभालने के लिए तैयार रहता है।"

"सदन के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने में इसकी सक्रिय भूमिका सरकार की भूमिका जितनी ही महत्वपूर्ण है।"

विपक्ष के नेता की व्यावहारिक भूमिका और जिम्मेदारी क्या है?

विपक्ष का नेता, सीबीआई निदेशक, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों तथा लोकपाल जैसे प्रमुख पदों पर नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समितियों में विपक्ष का प्रतिनिधि होता है।

वरीयता क्रम में, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के साथ सातवें स्थान पर आते हैं।

लोकसभा अध्यक्ष

हाल ही में, **ओम बिरला को लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष के रूप में** चुना गया है। वे देश के दूसरे ऐसे नेता बन गए हैं जो लगातार पांच साल स्पीकर रहने के बाद दूसरी बार स्पीकर बने हैं।

अस्थायी या प्रोटेम अध्यक्ष द्वारा नए सदस्यों को शपथ दिलाने के बाद, अध्यक्ष को सदन का पीठासीन अधिकारी चुना जाता है।

> लगातार दो बार चुने जाने और कार्यकाल पूरा करने वाले बलराम जाखड़ एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। हालांकि जीएम बालयोगी, पीए संगमा जैसे दिग्गज नेता भी दो बार लोकसभा अध्यक्ष बने थे लेकिन पूरे 5-5 साल के कार्यकाल पूरे नहीं किए।

संवैधानिक प्रावधान

संसदीय लोकतंत्र में अध्यक्ष की अहम भूमिका होती है। भारतीय संविधान में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों का प्रावधान है, जिन्हें **अनुच्छेद 93 के अनुसार सदन के शुरू होने के बाद "जितनी जल्दी हो सके" चुना जाना चाहिए।**

अध्यक्ष का चुनाव सदन में साधारण बहुमत से होता है। सदन के भंग होने के साथ ही उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, जब तक कि अध्यक्ष इस्तीफा न दे दे या उससे पहले पद से हटा न दिया जाए। **संविधान के अनुच्छेद 94 के अनुसार अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव 14 दिनों के नोटिस पर लाया जा सकता है।** इसके अलावा, सदन के किसी भी अन्य सदस्य की तरह अध्यक्ष को भी अयोग्यता का सामना करना पड़ सकता है।

अध्यक्ष बनने के लिए कोई विशेष योग्यता नहीं है, जिसका मतलब है कि कोई भी सदस्य विचार किए जाने का हकदार है। हालाँकि, अध्यक्ष का पद सदन के अन्य सदस्यों से अलग होता है।

अध्यक्ष का वेतन भारत की संचित निधि से लिया जाता है, जबकि अन्य सांसदों का वेतन सदन द्वारा पारित कानून के आधार पर लिया जाता है।

लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां

सदन का संचालन: अध्यक्ष सदन के बारे में बेहतर जानकारी रखते हुए यह तय करते हैं कि सदन का संचालन कैसे किया जाए। सरकारी कामकाज का संचालन अध्यक्ष द्वारा सदन के नेता के परामर्श से तय किया जाता है। सदस्यों को प्रश्न पूछने या किसी मामले पर चर्चा करने के लिए अध्यक्ष की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है।

सदन के कामकाज के लिए नियम और प्रक्रियाएँ होती हैं, लेकिन इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अध्यक्ष के पास व्यापक शक्तियाँ होती हैं।

प्रश्न और रिकॉर्ड : अध्यक्ष किसी सदस्य द्वारा उठाए गए प्रश्न की स्वीकार्यता तय करता है, साथ ही सदन की कार्यवाही को कैसे प्रकाशित किया जाए, यह भी तय करता है। अध्यक्ष के पास उन टिप्पणियों को पूरी तरह या आंशिक रूप से हटाने का अधिकार है, जिन्हें वह असंसदीय मानती हैं। सत्तारूढ़ दल के खिलाफ आलोचनात्मक टिप्पणियों को प्रकाशित नहीं किया जा सकता है, अगर अध्यक्ष उन्हें हटाने का फैसला करता है।

ध्वनि मत एवं मत विभाजन: जब सदन में सत्ता पक्ष की सीटें कम लगती हैं, तो अध्यक्ष विभाजन के अनुरोध को नजरअंदाज कर सकते हैं और ध्वनि मत से विधेयक को पारित करा सकते हैं।

अविश्वास प्रस्ताव: स्पीकर की निष्पक्षता विपक्ष पर सबसे ज़्यादा तब असर डालती है जब सरकार के खिलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। 2018 में जब वाईएसआरसीपी और टीडीपी ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया था, तब स्पीकर सुमित्रा महाजन ने प्रस्ताव को स्वीकार करने और वोटिंग के लिए रखने से पहले सदन को कई बार स्थगित किया था।

निर्णायक मत देना: हालांकि यह दुर्लभ है कि अध्यक्ष को अपना वोट देने की आवश्यकता होती है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण कार्य है। संविधान के अनुच्छेद 100 के अनुसार, जो सदनों में मतदान के बारे में बताता है, राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष, या इस तरह से कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति, "पहले तो वोट नहीं देगा, लेकिन वोटों की किसी भी बराबरी की स्थिति में उसे वोट देने का अधिकार होगा"। परम्परागत रूप से, अध्यक्ष सरकार के पक्ष में मतदान करता है।

सदस्यों की अयोग्यता : संविधान में 52वें (संशोधन) अधिनियम, 1985 के माध्यम से पेश की गई दसवीं अनुसूची या दलबदल विरोधी कानून, सदन के अध्यक्ष को किसी पार्टी से 'दलबदल' करने वाले विधायकों को अयोग्य घोषित करने की शक्ति देता है। 1992 में किहोटो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हु के ऐतिहासिक मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने अध्यक्ष में निहित शक्ति को बरकरार रखा और कहा कि केवल अध्यक्ष का अंतिम आदेश ही न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा।

लोकसभा उपाध्यक्ष

18वीं लोकसभा में विपक्ष की ताकत बढ़ने के साथ ही इसके सदस्य उपाध्यक्ष का पद पाने की उम्मीद कर रहे हैं।

17वीं लोकसभा (2019-24) के पूरे कार्यकाल में कोई उपाध्यक्ष नहीं रहा। जबकि भाजपा की सहयोगी पार्टी एआईएडीएमके के एम थम्बी दुरई 16वीं लोकसभा (2014-19) के उपाध्यक्ष थे। 1990 से 2014 तक लगातार उपाध्यक्ष का पद विपक्ष के पास रहा।

संविधान में उपाध्यक्ष को लेकर प्रावधान

अनुच्छेद 93 के अनुसार, लोक सभा यथाशीघ्र अपने दो सदस्यों को क्रमश: अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब कभी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए, तब सदन किसी अन्य सदस्य को, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगा।

अनुच्छेद 95(1) के अनुसार, यदि अध्यक्ष का पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करता है। सदन की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष के पास अध्यक्ष के समान सामान्य शक्तियाँ होती हैं।

अनुच्छेद 178 में राज्य विधानसभाओं के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के लिए समतुल्य प्रावधान है।

क्या संविधान के तहत उपाध्यक्ष का होना अनिवार्य है?

संविधान में नियुक्तियों के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। प्रावधान में यह अंतर ही सरकारों को उपाध्यक्ष की नियुक्ति में देरी करने या उसे टालने का अधिकार देता है।

हालांकि, संवैधानिक विशेषज्ञों ने बताया है कि अनुच्छेद 93 और अनुच्छेद 178 दोनों में "यथाशक्य शीघ्र" शब्द का प्रयोग किया गया है - जो दर्शाता है कि न केवल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अनिवार्य है, बल्कि इसे जल्द से जल्द कराया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष के चुनाव के नियम क्या हैं?

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का चुनाव लोक सभा के सदस्यों में से उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा किया जाता है।

सामान्यतः, लोक सभा और राज्य विधानसभाओं में नए सदन के प्रथम सत्र में अध्यक्ष का चुनाव करने की प्रथा रही है - आमतौर पर तीसरे दिन, जब पहले दो दिनों में शपथ-ग्रहण और प्रतिज्ञान हो चुका होता है।

उपाध्यक्ष का चुनाव आमतौर पर दूसरे सत्र में होता है, हालांकि नई लोकसभा या विधानसभा के पहले सत्र में इस चुनाव को कराने पर कोई रोक नहीं है। लेकिन उपाध्यक्ष का चुनाव आमतौर पर दूसरे सत्र से आगे नहीं टाला जाता, जब तक कि कुछ वास्तविक और अपरिहार्य बाधाएं न हों।

लोकसभा में उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 8 के तहत होता है। नियम 8 के अनुसार, चुनाव "अध्यक्ष द्वारा तय की गई तिथि पर होगा"। उपाध्यक्ष का चुनाव तब होता है जब उनके नाम का प्रस्ताव पारित हो जाता है। एक बार निर्वाचित होने के बाद, उपाध्यक्ष आमतौर पर सदन के भंग होने तक पद पर बने रहते हैं।

अनुच्छेद 94 (और राज्य विधानसभाओं के लिए अनुच्छेद 179) के तहत, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष "यदि लोक सभा का सदस्य नहीं रह जाता है तो वह अपना पद छोड़ देगा"। वे (एक दूसरे को) इस्तीफा भी दे सकते हैं, या "सदन के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित लोक सभा के प्रस्ताव द्वारा पद से हटाए जा सकते हैं"।

क्या कभी किसी उपाध्यक्ष को अनुपस्थित अध्यक्ष का स्थान लेना पड़ा है?

प्रथम अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही 1956 में निधन हो जाने के बाद, **उपाध्यक्ष एम.अनंतशयनम अयंगर ने 1956 से 1957 तक** लोकसभा के शेष कार्यकाल के लिए कार्यभार संभाला। बाद में अयंगर को दूसरी लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया।

पुनः, 2002 में 13वीं लोकसभा के अध्यक्ष, तेलुगू देशम पार्टी (टी.डी.पी.) के जी.एम.सी. बालयोगी के निधन के बाद, उ**पाध्यक्ष पी.एम. सईद दो महीने के लिए कार्यवाहक अध्यक्ष बने**, जब तक कि शिवसेना के मनोहर जोशी अध्यक्ष नहीं चुने गए।

केरल विधानसभा में राज्य का नाम बदलने के लिए संकल्प पारित

केरल विधानसभा ने 24 जून को सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया जिसमें केंद्र से संविधान में राज्य का नाम **केरल से बदलकर "केरलम" करने का आग्रह** किया गया है। पिछले एक साल में यह दूसरी बार है कि ऐसा संकल्प पारित किया गया है।

राज्य का नाम बदलने के लिए संकल्प

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा पेश किए गए संकल्प में कहा गया है कि "मलयालम में हमारे राज्य का नाम केरलम है... हालांकि, संविधान की पहली अनुसूची में हमारे राज्य का नाम केरल लिखा गया है।

यह विधानसभा सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से अनुरोध करती है कि वह **संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए तत्काल कदम उठाए।**"

केरल का इतिहास

केरल मलयाली केरलम के लिए अंग्रेजी शब्द है। इस शब्द का **सबसे पहला उल्लेख सम्राट अशोक के अभिलेख II में पाया जा सकता है, जो 257 ईसा पूर्व का** है। अभिलेख में सीमावर्ती शासकों जैसे चोडा [चोल], पांड्य, सतियपुत्र, केतलपुत्र [केरलपुत्र] का उल्लेख मिलता है।

केरलपुत्र, जिसका शाब्दिक अर्थ संस्कृत में "केरल का पुत्र" है, दक्षिण भारत के तीन मुख्य राज्यों में से एक चेरों के राजवंश को संदर्भित करता है।

केरल राज्य का गठन

स्वतंत्रता के बाद, 1 जुलाई, 1949 को दो मलयालम-भाषी रियासतों को मिलाकर त्रावणकोर-कोचीन राज्य बनाया गया।

राज्य पुनर्गठन आयोग की भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की सिफारिश के बाद आखिरकार केरल राज्य का निर्माण हुआ। **केरल राज्य 1 नवम्बर 1956 को अस्तित्व** में आया।

नवनिर्वाचित सांसदों द्वारा शपथ

18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून, 2024 से शुरू हुआ। सदन के विधायी कामकाज शुरू करने से पहले, नवनिर्वाचित सदस्यों को संसद सदस्य (एमपी) की शपथ लेनी होती है, जिसका संविधान में प्रावधान है।

राष्ट्रपति ने भर्तृहरि महताब को नए अध्यक्ष के चुनाव तक **संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत प्रोटेम स्पीकर के कर्तव्यों का दायित्व सौंपा है, जो संसद सदस्यों को शपथ दिलाएंगे।**

किसी सांसद का कार्यकाल कब शुरू होता है?

लोकसभा सांसद का पांच साल का कार्यकाल तब शुरू होता है जब भारत का चुनाव आयोग (ईसीआई) **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 73 के अनुसार** परिणाम घोषित करता है। उस दिन से, सांसद निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में कुछ अधिकारों के लिए पात्र होते हैं। उदाहरण के लिए, उन्हें ईसीआई अधिसूचना की तारीख से अपना वेतन और भत्ते मिलना शुरू हो जाते हैं।

उनके कार्यकाल की शुरुआत का अर्थ यह भी है कि यदि सांसद अपनी पार्टी की निष्ठा बदलते हैं, तो उनका राजनीतिक दल स्पीकर से दलबदल विरोधी कानून के तहत उन्हें संसद से अयोग्य घोषित करने के लिए कह सकता है।

यदि किसी सांसद का कार्यकाल शुरू हो गया है तो संसदीय शपथ क्यों महत्वपूर्ण है?

चुनाव जीतने और कार्यकाल शुरू करने से सांसद को स्वतः ही सदन की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति नहीं मिल जाती है। **लोकसभा में बहस करने और मतदान करने के लिए, एक सांसद को संविधान में निर्धारित शपथ या प्रतिज्ञान लेकर सदन में अपनी सीट लेनी होती है (अनुच्छेद 99)।**

संविधान में 500 रुपये का वित्तीय जुर्माना भी निर्दिष्ट किया गया है, यदि कोई व्यक्ति शपथ लिए बिना सदन की कार्यवाही में भाग लेता है या मतदान करता है (अनुच्छेद 104)।

हालाँकि, इस नियम का एक अपवाद है। कोई व्यक्ति संसद के लिए चुने बिना भी मंत्री बन सकता है। उनके पास लोकसभा या राज्यसभा में सीट सुरक्षित करने के लिए छह महीने का समय होता है । इस दौरान, वे सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते।

संसदीय शपथ क्या है?

संविधान की तीसरी अनुसूची में संसदीय शपथ का उल्लेख है। इसमें लिखा है, "मैं, अमुक, जो राज्य सभा या लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा, मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा।"

सांसद शपथ कैसे लेते हैं?

शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने के लिए बुलाए जाने से पहले, सांसदों को अपना निर्वाचन प्रमाण पत्र लोकसभा कर्मचारियों को प्रस्तुत करना होता है। सत्यापन के बाद, सांसद अंग्रेजी या संविधान में निर्दिष्ट **22 भाषाओं में से किसी में भी शपथ या प्रतिज्ञान** ले सकते हैं।

लगभग आधे सांसद हिंदी या अंग्रेजी में शपथ लेते हैं। पिछली दो लोकसभाओं में संस्कृत भी एक लोकप्रिय भाषा रही है जिसमें सांसदों ने शपथ ली है। 2019 में 44 सांसदों और 2014 में 39 सांसदों ने संस्कृत में शपथ ली थी।

लोकसभा चुनाव 2024 में महिला प्रतिनिधित्व

18वीं लोकसभा में 469 पुरुषों के साथ 74 महिलाएं चुनी गयी है। ये महिला सांसद सभी सांसदों का केवल 13.6 प्रतिशत हैं। न केवल यह हिस्सा बेहद विषम है, बल्कि यह 2019 के चुनाव (14.4 प्रतिशत) में चुनी गई महिलाओं के हिस्से से भी कम है।

भारत द्वारा ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक पारित किए जाने के बाद यह पहला संसदीय चुनाव था, जो लागू होने के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रयास करता है।

वास्तविक स्थिति

एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स (ADR) द्वारा संकलित डेटा के अनुसार, इस चुनाव में सभी **उम्मीदवारों में से केवल 9.6 प्रतिशत (और किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले 11 प्रतिशत उम्मीदवार) महिलाएँ** थीं। यह 2019 से बमुश्किल ही ज़्यादा है, जब उम्मीदवारों में महिलाओं की हिस्सेदारी नौ प्रतिशत थी।

अगर इतनी कम महिलाएं चुनाव लड़ पाती हैं, तो निर्वाचित लोगों में उनका प्रतिनिधित्व मामूली ही रहेगा। हालाँकि दुनिया के अधिकांश हिस्सों में संसदों में पुरुषों का वर्चस्व बना हुआ है, लेकिन भारत अपने अधिकांश समकक्षों से बहुत पीछे है।

उदाहरण के लिए, 2**023 में, दुनिया भर के 52 देशों में संसदीय चुनाव हुए - औसतन 27.6 प्रतिशत महिलाएं चुनी** गईं। वास्तव में, वैश्विक स्तर पर, वर्तमान में सभी सांसदों में महिलाओं का 26.9 प्रतिशत हिस्सा है।

18वीं लोकसभा के चुनाव से पहले, **भारत इस पैमाने पर 185 देशों में 143वें स्थान** पर था। महिलाओं के प्रतिनिधित्व में इस गिरावट के साथ, रैंकिंग में पांच या छह स्थान की और गिरावट आने की संभावना है।

मेक्सिको से एक उदाहरण

भारत में मतगणना के एक दिन पहले, दुनिया के एक अलग कोने में एक और ऐतिहासिक चुनाव परिणाम सामने आया। मेक्सिको में, जहाँ विभिन्न राजनीतिक पदों के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए आम चुनाव हुए, **क्लाउडिया शिनबाम शीर्ष राजनीतिक पद** पर बहुमत से चुनी गईं। **यह पहली बार है जब देश के राष्ट्रपति के रूप में एक महिला चुनी गई है।**

आगे की राह

स्थानीय स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के मामले में भारत ने सबसे आगे रहकर काम किया है। अब समय आ गया है कि हम राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद कमियों को दूर करने के लिए भी इसी तरह की प्रतिबद्धता दिखाएं।

इसके लिए शीर्ष स्तर से सुधार की आवश्यकता होगी, लेकिन प्रगति सुनिश्चित करने की अंतिम जिम्मेदारी हमारे राजनीतिक दलों के कंधों पर होगी।

QuizHat

अर्थव्यवस्था

प्रेस्टन वक्र

प्रेस्टन वक्र एक ग्राफिकल निरूपण है जो किसी देश में **जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय के बीच संबंध** को संदर्भित करता है।

इसे पहली बार **अमेरिकी समाजशास्त्री सैमुअल एच. प्रेस्टन** ने अपने 1975 के शोधपत्र "मृत्यु दर और आर्थिक विकास के स्तर के बीच बदलते संबंध" में प्रस्तावित किया था।

प्रेस्टन ने पाया कि अमीर देशों में रहने वाले लोगों का जीवन काल आम तौर पर गरीब देशों में रहने वाले लोगों की तुलना में लंबा होता है। ऐसा संभवतः इसलिए है क्योंकि अमीर देशों में लोगों को स्वास्थ्य सेवा तक बेहतर पहुँच है, वे बेहतर शिक्षित हैं, स्वच्छ परिवेश में रहते हैं, बेहतर पोषण का आनंद लेते हैं आदि।

जब कोई गरीब देश विकास करना शुरू करता है , तो उसकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती है और जीवन प्रत्याशा में भी उल्लेखनीय वृद्धि होती है, क्योंकि लोग जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त कैलोरी से अधिक उपभोग करने में सक्षम हो जाते हैं, तथा बेहतर स्वास्थ्य सेवा का आनंद ले पाते हैं, आदि।

भारतीयों की औसत प्रति व्यक्ति आय 1947 में लगभग ₹9,000 प्रति वर्ष से बढ़कर 2011 में लगभग ₹55,000 प्रति वर्ष हो गई है। इसी अवधि के दौरान, **भारतीयों की औसत जीवन प्रत्याशा मात्र 32 वर्ष से बढ़कर 66 वर्ष से अधिक** हो गई।

हालाँकि, प्र**ति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा के बीच सकारात्मक संबंध एक निश्चित बिंदु के बाद ख़त्म होने लगता है**।

दूसरे शब्दों में, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से उसकी जनसंख्या की जीवन प्रत्याशा में एक सीमा से अधिक वृद्धि नहीं होती, क्योंकि मानव जीवन काल को अनिश्चित काल तक नहीं बढ़ाया जा सकता।

नई गरीबी रेखा की आवश्यकता

हाल ही में, **प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बिबेक देबरॉय ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)** द्वारा आयोजित डेटा उपयोगकर्ता सम्मेलन में **एक नई गरीबी रेखा की आवश्यकता पर बल** दिया।

देबरॉय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत अभी भी **एक दशक पुरानी तेंदुलकर समिति द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा पर निर्भर** है।

उन्होंने कहा कि **रंगराजन समिति ने एक अलग गरीबी रेखा का प्रस्ताव रखा** था, लेकिन इसे कभी आधिकारिक रूप से अपनाया नहीं गया।

इसके अलावा, उन्होंने बताया कि **बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MDPI) गरीबी रेखा नहीं** है।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) के बारे में:

यह भारत सरकार, विशेष रूप से प्रधान मंत्री को आर्थिक और संबंधित अन्य मुद्दों पर सलाह देने के लिए **2017 में गठित एक स्वतंत्र निकाय** है ।

ईएसी-पीएम के विचारार्थ विषयों में प्रधानमंत्री द्वारा संदर्भित किसी भी मुद्दे, चाहे वह आर्थिक हो या अन्य , का विश्लेषण करना और उस पर उन्हें सलाह देना शामिल है।

ईएसी प्रधानमंत्री के लिए **देश और विदेश में आर्थिक विकास पर एक मासिक रिपोर्ट** भी तैयार करता है।

यह नियमित आधार पर **आर्थिक प्रवृत्तियों पर नजर** रखता है और प्रधानमंत्री के ध्यान में देश और विदेश में महत्वपूर्ण घटनाक्रम लाता है तथा उपयुक्त नीतिगत प्रतिक्रियाएं सुझाता है।

ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स' रिपोर्ट

'ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स' रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है और यह वैश्विक आर्थिक स्थिति, विकास दर, और भविष्य की आर्थिक संभावनाओं का व्यापक विश्लेषण प्रदान करती है।

रिपोर्ट में वैश्विक और क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों का मूल्यांकन, विकास दर के पूर्वानुमान, और विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण शामिल होता है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

2024-25 में, लगभग 60 प्रतिशत अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि 2010 के औसत से कम रहने वाली है, जिसमें **वैश्विक आबादी का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा** शामिल है।

मजबूत घरेलू मांग, निवेश में वृद्धि और मजबूत सेवा गतिविधि से उत्साहित **भारतीय अर्थव्यवस्था के 2024 से 2026 तक प्रति वित्त वर्ष औसतन 6.7% की वृद्धि होने का अनुमान** है, जिससे दक्षिण एशिया दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र बन जाएगा।

विश्व बैंक ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। पूर्वानुमान के अनुसार, भारत **वित्त वर्ष 2024, वित्त वर्ष 2025 और वित्त वर्ष 2026 में क्रमशः 6.6%, 6.7% और 6.8% की वृद्धि दर्ज करने के लिए तैयार** है।

तुलनात्मक रूप से, वैश्विक विकास दर **2024 में 2.6% पर स्थिर रहने का अनुमान है, जो 2025 और 2026 में क्रमशः औसतन 2.7% तक बढ़ जाएगी**।

वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स के एक समूह में भारत शामिल

हाल ही में, **वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (FATF) ने भारत को चार अन्य जी-20 देशों के साथ एक चुनिंदा समूह में शामिल** किया है। यह समूह FATF के नए नियमों और मानकों को लागू करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता और दक्षता के आधार पर चुना गया है।

जी-20 के नेताओं ने अपने संयुक्त वक्तव्य में आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में FATF की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और इसके संसाधनों को बढ़ाने के लिए समर्थन का आश्वासन दिया।

भारत ने FATF के मानकों को अपनाने और लागू करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, खासकर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ।

इस समूह में शामिल होने से भारत की स्थिति और भी मजबूत होगी, और यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण

हाल ही में एनएसएसओ ने अगस्त **2022 से जुलाई 2023 तक पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण पूरा किया है। अगस्त 2022 से जुलाई 2023 के बीच किया गया यह सर्वेक्षण 2011-12 के बाद पहला सर्वेक्षण** है। **यह सर्वेक्षण आमतौर पर हर पांच साल में आयोजित किया जाता है।**

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के तहत आने वाला राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) 1950 में अपनी स्थापना के बाद से नियमित रूप से पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण (Household Consumption Expenditure surveys : HCES) कर रहा है।

यह सर्वेक्षण पारिवारिक मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (Monthly Per Capita Consumption Expenditure : MPCE) और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों तथा विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समूहों में इसके वितरण का अनुमान बताता है।

एंजेल टैक्स

हाल ही में, **भारतीय उद्योग जगत ने स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग में भारी गिरावट को ध्यान में रखते हुए एंजेल टैक्स हटाने की मांग** की है।

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने आ**यकर अधिनियम की धारा 56(2) (viib) को हटाने का सुझाव** दिया, जिसे बोलचाल की भाषा में 'एंजेल टैक्स' के रूप में जाना जाता है।

आयकर अधिनियम की धारा 56(2)(viib) में संशोधन

वित्त अधिनियम, 2023 ने आयकर अधिनियम की धारा 56(2)(viib) में संशोधन किया था।

इस संशोधन के अनुसार, जब कोई गैर-सूचीबद्ध कंपनी, जैसे कि स्टार्ट-अप, किसी घरेलू निवेशक से शेयर जारी करने के लिए इक्विटी निवेश प्राप्त करती है, जो ऐसे शेयरों के अंकित मूल्य से अधिक है, तो इसे स्टार्ट-अप के लिए आय के रूप में गिना जाएगा और प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के लिए 'अन्य स्रोतों से आय' शीर्षक के अंतर्गत आयकर के अधीन होगा।

हालाँकि, नवीनतम संशोधन के साथ, सरकार ने विदेशी निवेशकों को भी इस दायरे में शामिल करने का प्रस्ताव किया है, जिसका अर्थ है कि जब कोई स्टार्ट-अप किसी विदेशी निवेशक से धन जुटाता है, तो उसे भी अब आय के रूप में गिना जाएगा और कर योग्य होगा।

उद्योग जगत की ओर से विरोध और वित्त पोषण में गिरावट की खबरों के बाद वित्त मंत्रालय ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस सहित 21 देशों के निवेशकों को गैर-सूचीबद्ध भारतीय स्टार्ट-अप में अनिवासी निवेश के लिए एंजल टैक्स से छूट दे दी।

लेकिन इस सूची में सिंगापुर, नीदरलैंड और मॉरीशस जैसे देशों से निवेश को शामिल नहीं किया गया है - जो परंपरागत रूप से स्टार्ट-अप के लिए धन जुटाने के लिए प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र रहे हैं।

QuizHat

क्या है एंजेल टैक्स

यह टैक्स तब लगाया जाता है, जब **कोई गैर-सूचीबद्ध कंपनी किसी निवेशक को उसके उचित बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर शेयर जारी करती** है। पहले, यह केवल घरेलू निवेशक (resident investor) द्वारा किए गए निवेश पर लगाया जाता था। हालाँकि **वित्त अधिनियम 2023 में 1 अप्रैल, 2024 से गैर-निवासी निवेशकों पर भी एंजेल टैक्स लागू करने का प्रस्ताव** है।

एंजेल टैक्स **पहली बार 2012 में लागू किया गया** था, ताकि किसी निजी स्वामित्व वाली कंपनी के शेयरों को उस कंपनी के शेयरों के उचित बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर खरीदकर बेहिसाब धन के सृजन और उपयोग को रोका जा सके।

उद्योग जगत का तर्क

उद्योग जगत ने तर्क दिया है कि सरकार द्वारा मूल्यांकन और वास्तविक प्रदर्शन के बीच अंतर को मनी लॉन्ड्रिंग का संकेत बताना गलत है, साथ ही कहा कि निवेशक भविष्य की संभावनाओं के आधार पर स्टार्टअप को फंड देते हैं।

इसने कहा कि गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के निर्गम मूल्य और उसके उचित बाजार मूल्य (FMV) के बीच अंतर पर लगाए गए करों ने फंडिंग को नुकसान पहुंचाया है।

QuizHat

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

पैरेंग्योडोन्टियम एल्बम

हाल ही में, समुद्र में **प्लास्टिक पॉलीइथिलीन (पीई) को तोड़ने के लिए पैरेंग्योडोन्टियम एल्बम नामक एक समुद्री कवक की खोज** की गई है।

पैरेंग्योडोन्टियम एल्बम के बारे में:

यह एक समुद्री कवक है जो प्लास्टिक पॉलीइथिलीन (पीई) को विघटित कर सकता है, जो समुद्र में सबसे आम प्लास्टिक है।

यह कवक समुद्र में **प्लास्टिक के कूड़े पर पतली परतों में अन्य समुद्री सूक्ष्मजीवों के साथ रहता** है।

पी. एल्बम केवल उस प्लास्टिक को विघटित कर सकता है जो **UV विकिरण के संपर्क में** आया हो, अर्थात यह सतह के पास तैर रहे प्लास्टिक को विघटित कर देता है।

कवक को ऊर्जा स्रोत के रूप में पीई का उपयोग करने के लिए यूवी-प्रकाश की आवश्यकता होती है। इस खोज का मतलब है कि, समुद्र में, यह कवक केवल सतह के पास तैर रहे प्लास्टिक को ही नष्ट करता है।

मनुष्य प्रतिवर्ष **400 अरब किलोग्राम से अधिक प्लास्टिक का उत्पादन** करता है, जिसमें से अधिकांश समुद्र में चला जाता है।

बायोल्यूमिनसेंट मशरूम

हाल ही में, कासरगोड के जंगलों में शोधकर्ताओं ने **बायोल्यूमिनसेंट मशरूम की एक दुर्लभ प्रजाति** की खोज की है, जो रात में हरा प्रकाश उत्सर्जित करती है।

यह कवक, जिसे वैज्ञानिक रूप से **फिलोबोलेटस मैनिपुलरिस** के नाम से जाना जाता है, **जैव रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करने में सक्षम** हैं। वैज्ञानिकों ने इस मशरूम को "खाने के लिए उपयुक्त नहीं" माना है।

फिलोबोलेटस मैनिपुलरिस क्या है?

फिलोबोलेटस मैनिपुलरिस बायोल्यूमिनसेंट मशरूम की एक आकर्षक प्रजाति है। यह मशरूम अपनी **कोशिकाओं में रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण रात में चमकीले हरे रंग में चमकते** हैं।

"यह उष्णकटिबंधीय, आर्द्र वातावरण में पनपते हैं, आमतौर पर घने जंगलों में पाए जाते हैं जहाँ गिरे हुए पेड़ और पत्तियाँ जैसे सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं।

फिलोबोलेटस मैनिपुलरिस का चमकीला रंग **ल्यूसिफेरिन (एक रंगद्रव्य) और ल्यूसिफेरेज़ (एक एंजाइम)** से जुड़ी रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण है, जिसमें ऑक्सीजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

इस प्रतिक्रिया से प्रकाश उत्पन्न होता है, जो कि **अन्य जीव-प्रकाश उत्सर्जक जीवों जैसे कि जुगनू और कुछ समुद्री जीवों में भी पाया जाता** है।

'फेनोम इंडिया' परियोजना

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) ने अपनी अभूतपूर्व स्वास्थ्य निगरानी परियोजना, 'फेनोम इंडिया-सीएसआईआर हेल्थ कोहोर्ट नॉलेजबेस' (पीआई-चेक) के पहले चरण के सफल समापन की घोषणा की।

इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को यादगार बनाने के लिए, **सीएसआईआर ने 3 जून को गोवा के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (एनआईओ) में एक विशेष कार्यक्रम 'फेनोम इंडिया अनबॉक्सिंग 1.0' का आयोजन** किया।

मीडिया को संबोधित करते हुए सीएसआईआर-इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉ. शांतनु सेनगुप्ता ने कहा कि भारत में कार्डियो-मेटाबोलिक बीमारियों का के बहुत केस होने के बावजूद, भारतीय आबादी में इतनी अधिक घटनाओं के कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हैं।

उन्होंने कहा, "पश्चिम के जोखिम कारक भारत के जोखिम कारकों के समान नहीं हैं। एक कारक जो किसी विशेष व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, वह दूसरे व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे देश में एक ही तरह की अवधारणा को खत्म करना होगा।"

उन्होंने बताया कि पहली बार, **कार्डियो-मेटाबोलिक बीमारी,** विशेष रूप से मधुमेह, लिवर रोग और हृदय रोगों के लिए एक उन्नत पूर्वानुमान मॉडल विकसित करने के उद्देश्य से एक अखिल भारतीय अध्ययन किया जा रहा है। इस तरह का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि इन बीमारियों में आनुवंशिक और जीवनशैली दोनों कारक होते हैं जो जोखिम में योगदान करते हैं।

अध्ययन 10,000 नमूनों के अपने लक्ष्य को पार करने में सफल रहा है। सीएसआईआर ने नमूना संग्रह के लिए एक लागत प्रभावी मानक संचालन प्रक्रिया विकसित की है।

7 दिसंबर 2023 को लॉन्च की गई 'पीआई-चेक' परियोजना का उद्देश्य भारतीय आबादी में गैर-संचारी (कार्डियो-मेटाबोलिक) रोगों के जोखिम कारकों का आकलन करना है।

इस अनूठी पहल में पहले से ही लगभग 10,000 प्रतिभागियों को नामांकित किया गया है, जिन्होंने व्यापक स्वास्थ्य डेटा प्रदान करने के लिए स्वेच्छा से काम किया है।

भारतीय आबादी में कार्डियो मेटाबोलिक विकारों के बढ़ते जोखिम और घटनाओं के पीछे छिपे तंत्रों को समझना और इन प्रमुख बीमारियों के जोखिम स्तरीकरण, रोकथाम और प्रबंधन के लिए नई रणनीतियां विकसित करना महत्वपूर्ण है।

वर्तमान में, इनमें से अधिकांश जोखिम पूर्वानुमान एल्गोरिदम काकेशियन आबादी के महामारी विज्ञान डेटा पर आधारित हैं और इस बात के प्रमाण हैं कि वे जातीय विविधता, विभिन्न आनुवंशिक संरचना और आहार संबंधी आदतों सहित जीवनशैली पैटर्न के कारण भारतीय आबादी के लिए बहुत सटीक नहीं हो हैं। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि भारत-विशिष्ट जोखिम पूर्वानुमान एल्गोरिदम विकसित किए जाएं।

फेनोम इंडिया परियोजना पूर्वानुमानित, व्यक्तिगत, सहभागी और निवारक स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से सटीक चिकित्सा को आगे बढ़ाने के लिए सीएसआईआर की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। भारतीय आबादी के अनुरूप एक व्यापक फेनोम डेटाबेस तैयार करके, परियोजना का उद्देश्य पूरे देश में इसी तरह की पहल को उत्प्रेरित करना है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि जोखिम पूर्वानुमान एल्गोरिदम अधिक सटीक हों और भारत के विविध आनुवंशिक और जीवन शैली परिदृश्य का प्रतिनिधित्व करें।

दुर्लभ संवेदी तंत्रिका श्रवण हानि (rare sensorineural nerve hearing loss)

हाल ही में, **बॉलीवुड पार्श्व गायिका अलका याग्निक को दुर्लभ संवेदी श्रवण हानि से पीड़ित** होने का पता चला है।

सेंसोरिन्यूरल तंत्रिका श्रवण हानि क्या है?

सेंसोरिन्यूरल तंत्रिका श्रवण हानि एक प्रकार की श्रवण हानि है, जो **आंतरिक कान या कान से मस्तिष्क तक ध्वनि संचारित करने वाले तंत्रिका मार्गों को क्षति पहुंचने के कारण** होती है।

यद्यपि संवेदी श्रवण हानि (SNHL) **उम्र बढ़ने की एक प्राकृतिक प्रक्रिया** है, लेकिन **बहुत तेज संगीत सुनने से भी आंतरिक कान या श्रवण तंत्रिका को स्थायी नुकसान** हो सकता है।

आंतरिक कान के अंदर, **कोक्लीया (cochlea) नामक एक सर्पिल आकार के अंग में छोटे बाल होते हैं जिन्हें स्टीरियोसिलिया (stereocilia) कहा** जाता है।

ये बाल **ध्वनि तरंगों से कंपन को तंत्रिका संकेतों में बदलने के लिए जिम्मेदार** होते हैं, जिन्हें श्रवण तंत्रिका मस्तिष्क तक पहुंचाती है।

85 डेसिबल से अधिक तेज़ आवाज़ के संपर्क में आने से ये बाल क्षतिग्रस्त हो सकते हैं।

इसके बावजूद, सुनने की क्षमता में कमी तब तक स्पष्ट नहीं हो सकती जब तक कि **30-50% बाल क्षतिग्रस्त** न हो जाएं।

सेंसोरिन्यूरल तंत्रिका श्रवण हानि के कारण

जन्मजात कारक: गर्भावस्था या प्रसव के दौरान आनुवंशिक कारक या जटिलताएँ।

शोर के संपर्क में रहना: लंबे समय तक तेज शोर के संपर्क में रहने से आंतरिक कान की बाल कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, जिससे शोर के कारण सुनने की क्षमता कम हो सकती है।

उम्र बढ़ना: प्राकृतिक उम्र बढ़ने की प्रक्रिया आंतरिक कान में बाल कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त या नष्ट कर सकती है।

संक्रमण और रोग: मेनिन्जाइटिस, मम्पस, खसरा, तथा मेनियर रोग के कारण।

आघात: सिर पर चोट या आंतरिक कान में आघात।

ओटोटॉक्सिक दवाएं: कुछ एंटीबायोटिक्स और कीमोथेरेपी दवाएं।

सेंसोरिन्यूरल तंत्रिका श्रवण हानि के लक्षण

सुनने में कठिनाई।

दबी हुई या विकृत ध्वनियाँ।

कानों में बजने, भिनभिनाने या फुफकारने की आवाज आना।

ऊंची आवाजें सुनने में कठिनाई होना।

संतुलन संबंधी समस्याएं।

पुष्पक : आरएलवी लेक्स-03

हाल ही में, **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने तीसरा और अंतिम पुन: प्रयोज्य प्रक्षेपण यान (Reusable Launch Vehicle : RLV) का लैंडिंग एक्सपेरीमेंट (Landing Experiment : LEX)** सफलतापूर्वक किया।

आरएलवी लेक्स-03 नामक यह मिशन **कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एयरोनॉटिकल टेस्ट रेंज (एटीआर)** में संचालित किया गया।

आरएलवी लेक्स-03 मिशन ने अधिक चुनौतीपूर्ण रिलीज स्थितियों और गंभीर हवा की स्थिति में आरएलवी की स्वायत्त लैंडिंग क्षमता का प्रदर्शन किया।

पुष्पक नामक इस वाहन को **भारतीय वायु सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई** पर छोड़ा गया।

चंद्रयान-4 मिशन में डॉकिंग

हाल ही में, चंद्रयान-4 मिशन के बारे में नई जानकारी सामने आई है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा है कि, **इसरो यान को एक बार में प्रक्षेपित नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके बजाय, अंतरिक्ष यान के विभिन्न भागों को दो प्रक्षेपणों के माध्यम से कक्षा में भेजा जाएगा, तथा चंद्रमा पर जाने से पहले अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में ही जोड़ा जाएगा।**

ऐसा इसलिए करना होगा क्योंकि चंद्रयान -4 की वहन क्षमता इसरो के वर्तमान सबसे शक्तिशाली रॉकेट की क्षमता से भी अधिक होगी ।

हालाँकि, **यह संभवतः दुनिया में पहली बार होगा कि किसी अंतरिक्ष यान को अलग-अलग हिस्सों में लॉन्च किया जाएगा और फिर अंतरिक्ष में जोड़ा जाएगा।**

चंद्रमा से वापसी की यात्रा पर अंतरिक्ष यान मॉड्यूल का डॉकिंग एक काफी नियमित प्रक्रिया है। अंतरिक्ष यान का एक हिस्सा मुख्य अंतरिक्ष यान से अलग हो जाता है और चंद्रमा पर लैंडिंग करता है जबकि दूसरा हिस्सा चंद्रमा की कक्षा में रहता है। जब लैंडिंग वाला हिस्सा चंद्रमा की सतह से बाहर निकलता है, तो वह डॉक करता है और परिक्रमा करने वाले हिस्से से जुड़ जाता है, और फिर से एक इकाई बन जाता है।

इसरो को अब तक अंतरिक्ष में डॉकिंग ऑपरेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है, और **स्पैडेक्स (स्पेस डॉकिंग एक्सपेरीमेंट) मिशन** इस क्षमता को प्रदर्शित करने का पहला अवसर होगा।

चंद्रयान-4 के बारे में

इसरो (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) चंद्रयान-4 को **चांद की सतह से मिट्टी और चट्टान के नमूने वापस लाने के उद्देश्य से विकसित** कर रहा है। यह **मिशन 2028 के आसपास लॉन्च** किया जाएगा और इसमें भारत के उभरते हुए निजी क्षेत्र की भी भागीदारी होगी।

चंद्रयान-4 का प्रमुख लक्ष्य चंद्र सतह पर सुरक्षित लैंडिंग करना, नमूने इकट्ठा करना, उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लाना है। **मिशन में दो लॉन्च वाहनों का उपयोग होगा: LVM-3 और PSLV**।

चंद्रयान-4 का लैंडिंग स्थल शिव शक्ति प्वाइंट के पास होगा, जो चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर का लैंडिंग स्थल भी था।

इस मिशन में **चांद पर एक 350 किलो का रोवर भेजा** जाएगा जो एक बड़े क्षेत्र में अन्वेषण करेगा। नमूने इकट्ठा करने के बाद, ये नमूने एक विशेष मॉड्यूल में धरती पर लाए जाएंगे, जो चंद्र कक्षा में डॉक करेगा और फिर पृथ्वी पर वापसी करेगा।

चीन का चांग'ई-6 मिशन

चीन का चांग'ई-6 मिशन चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने लाने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया है। यह मिशन **चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव-ऐटकेन बेसिन में उतरा, जो एक विशाल और प्राचीन क्रेटर** है।

लैंडर 1 जून को चंद्रमा की सतह पर उतरा और रोबोटिक भुजा और ड्रिल का उपयोग करके दो दिन तक चंद्रमा के सबसे पुराने और सबसे बड़े गड्ढों में से एक - 2,500 किमी चौड़े दक्षिणी ध्रुव-ऐटकेन बेसिन से चट्टानों और मिट्टी को इकट्ठा करने में बिताया। यह नमूने 25 जून, 2024 को पृथ्वी पर पहुंचे हैं।

यह **चीन का छठा चन्द्र मिशन** है, जिसका नाम **चीनी पौराणिक कथाओं में चन्द्र देवी चांग'ई** के नाम पर रखा गया है।

चांग'ई-6 मिशन का मुख्य उद्देश्य

चांग'ई-6 मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के इस कम अन्वेषित क्षेत्र के बारे में वैज्ञानिक जानकारी जुटाना है।

सुदूर हिस्से से प्राप्त नमूने चंद्रमा, पृथ्वी और सौरमंडल के इतिहास और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकते हैं।

चांग'ई-6 ने कई वैज्ञानिक उपकरणों का भी उपयोग किया, जिनमें **फ्रांस द्वारा निर्मित एक राडॉन गैस डिटेक्टर और स्वीडन द्वारा विकसित एक नकारात्मक आयन डिटेक्टर** शामिल हैं। इसके अलावा, इसने एक छोटे रोवर को भी तैनात किया, जो लैंडर के चारों ओर की तस्वीरें लेने के लिए प्रयोग किया गया।

इस मिशन की सफलता ने चीन को चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने लाने वाला पहला देश बना दिया है, जो भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

कोई अन्य अंतरिक्ष यान जो चंद्रमा के नमूने लेकर पृथ्वी पर लाया है

जुलाई 1969 में, अमेरिका के अपोलो 11 मिशन ने 50 चट्टानों सहित 22 किलोग्राम चंद्र सतह सामग्री को पृथ्वी पर लाया था।

सितंबर 1970 में, **सोवियत लूना 16 मिशन - पहला रोबोटिक नमूना वापसी मिशन** - भी चंद्रमा से चट्टान लेकर पृथ्वी पर आया था। हाल के वर्षों में, चांग'ई-6 के पूर्ववर्ती चांग'ई-5 ने भी दिसंबर 2020 में 2 किलोग्राम चंद्र मिट्टी लेकर आया था।

भारत का चंद्रयान -4 मिशन, जो वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा विकसित किया जा रहा है, भी एक सैंपल रिटर्न मिशन होगा। चंद्रयान-3 पिछले साल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से लगभग 600 किलोमीटर दूर उतरा था।

चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव

चांग'ई-6 यान विश्व में पहली बार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट एक विशाल क्रेटर- ऐटकेन बेसिन में उतरा था। यह क्रेटर सौरमंडल में ज्ञात सबसे बड़े क्रेटरों में से एक है।

यान को यहाँ भेजना जोखिम से भरा था, क्योंकि एक बार चंद्रमा के सुदूरवर्ती भाग पर पहुंच जाने के बाद अंतरिक्ष यान से संपर्क करना बहुत कठिन होता है।

चीन के अन्य चंद्र मिशन

यह **चंद्रमा से नमूने एकत्र करने का चीन का दूसरा मिशन है, लेकिन चंद्रमा के सुदूर भाग से नमूने एकत्रित करने वाला पहला मिशन** है।

2020 में, चीन का चांग'ए-5 यान चंद्रमा के निकटवर्ती भाग पर **ओशनस प्रोसेलरम नामक क्षेत्र से 1.7 किलोग्राम सामग्री लेकर** लाया था।

और एक वर्ष पहले, चीन का चांग'ई-4 चंद्रमा के सुदूर भाग पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया था।

चंद्रमा की चट्टान का विश्लेषण

चंद्रमा से लाये जा रहे ये नमूने इसकी **भूवैज्ञानिक संरचना और विकास के बारे में** अमूल्य जानकारी प्रदान कर सकते हैं।चंद्रमा की चट्टान का विश्लेषण करने से **ग्रहों के निर्माण के बारे में मूलभूत प्रश्नों** का उत्तर मिल सकता है।

PT FACT

चीन के पास पहले से ही अपना स्वयं का **अंतरिक्ष स्टेशन है जिसे तियांगोंग या हेवनली पैलेस** के नाम से जाना जाता है।

बीजिंग की व्यापक रणनीति का लक्ष्य 2030 तक एक चीनी अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर चलते देखना है।

नासा का लक्ष्य **2026 में आर्टेमिस-3 मिशन को प्रक्षेपित** करना है, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों को पुनः चंद्रमा पर भेजना है।

निष्कर्ष

हालांकि, 20वीं सदी की यूएस-यूएसएसआर अंतरिक्ष दौड़ के विपरीत, जिसका उद्देश्य तकनीकी और बौद्धिक श्रेष्ठता हासिल करना था, आज के चंद्र मिशन चंद्रमा पर लंबे समय तक रहने और इसके संसाधनों का उपयोग करने के तरीकों की खोज करने के बारे में हैं। यह भी उम्मीद की जाती है कि निकट भविष्य में चंद्रमा का उपयोग अंतरिक्ष में और अन्य अलौकिक निकायों में यात्रा करने के लिए लॉन्च पैड के रूप में किया जा सकता है।

पर्यावरण एवं परिस्थितिकी

स्ट्रोमेटोलाइट्स शैवाल

हाल ही में, वैज्ञानिकों ने **सऊदी अरब में लाल सागर के उत्तर-पूर्वी शेल्फ पर स्थित शेबाराह द्वीप पर जीवित स्ट्रोमेटोलाइट्स (Stromatolites) शैवाल से बनी प्राचीन भूवैज्ञानिक संरचनाओं** का पता लगाया है।

अब तक यह माना जाता था कि **3.48 अरब वर्ष पुराने ये प्राचीन जीवन रूप केवल शार्क खाड़ी, ऑस्ट्रेलिया और एक्जुमा द्वीप, बहामास** में ही पनपते हैं।

यह इतनी महत्वपूर्ण खोज इसलिए है क्योंकि **स्ट्रोमेटोलाइट्स पृथ्वी पर जीवन के सबसे शुरुआती भूवैज्ञानिक संकेतक** हैं।

इसके अलावा, इन जैविक संरचनाओं ने **2 अरब साल पहले महान ऑक्सीजनेशन (Great Oxygenation) घटना में** महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे वायुमंडल में ऑक्सीजन पहुंची और पृथ्वी पर आवास की क्षमता में बदलाव आया।

स्ट्रोमेटोलाइट्स का अध्ययन करके, जो पृथ्वी पर ऑक्सीजन युक्त वातावरण होने से पहले पनपे थे, वैज्ञानिक अन्य ग्रहों पर जीवन के संभावित संकेतों को पहचानने के लिए मॉडल विकसित कर सकते हैं।

स्पॉट-बेलीड ईगल आउल

हाल ही में, **पेंच टाइगर रिजर्व (महाराष्ट्र) में स्पॉट-बेलीड ईगल आउल** की अल्पज्ञात आबादी के लिए एक अच्छा प्रजनन स्थल बन गया है।

इसे **फ़ॉरेस्ट ईगल आउल के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम बुबो निपलेंसिस (Bubo Nipalensis)** है।

यह **भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण-पूर्व एशिया में पाई जाने वाली उल्लू की एक शिकारी प्रजाति** है। यह आमतौर पर भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है।

ये घ**ने सदाबहार और नम पर्णपाती जंगलों में** पाए जाते हैं जो आमतौर पर **आर्द्र समशीतोष्ण और तटवर्ती जंगलों में** पाए जाते हैं।

यह पक्षी इंसानों के समान एक अजीब चीख निकालता है, जिसके कारण इसे भारत में **'घोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट' और 'डेविल बर्ड'** भी कहा जाता है।

संरक्षण की स्थिति:

आईयूसीएन स्थिति: **कम चिंताजनक (Least Concern)**

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: **अनुसूची IV**

पैरापैराट्रेचिना नीला (Paraparatrechina neela)

हाल ही में, अरुणाचल प्रदेश के सियांग घाटी में शोधकर्ताओं ने एक **नई नीली चींटी की खोज** की है।

नई चींटी का नाम **पैरापैराट्रेचिना नीला** रखा गया है - नीला शब्द इसके अनोखे नीले रंग से लिया गया है।

यह एक **चमकीली नीले रंग की चींटी है, जो मुश्किल से 2 मिमी लंबी** होती है।

यह उल्लेखनीय खोज **पैरापैराट्रेचिना जीनस में 121 वर्षों बाद हुई** है।

हूलॉक गिब्बन के लिए कैनोपी पुलों के निर्माण

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने भारत के एकमात्र वानर के लिए पूर्वी असम में उसके प्रमुख निवास स्थान को दो भागों में विभाजित करने वाले **रेलवे ट्रैक पर आवागमन हेतु कैनोपी पुलों के निर्माण का निर्णय** किया है।

अपनी आवाज के लिए प्रसिद्ध गिब्बन अपना ज्यादातर समय **ऊंचे पेड़ों की ऊपरी कैनोपी** पर बिताता है, **खासकर होलोंग (hollong) के पेड़ों पर।**

ट्रैक के किनारे जंगल के विखंडन ने गिब्बन के आवास को नष्ट कर दिया है, जिससे ट्रैक पार करते समय उसे खतरा हो रहा है।

अभयारण्य में कैनोपी ब्रिज बनाने का फैसला किया गया है, ताकि ट्रैक के पार गिब्बन की आवाजाही को सुविधाजनक बनाया जा सके।

होलोंगापार गिब्बन अभयारण्य

असम के जोरहाट जिले में 2,098.62 हेक्टेयर के होलोंगापार गिब्बन अभयारण्य (Hollongapar Gibbon Sanctuary) को 1.65 किलोमीटर लंबा ट्रैक विभाजित करता है - जिसे दोगुना और विद्युतीकृत किया जाना है।

इस अभयारण्य में हूलॉक गिब्बन की सबसे बड़ी संख्या निवास करती है, जो **पृथ्वी पर वानरों की 20 प्रजातियों में से एक** है।

होलांगापार गिब्बन अभयारण्य में लगभग 125 दुर्लभ हूलॉक गिब्बन रहते हैं, जो भारत में पाया जाने वाला एकमात्र वानर है।

आईयूसीएन रेड लिस्ट में संरक्षण की स्थिति:

पूर्वी हूलॉक गिब्बन: सुभेद्य (Vulnerable)

पश्चिमी हूलॉक गिब्बन: संकटग्रस्त (Endangered)

नाइट्रस ऑक्साइड (N2O) का उत्सर्जन

भारत नाइट्रस ऑक्साइड (N2O) का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जनकर्ता देश है, जो एक ग्रीनहाउस गैस है जो वातावरण को कार्बन डाइऑक्साइड से कहीं ज़्यादा गर्म करती है। नाइट्रस ऑक्साइड के **वैश्विक उत्सर्जन में भारत से आगे केवल चीन** है।

2020 में नाइट्रस ऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन का लगभग 11% भारत में हुआ था, जबकि नाइट्रस ऑक्साइड के **वैश्विक उत्सर्जन का लगभग 16% चीन द्वारा उत्सर्जित** किया जाता था।

अर्थ सिस्टम साइंस डेटा जर्नल में प्रकाशित N2O उत्सर्जन के वैश्विक आकलन के अनुसार, इन उत्सर्जनों का **प्रमुख स्रोत उर्वरकों का उपयोग** है।

नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन मुख्य रूप से **नाइट्रोजन उर्वरक के उपयोग और पशु गोबर से होता है; हालांकि इसका वर्तमान स्तर कार्बन डाइऑक्साइड से हजार गुना कम** है, लेकिन यह बहुत लंबे समय तक रहता है और तेजी से बढ़ रहा है।

अध्ययन में कहा गया है कि **2022 में वायुमंडलीय N2O की सांद्रता 336 भाग प्रति बिलियन तक पहुँच जाएगी, जो औद्योगिक युग से पहले देखे गए स्तरों से लगभग 25% अधिक** है। जबकि **कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता 2022 में 417 भाग प्रति मिलियन** थी।

हिंदू कुश हिमालय

इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (ICIMOD) की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2003 से 2024 तक बर्फ के बने रहने के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया, जिसमें यह पाया गया कि इस वर्ष **हिंदू कुश हिमालय में बर्फ़ सामान्य से काफी कम** है।

रिपोर्ट के अनुसार, **सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र घाटियों में बर्फबारी का स्तर औसत से कम रहा** है, जिसमें **2003-2023 के दौरान ऐतिहासिक अवलोकनों की तुलना में नवंबर 2023 और अप्रैल 2024 के बीच क्रमशः 23, 17 और 15 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई** है।

FIGURE 1: SNOW COVER PERSISTENCE ANOMALY DURING NOV 2023–APRIL 2024 COMPARED TO HISTORIC OBSERVATIONS DURING 2003–2023.

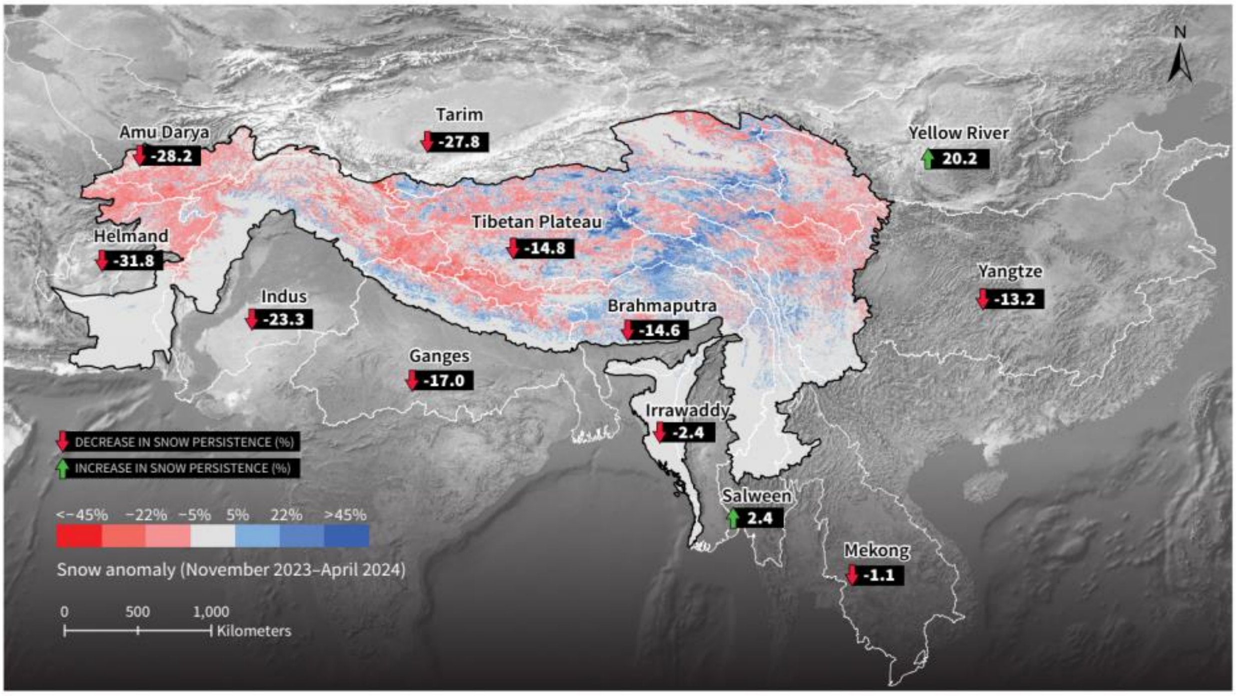

हिंदू कुश हिमालय के बारे में:

हिंदू कुश हिमालय 3,500 किलोमीटर तक फैला है, जो आठ देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान में विस्तृत है।

हिंदू कुश हिमालय **दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण 'वॉटर टावर'** है, जो **एशिया की दस सबसे बड़ी नदियों का स्रोत** है और आर्कटिक और अंटार्कटिका के बाहर सबसे ज़्यादा बर्फ़ और हिमपात का स्रोत भी है।

इसे तीसरा ध्रुव (उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बाद) भी कहा जाता है और इसका जलवायु पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

यह क्षेत्र दस बड़ी एशियाई नदी प्रणालियों का स्रोत है: **आमू दरिया, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इरावदी , सालवीन, मेकांग , यांग्त्से, पीली नदी और तारिम**।

डायटम की एक नई प्रजाति की खोज

हाल ही में, शोधकर्ताओं ने **पूर्वी और पश्चिमी घाट के इलाकों में स्वच्छ जल नदी में पाए जाने वाले गोम्फोनमॉइड डायटम की एक नई प्रजाति की खोज** की है। इसे **इंडिकोनेमा** नाम दिया गया है।

डायटम सूक्ष्म शैवाल हैं जो वैश्विक ऑक्सीजन का 25 प्रतिशत, यानी हमारे द्वारा ली जाने वाली ऑक्सीजन की लगभग हर चौथी सांस का उत्पादन करके हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

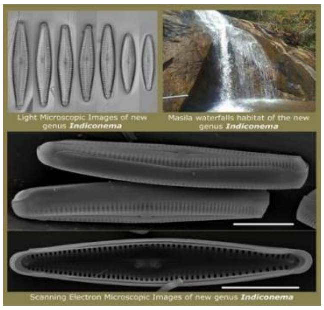

ये **जलीय खाद्य श्रृंखला के आधार के रूप में कार्य** करते हैं। किसी भी जल रसायन परिवर्तन के प्रति उनकी संवेदनशीलता के कारण, ये जलीय स्वास्थ्य के उत्कृष्ट संकेतक हैं।

डायटम भारत में सबसे पहले दर्ज किए गए सूक्ष्मजीव हैं। एक अनुमान के अनुसार **लगभग 6,500 डायटम टैक्सा हैं, जिनमें से 30 प्रतिशत भारत के लिए स्थानिक** (एक विशेष क्षेत्र तक सीमित) हैं, जो भारत की अनूठी जैव विविधता का प्रमाण हैं।

चीतल और सांभर का बर्दा वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरण

एशियाई शेरों के दीर्घकालिक संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, गुजरात में वन विभाग ने **गिर वन से चित्तीदार हिरण (चीतल) और सांभर को बर्दा वन्यजीव अभयारण्य (बीडब्ल्यूएस) में स्थानांतरित** करना शुरू कर दिया है।

वन अधिकारियों ने **बोमा तकनीक का उपयोग करके गिर से 23 चित्तीदार हिरणों को पकड़ा** और उन्हें विशेष वाहनों के जरिये **पोरबंदर के बर्दा वन्यजीव अभयारण्य** में पहुँचाया गया।

बोमा तकनीक में जानवरों को फनल जैसी बाड़ के माध्यम से पीछा करके एक बाड़े में फुसलाया जाता है।

इस पहल से गुजरात के बर्दा वन्यजीव अभयारण्य में चित्तीदार हिरणों की आबादी बढ़ेगी, जिससे अभयारण्य में एशियाई शेरों और अन्य बड़े शिकारियों के दीर्घकालिक संरक्षण में मदद मिलेगी।

192.31 वर्ग किलोमीटर में फैला बर्दा वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों के प्राकृतिक प्रसार के लिए एक महत्वपूर्ण निवास स्थान है क्योंकि बरदा की पारिस्थितिकीय परिस्थितियाँ और वनस्पति संरचना गिर के जंगलों के कई हिस्सों से मिलती-जुलती है, जो इसे एशियाई शेरों के लिए एक संभावित घर बनाती है। हालाँकि, बर्दा में शिकार का आधार बहुत कम है।

गिर क्षेत्र

गिर क्षेत्र मुख्य रूप से **गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिरनार वन्यजीव अभयारण्य, पनिया अभयारण्य, मितियाला अभयारण्य और गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली और भावनगर जिलों के राजस्व क्षेत्रों में** विभाजित है। जबकि बर्दा वन्यजीव अभयारण्य **गिर क्षेत्र से लगभग 100 किमी दूर है, जिसे ग्रेटर गिर क्षेत्र** भी कहा जाता है।

बर्दा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में:

यह **गुजरात राज्य के पोरबंदर में** स्थित है।

इस क्षेत्र में **मालधारी, भरवाड़, रबारी और गढ़वी जैसी जातियां** रहती हैं।

एशियाई शेरों के बारे में मुख्य तथ्य

यह **गुजरात के गिर क्षेत्र का स्थानिक शेर** है, एशियाई शेर (वैज्ञानिक नाम - पैंथेरा लियो पर्सिका) भारत की मूल निवासी पाँच पैंथराइन बिल्लियों में से एक है।

संरक्षण की स्थिति

आईयूसीएन रेड लिस्ट: संकटग्रस्त

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972: अनुसूची I

CITES : परिशिष्ट I

लाल सिर वाले गिद्धों के लिए संरक्षण और प्रजनन केंद्र

उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र का नाम **जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र** होगा।

इस केंद्र का उद्देश्य इस प्रजाति की आबादी में सुधार करना है, जिसे **2007 से अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लाल सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध** किया गया है।

यह गिद्ध **एशियाई किंग गिद्ध** के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये अपने पूरे जीवन में एक ही साथी बनाते हैं और साल में एक ही अंडा देते हैं। इसलिए इनका संरक्षण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

लाल सिर वाले गिद्ध अपने आवासों के नष्ट होने तथा घरेलू पशुओं में **डाइक्लोफेनाक (एक नॉनस्टेरॉइडल एंटी-इंफ्लेमेटरी दवा) के अत्यधिक प्रयोग** के कारण खतरे में हैं, जो गिद्धों के लिए जहरीली हो जाती है।

देश के अन्य गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्रों में लंबी चोंच वाले और सफेद पीठ वाले गिद्ध (long-billed and white-backed vultures) हैं।

डेनमार्क द्वारा पशुपालकों पर कर लगाने की योजना

डेनमार्क ने वर्ष 2030 से पशुपालकों पर उनकी गायों, भेड़ों और सूअरों द्वारा उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैसों के लिए कर लगाने की योजना की घोषणा की है। यह कदम देश की जलवायु परिवर्तन से निपटने की प्रतिबद्धता के तहत उठाया जा रहा है।

ऐसा करने वाला **डेनमार्क विश्व का पहला देश** होगा, इसका **लक्ष्य मीथेन उत्सर्जन को नियंत्रित करना** है, जो वैश्विक तापमान में वृद्धि में योगदान देने वाली सबसे शक्तिशाली गैसों में से एक है।

इसका उद्देश्य **2030 तक डेनमार्क के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 70 प्रतिशत तक कम करना** है।

2030 तक डेनमार्क के पशुपालकों पर कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर प्रति टन 300 क्रोनर ($43) का कर लगाया जाएगा। 2035 तक यह कर बढ़कर 750 क्रोनर (108 डॉलर) हो जाएगा।

महत्व

लैंडफिल, तेल एवं प्राकृतिक गैस प्रणालियों और पशुधन सहित स्रोतों से उत्सर्जित होने वाली मीथेन का स्तर 2020 के बाद से विशेष रूप से तेजी से बढ़ा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का कहना है कि मानव-जनित मीथेन उत्सर्जन में पशुधन की हिस्सेदारी लगभग 32 प्रतिशत है।

डेनमार्क सरकार का लक्ष्य है कि इस **कर के माध्यम से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम** किया जाए और पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं।

इस निर्णय का उद्देश्य किसानों को उनके पशुपालन तरीकों को सुधारने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि वे अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को अपनाएं।

इसके साथ ही, सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि इस **कर का असर किसानों की आय पर न्यूनतम हो** और उन्हें आवश्यक समर्थन प्रदान किया जाए।

डेनमार्क के इस कदम को पर्यावरणविदों और जलवायु परिवर्तन के विशेषज्ञों ने सराहा है, जबकि कुछ किसान संगठनों ने इसकी आलोचना भी की है। उनका मानना है कि इससे उनके व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। फिर भी, डेनमार्क सरकार का यह मानना है कि दीर्घकालिक लाभों के लिए यह कदम आवश्यक है।

गैंडों के सींगों में रेडियोधर्मी पदार्थ इंजेक्ट

दक्षिण अफ्रीका के शोधकर्ताओं ने गैंडों के शिकार को कम करने के उद्देश्य से एक शोध परियोजना के तहत **20 गैंडों के सींगों में रेडियोधर्मी पदार्थ इंजेक्ट** किया है, ताकि सीमा चौकियों पर उनका पता लगाना आसान हो सके।

राष्ट्रीय सीमाओं पर पहले से ही मौजूद विकिरण डिटेक्टर सींगों का पता लगा लेंगे और अधिकारियों को शिकारियों और तस्करों को गिरफ्तार करने में मदद करेंगे।

गैंडों की आबादी

गैंडे के सींगों की काले बाज़ार में बहुत मांग होती है, जहाँ वजन के हिसाब से उनकी कीमत सोने और कोकीन के बराबर होती है।

इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के आंकड़ों के अनुसार, 20वीं सदी की शुरुआत में **वैश्विक गैंडों की आबादी लगभग 5,00,000** थी। काले बाजार में गैंडे के सींगों की निरंतर मांग के कारण वर्तमान में इनकी आबादी लगभग 27,000 रह गयी है।

दक्षिण अफ्रीका में गैंडे

दक्षिण अफ्रीका विश्व के अधिकांश गैंडों का घर है, जो एशिया से होने वाली मांग के कारण गैंडों के अवैध शिकार का केंद्र भी है, जहां सींगों का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में उनके उपचारात्मक प्रभाव के कारण किया जाता है।

दक्षिण अफ्रीका में गैंडों की सबसे बड़ी आबादी है, जो अनुमानतः 16,000 है, जिससे यह एक हॉटस्पॉट बन गया है, जहां हर साल 500 से अधिक गैंडे मारे जाते हैं।

अन्य जानकारी

गैंडे के सींग का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक करता है।

भारतीय गैंडे को IUCN रेड लिस्ट में सुभेद्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया है; इसे पहले संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया था।

भारतीय घरेलू कौवे (Indian House Crows)

कौओं की आबादी को नियंत्रित करने के दशकों के प्रयासों के बाद, **केन्याई सरकार 31 दिसंबर तक 10 लाख घरेलू कौओं को जहर देकर मारने की योजना** बना रही है।

भारतीय घरेलू कौवे (कॉर्वस स्प्लेंडेंस) की बढ़ती संख्या ने केन्या सहित पूर्वी अफ्रीकी देशों में स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र और समुदायों को बुरी तरह प्रभावित किया है।

पक्षियों को स्टार्लिसाइड नामक एक कीटनाशक से जहर दिया जाएगा, जिसे केन्याई सरकार न्यूजीलैंड से आयात करेगी।

घरेलू कौवे से होने वाले नुकसान

घरेलू कौवे अक्सर स्थानीय पक्षियों पर हमला करते हैं, उन्हें मारते हैं और उनके अंडे खा जाते हैं। कौवों के इस आक्रामक व्यवहार ने कई स्थानीय पक्षियों को अपना प्राकृतिक आवास छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। **केन्या में, स्केली बैबलर, पाइड कौवे, सनबर्ड, वीवर बर्ड और वैक्सबिल जैसे पक्षियों को घरेलू कौवों ने विस्थापित** कर दिया है।

ऐसा केवल देशी पक्षियों के साथ ही नहीं होता; कौवे बछड़ों और बकरियों को सताने और मारने के लिए भी जाने जाते हैं तथा अनेक प्रकार के छोटे सरीसृपों, उभयचरों, स्तनधारियों और कीड़ों को खा जाते हैं।

कौवे आम और अमरूद जैसे फलों के पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, और गेहूं, मक्का, बाजरा, चावल और सूरजमुखी सहित फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे स्थानीय किसानों को नुकसान होता है।

केन्या में भारतीय कौवे

यह प्रजाति, जो भारत और उपमहाद्वीप के अलावा एशिया और मध्य पूर्व के अन्य भागों की मूल निवासी है, 1890 के दशक में पूर्वी अफ्रीका में देखी जाने लगी।

1947 तक कौवे केन्या तक पहुंच गये थे और वर्तमान में देश में इनकी अनुमानित जनसंख्या 750,000 से 1 मिलियन के बीच है।

यह पहली बार नहीं है कि केन्या में कौवों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। "1980 के दशक से लेकर 2005 तक देश में कौवों को जहर देकर कम स्तर पर नियंत्रण किया जा रहा था।"

गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में चीतें

मध्य प्रदेश में गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य भारत में चीतों के लिए दूसरा घर बनने जा रहा है। गांधी सागर में चीतों को शुरू में 64 वर्ग किलोमीटर के बाड़े में रखा जाएगा।

कुनो नेशनल पार्क की वहन क्षमता के आकलन से पता चला है कि इस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों की संख्या इसकी वहन क्षमता से अधिक हो गई है।

कुनो में चीतों की अधिकता के कारण चीतों के मुख्य शिकार चीतल में 25 प्रतिशत की कमी आई है।

अफ्रीका से आए जानवर और उनके बच्चे ही राष्ट्रीय उद्यान में एकमात्र शिकारी नहीं हैं। कुनो के तेंदुए शाकाहारी जानवरों के लिए चीतों से प्रतिस्पर्धा करते हैं।

खुले सवाना में, अफ्रीकी जानवर तेंदुओं से आगे निकल सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि तेंदुओं ने अपने घरेलू परिस्थितियों का भरपूर लाभ उठाया है।

वन विभाग का मानना है कि अतिरिक्त चीतों को गांधी सागर में स्थानांतरित करने से कुनो का पारिस्थितिक संतुलन बहाल हो सकता है।

PT FACT

गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य

गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी मध्य प्रदेश के मंदसौर (187.12 वर्ग किमी) और नीमच (181.5 वर्ग किमी) जिलों में 368.62 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है, जो राजस्थान की सीमा पर स्थित है।

यह समतल चट्टानी पठार के ऊपर स्थित है, जहाँ **चंबल नदी अभयारण्य को लगभग दो बराबर हिस्सों में विभाजित** करती है। **1960 में नदी पर बना गांधी सागर बांध अभयारण्य** के क्षेत्र में आता है, जो **क्षेत्रफल में 726 वर्ग किलोमीटर बड़ा है और देश में तीसरा सबसे बड़ा अभयारण्य** है।

एशियाई चीते

एशियाई चीते कभी भारत में बहुतायत में पाए जाते थे, लेकिन सदियों से उनके आवास नष्ट होने और बड़े पैमाने पर शिकार के कारण उनकी संख्या घटती चली गई। देश में आखिरी बार चीते को 1952 में देखा गया था।

स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट

हाल ही में जारी स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट के अनुसार, वायु प्रदूषण के कारण **2021 में दुनिया भर में 8.1 मिलियन मौतें हुईं, जिसमें चीन और भारत में क्रमशः 2.3 और 2.1 मिलियन मौतें** हुई है।

रिपोर्ट के अनुसार, वायु प्रदूषण को वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े हत्यारों में से एक माना जाता है, जो उच्च रक्तचाप के बाद दूसरे स्थान पर है। **कुल मौतों में से 700,000 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे** थे। रिपोर्ट में कहा गया है, "वायु प्रदूषण एक बहुत बड़ी और बढ़ती सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती है।"

भारत की स्थिति

वायु प्रदूषण के कारण 2.1 मिलियन मौतों के साथ भारत और 2.3 मिलियन मौतों के साथ चीन वैश्विक बोझ का 55% हिस्सा साझा करते हैं।

केवल पार्टिकुलेट मैटर ही नहीं, भारतीय ओज़ोन के उच्च स्तर के संपर्क में भी हैं। ओज़ोन के अल्पकालिक संपर्क से अस्थमा और अन्य श्वसन संबंधी रोग हो सकते हैं, जबकि दीर्घकालिक संपर्क से **क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज** हो सकता है, इस रोग में फेफड़े में सूजन रहती है जिससे वायु प्रवाह बाधित होता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में वैश्विक स्तर पर 489,000 मौतें ओज़ोन के संपर्क में आने के कारण हुईं - इन मौतों में से लगभग 50% या 237,000 मौतें भारत में हुईं।

भारत ने 2021 में पांच साल से कम उम्र के बच्चों में प्रदूषण से जुड़ी मौतों की सबसे अधिक संख्या भी दर्ज की, जिसमें **कम से कम 169,400 मौतें वायु प्रदूषण के कारण** हुईं।

डायरेक्ट सीडिंग ऑफ़ राइस

पंजाब सरकार चावल की सीधी बुआई (direct seeding of rice : DSR) या 'टार-वाटर' (tar-wattar) तकनीक को बढ़ावा दे रही है, **जिससे पानी का उपयोग 15% से 20% तक कम हो सकता है** (पारंपरिक पडलिंग विधि (puddling method) में एक किलो चावल उगाने के लिए 3,600 से 4,125 लीटर पानी की आवश्यकता होती है)।

इसके अलावा, डीएसआर को कम श्रम की आवश्यकता होती है और यह 7 से 10 दिन पहले पक जाती है, जिससे किसानों को धान की पराली का प्रबंधन करने के लिए अधिक समय मिल जाता है।

वर्तमान स्थिति

इन लाभों और सरकारी प्रोत्साहनों (इस वर्ष 1,500 रुपये प्रति एकड़) के बावजूद, इस तकनीक को पंजाब में अभी तक व्यापक रूप से अपनाया जाना बाकी है।

पिछले वर्ष, पंजाब में धान की खेती के तहत 79 लाख एकड़ में से केवल 1.73 लाख एकड़ में ही इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था।

यहां तक कि इस साल डीएसआर के तहत 7 लाख एकड़ लाने का सरकार का लक्ष्य भी पंजाब के कुल चावल के रकबे का 10% से भी कम है।

डीएसआर कैसे काम करता है?

परंपरागत रूप से, धान के किसान नर्सरी तैयार करते हैं जहाँ पहले बीज बोए जाते हैं। **25-35 दिनों के बाद, युवा पौधों को उखाड़ दिया जाता है और पानी भरे मुख्य खेत में फिर से रोप दिया जाता है।** हालाँकि यह विधि श्रम और पानी-गहन है, लेकिन यह उपज को अधिकतम करने और बेहतर फसल स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए जानी जाती है।

डीएसआर, जैसा कि नाम से पता चलता है, इसके लिए नर्सरी तैयार करने या रोपाई की आवश्यकता नहीं होती है। लगभग 20-30 दिन पहले धान के बीज सीधे बोए जाते हैं। बीज बोने की प्रक्रिया से पहले खेत की सिंचाई की जाती है और लेजर लेवलिंग की जाती है, जिसे सीड ड्रिल या लकी सीडर का उपयोग करके किया जाता है। बीज उपचार महत्वपूर्ण है, जिसमें बीजों को आठ घंटे तक फफूंदनाशक घोल में भिगोया जाता है, फिर बुवाई से पहले आधे दिन तक सुखाया जाता है।

सिंचाई का पहला दौर बुवाई के 21 दिन बाद किया जाता है, उसके बाद मिट्टी के प्रकार और मानसून की गुणवत्ता के आधार पर 7-10 दिन के अंतराल पर 14-17 बार और सिंचाई किए जाते हैं। अंतिम सिंचाई कटाई से 10 दिन पहले की जाती है। पारंपरिक विधि में कुल 25-27 सिंचाई की आवश्यकता होती है।

मिट्टी की बनावट

विशेषज्ञ इस बात पर ज़ोर देते हैं कि डीएसआर के सफल क्रियान्वयन के लिए मिट्टी की उपयुक्तता बहुत महत्वपूर्ण है। किसानों को हल्की बनावट वाली मिट्टी में डीएसआर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए - यह **भारी या मध्यम से भारी बनावट वाली मिट्टी के लिए ज़्यादा उपयुक्त** है। ऐसा मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि हल्की बनावट वाली मिट्टी पानी को अच्छी तरह से बरकरार नहीं रखती।

लौह तत्व का महत्व

मिट्टी में लौह तत्व की मात्रा भी डीएसआर की उपयुक्तता निर्धारित करती है। लोहे की गंभीर कमी वाली मिट्टी और खरपतवार की समस्या वाली मिट्टी में इस तकनीक का उपयोग करके खेती नहीं करनी चाहिए।

राइन नदी के जलस्तर में वृद्धि

हाल ही में **भारी बारिश के कारण जल स्तर बढ़ने से दक्षिणी जर्मनी में राइन नदी के कुछ हिस्सों को मालवाहक जहाजों के लिए बंद कर** दिया गया।

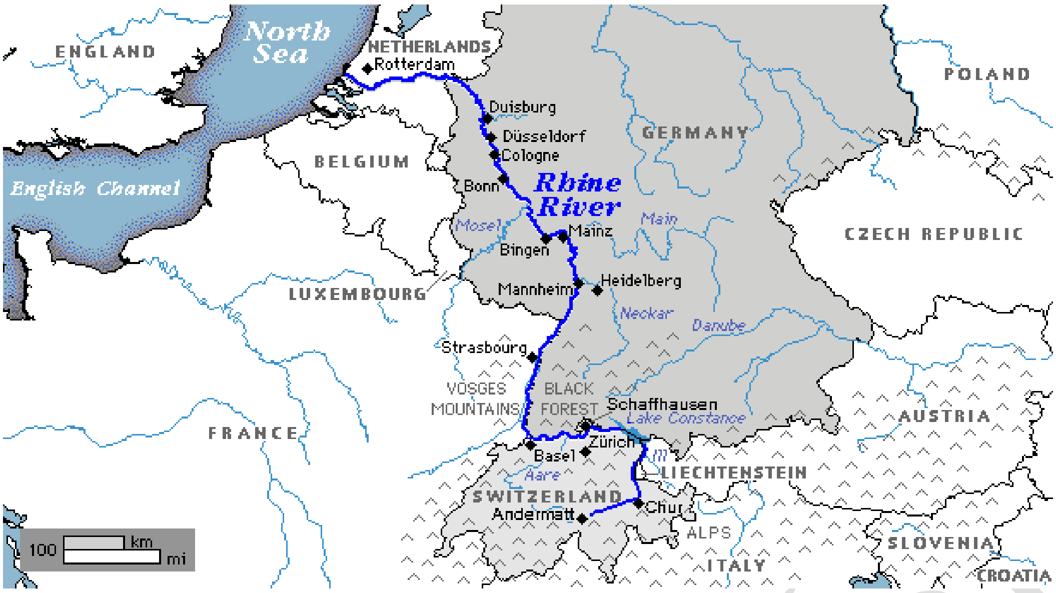

राइन नदी के बारे में:

यह नदी स्विट्ज़रलैंड में **आल्प्स पर्वतश्रेणी से निकलती** है और **छह देशों - स्विट्जरलैंड , लिकटेंस्टीन , ऑस्ट्रिया , जर्मनी , फ्रांस और नीदरलैंड से होकर बहती** है।

नीदरलैंड के **रॉटरडैम में उत्तरी सागर में गिरती** है। जर्मनी में इसे राइन, फ्रांस में राइन और नीदरलैंड में रिजन कहा जाता है।

राइन नदी **जर्मनी और फ्रांस के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती** है।

यह **यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक जलमार्ग** है, जो स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड के बीच व्यापार के प्रवाह को नियंत्रित करता है ।

राइन के किनारे स्थित प्रमुख शहरों में **बासेल (स्विट्जरलैंड), कोलोन, बॉन , डुइसबर्ग और न्यूस (जर्मनी), स्ट्रासबर्ग (फ्रांस), तथा रॉटरडैम (नीदरलैंड)** शामिल हैं।

मेक्सिको की खाड़ी में डेड ज़ोन

राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन (NOAA) ने **मेक्सिको की खाड़ी में लगभग 5,827 वर्ग मील क्षेत्र में औसत से अधिक ग्रीष्मकालीन डेड ज़ोन का पूर्वानुमान** लगाया है। वर्तमान मिसिसिपी-अटचाफ़लया जलक्षेत्र (Mississippi-Atchafalaya watershed) में शहरों और कृषि क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों से होने वाले अत्यधिक पोषक प्रदूषण का परिणाम है।

डेड ज़ोन के बारे में:

डेड ज़ोन, या हाइपोक्सिक क्षेत्र, दुनिया की झीलों और महासागरों में कम ऑक्सीजन वाले क्षेत्रों को संदर्भित करता है।

चूँकि ज़्यादातर जीवों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसलिए कुछ ही जीव हाइपोक्सिक परिस्थितियों में जीवित रह पाते हैं। इसीलिए इन क्षेत्रों को मृत क्षेत्र या डेड ज़ोन कहा जाता है।

हाइपोक्सिक क्षेत्र प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन मानवीय गतिविधियों के कारण भी मृत क्षेत्रों का निर्माण हो सकता है।

मृत क्षेत्र कैसे बनते हैं?

मृत क्षेत्र **यूट्रोफिकेशन के कारण** उत्पन्न होता है। यह तब होता है जब **जल का कोई स्रोत फास्फोरस और नाइट्रोजन जैसे अत्यधिक पोषक तत्वों** से भर जाता है।

सामान्य स्तर पर, **साइनोबैक्टीरिया - या नीला-हरा शैवाल - नामक जीव** इन पोषक तत्वों पर निर्भर रहता है। पोषक तत्वों के कारण बहुत कम समय में शैवाल की अत्यधिक वृद्धि हो सकती है, जिसे शैवाल प्रस्फुटन भी कहा जाता है ।

मृत क्षेत्र तब बनते हैं जब शैवाल मर जाते हैं, नीचे डूब जाते हैं और जीवाणुओं द्वारा विघटित हो जाते हैं, इसके परिणामस्वरूप पानी से घुली हुई ऑक्सीजन कम हो जाती है।

कला एवं संस्कृति

अहिल्या बाई होल्कर की 300वीं जयंती

31 मई, 2024 को मराठा रानी अहिल्या बाई होल्कर की **300वीं जयंती** मनाई गई। अहिल्या बाई का शासनकाल उत्कृष्ट शासन के लिए जाना जाता है, जिसने सच्चे अर्थों में सामाजिक सद्भाव लाने में मदद की।

अहिल्या बाई का जीवन

अहिल्या बाई होल्कर का जन्म **1725 में अहमदनगर जिले (महाराष्ट्र) के चोंडी गांव** में एक चरवाहा (धनगर /गडरिया) परिवार में हुआ था।

इनका विवाह 1733 में 8 वर्ष की आयु में खांडेराव होल्कर से हुआ था।

वर्ष 1754 में भरतपुर के राजा के विरुद्ध कुंभेर की लड़ाई में अपने पति की मृत्यु के बाद, अहिल्या बाई ने एक सम्राट के रूप में शासन किया।

अहिल्याबाई **11 दिसंबर 1767 को इंदौर (मालवा) की शासक** बनीं। अगले 28 वर्षों (1767 से 1795) तक, महारानी अहिल्याबाई ने मालवा पर शासन किया।

मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा ध्वस्त किए जाने के लगभग 100 वर्षों बाद, 1780 में, अहिल्या बाई होल्कर के नेतृत्व में **वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार** हुआ। इन्होंने **1783 में सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार** करवाया।

इन्होंने महेश्वर में एक कपड़ा उद्योग स्थापित किया, जो आज अपनी **महेश्वरी साड़ियों** के लिए प्रसिद्ध है।

नालंदा विश्वविद्यालय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने **19 जून को नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस** का उद्घाटन किया। विश्वविद्यालय को **प्रसिद्ध वास्तुकार पद्म विभूषण स्वर्गीय बी.वी. दोशी ने डिजाइन** किया है।

इसके **बुनियादी ढांचे को नेट जीरो यानी शून्य कार्बन उत्सर्जन वाले कैंपस के रूप में** बनाया गया है।

परिसर से **लगभग 12 किलोमीटर दूर नालंदा महाविहार के खंडहर** हैं, जो प्राचीन दुनिया में ज्ञान के सबसे महान केंद्रों में से एक है।

भारत के अलावा 17 देशों - ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, ब्रुनेई दारुस्सलाम, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओस, मॉरीशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम ने विश्वविद्यालय की स्थापना में मदद की है।

बिहार में **प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों को 2016 में यूनेस्को द्वारा विश्व सांस्कृतिक धरोहर घोषित** किया गया था।

नालंदा का इतिहास

संरक्षण

नालंदा प्राचीन और मध्यकाल में एक प्रसिद्ध **बौद्ध महाविहार यानी महान मठ** हुआ करता था। ये दुनियाभर में **बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा शिक्षण केंद्र** था।

यह प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय **तीसरी से छठी शताब्दी ईसवी के बीच में गुप्त काल के दौरान** अस्तित्व में आया था। **427 ई. में सम्राट कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना** की थी। **13वीं शताब्दी यानी 800 से अधिक वर्षों तक यहां विश्वविद्यालय संचालित** होता रहा।

गुप्तों के बाद, **कन्नौज के हर्षवर्धन (बौद्ध स्रोतों में शिलादित्य के रूप में जाने जाते हैं) नालन्दा महाविहार के सबसे उल्लेखनीय संरक्षक** थे।

यद्यपि शाही संरक्षण **पालों के शासनकाल (8वीं-12वीं शताब्दी ई.) तक जारी** रहा, फिर भी पाल शासनकाल के दौरान **विक्रमशिला और सोमपुरा जैसे कई प्रतिस्पर्धी मठों के निर्माण के कारण इसमें धीरे-धीरे गिरावट** देखी गई।

वास्तव में, नालंदा के खंडहरों से **सबसे पुराना पुरातात्विक साक्ष्य शक्रादित्य (गैर-बौद्ध स्रोतों में चंद्रगुप्त द्वितीय "विक्रमादित्य" के पुत्र कुमारगुप्त प्रथम के रूप में जाना जाता है) के नाम से अंकित एक सिक्का है, जो 415-55 ई. के बीच** का माना जा सकता है, जब शक्रादित्य का शासन था।

यात्रा वृत्तांत

साहित्यिक स्रोतों में सबसे ज़्यादा उद्धृत **7वीं शताब्दी के चीनी तीर्थयात्री ह्वेन त्सांग (जिन्हें मोक्षदेव के नाम से भी जाना जाता है) का यात्रा वृत्तांत** है, जिन्होंने बौद्ध पांडुलिपियों की तलाश में **629-645 ई. तक पूरे भारत की यात्रा** की थी। इन्होंने **नालंदा में लगभग पाँच साल** बिताए, जहाँ इन्होंने **महाविहार के महान मठाधीश शीलभद्र के अधीन अध्ययन** किया।

ह्वेन त्सांग ने अनुमान लगाया कि **उनकी यात्रा के समय, मठ में 10,000 छात्र, 2,000 शिक्षक और नौकरों का एक विशाल दल रहता** था।

लेकिन चीनी यात्री **फ़ा हियान ने 5वीं शताब्दी ई. की शुरुआत में मगध की यात्रा की थी, इसने नालंदा महाविहार का ज़िक्र तक नहीं** किया।

चीनी तीर्थयात्री **यिजिंग, जो 675-685 ई. तक महाविहार** में रहे, ने उल्लेख किया है कि **नालंदा में "3,000 से अधिक" लोग रहते** थे।

विध्वंस

1193 ई. में तुर्की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में आक्रमणकारियों की सैन्य टुकड़ी ने विश्वविद्यालय को जलाकर खत्म कर दिया था।

नालंदा विश्वविद्यालय का परिसर इतना विशाल था कि हमलावरों के **आग लगाने के बाद परिसर तीन महीने तक जलता** रहा।

खेल

ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024

हाल ही में, **भारत ने बारबाडोस में दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी टी-20 विश्व कप जीत** लिया है। यह 2013 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भारत का पहला आईसीसी खिताब है।
प्लेयर ऑफ द मैच: विराट कोहली
प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट: जसप्रीत बुमराह
टी20 विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक विकेट:अर्शदीप सिंह (भारत) और फ़ज़लहक फ़ारूक़ी (अफगानिस्तान)- 17 विकेट
टी20 विश्व कप संस्करण में सबसे कम इकॉनमी रेट:
4.17 - जसप्रीत बुमराह (2024)
यह तीसरी बार है जब किसी टीम ने लक्ष्य का बचाव करते हुए टी-20 विश्व कप फाइनल जीता है, इससे पहले **2007 में भारत और 2012 में वेस्टइंडीज** ने लक्ष्य का बचाव करते हुए जीत हासिल की थी।
भारत पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रहकर टी-20 विश्व कप जीतने वाली पहली टीम बन गई है।
विश्व कप जीत के बाद, तीन भारतीय खिलाड़ियों **विराट कोहली, रोहित शर्मा और रवींद्र जडेजा** ने टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों से संन्यास की घोषणा कर दी है।

आयोजन

आईसीसी पुरुष टी-20 विश्व कप के नौवें संस्करण में 20 टीमों ने भाग लिया है। यह टूर्नामेंट 1-29 जून के बीच **अमेरिका और वेस्टइंडीज** की संयुक्त मेजबानी में खेला गया।
9 स्थानों पर 20 टीमों द्वारा **कुल 55 मैच खेले गये**, जिसका समापन 29 जून को बारबाडोस में हुआ।
20 टीमों में शामिल हैं- भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, स्कॉटलैंड, ओमान, वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, युगांडा, पापुआ न्यू गिनी, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, नीदरलैंड, नेपाल।

एम्बेसडर

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने भारत के दिग्गज खिलाड़ी युवराज सिंह को ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का एम्बेसडर घोषित किया है, जब T20 क्रिकेट के शुरू होने में केवल 36 दिन शेष थे। युवराज सिंह ने 2007 में पहले टी-20 विश्व कप के दौरान एक ओवर में 36 रन बनाए थे।
युवराज सिंह के अलावा, **पकिस्तान के शाहिद अफरीदी, वेस्टइंडीज के क्रिस गेल और जमैका के धावक उसेन बोल्ट को 9वें** आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप का ब्रांड एंबेसडर चुना गया हैं।

टीम ऑफ द टूर्नामेंट

आईसीसी ने टी20 विश्व कप 2024 के लिए टीम ऑफ द टूर्नामेंट की घोषणा कर दी है। खिताब जीतने वाली भारतीय टीम के छह खिलाड़ियों को इस टीम में आईसीसी ने जगह दी है, वहीं रनरअप रही साउथ अफ्रीकन टीम का कोई भी खिलाड़ी टॉप 11 में जगह नहीं बना सका है।

अगला टी20 विश्व कप

अगला टी20 विश्व कप 2026 में भारत और श्रीलंका में की संयुक्त मेजबानी में होगा. आईसीसी ने जानकारी दी है कि अगले टूर्नामेंट में भी 55 मैच खेले जाएंगे।

ब्रिक्स खेल 2024

ब्रिक्स खेलों का आयोजन 12 से 23 जून, 2024 तक **कज़ान, तातारस्तान (रूस) में** किया गया। इस प्रतियोगिता में **82 देशों के एथलीटों ने 27 खेलों** में भाग लिया।

ब्रिक्स अध्यक्ष देश में खेल आयोजनों की परंपरा 2016 में शुरू हुई, जब भारत में पहला फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया गया था।

ब्रिक्स खेलों का मुख्य लक्ष्य राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण खेल संबंधों को मजबूत करना, समानता, गैर-भेदभाव और सभी एथलीटों के लिए प्रतिस्पर्धा करने की समान पहुंच के सिद्धांतों को बढ़ावा देना है।

इस खेल प्रतियोगिता की पदक तालिका में **शीर्ष 3 देशों में रूस (262 स्वर्ण, 141 रजत, 99 कांस्य पदक), बेलारूस (55 स्वर्ण, 85 रजत, 107 कांस्य पदक) और चीन (20 स्वर्ण, 24 रजत, 18 कांस्य पदक)** शामिल हैं

।

महत्वपूर्ण दिवस

विश्व पर्यावरण दिवस

विश्व पर्यावरण दिवस (WED) **प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सतत प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम** के रूप में मनाया जाता है।

इस साल, सऊदी अरब को 2024 पर्यावरण दिवस समारोह की मेज़बानी करने का सम्मान मिला है।

विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का विषय है "हमारी भूमि, हमारा भविष्य, हम पीढ़ी पुनर्स्थापना हैं" ("Our Land, Our Future, We Are Generation Restoration"), जिसमें भूमि पुनर्स्थापना, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

5 जून, 1972 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना के साथ ही विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत हुई।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2021 से 2030 तक के दशक को पारिस्थितिकी तंत्र बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक (UN Decade on Ecosystem Restoration) के रूप में घोषित किया है।

विश्व महासागर दिवस

हर वर्ष **विश्व महासागर दिवस 8 जून को** मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस की अवधारणा **पहली बार 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन में प्रस्तावित** की गई थी।

2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया।

इस दिन की स्थापना महासागरों के साथ मनुष्यों के संबंध के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से की गई थी।

इस वर्ष के विश्व महासागर दिवस का विषय है - **"नई गहराई को जागृत करें" (Awaken New Depths)।**

महासागर पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक भाग को कवर करते हैं और जलवायु को नियंत्रित करने, भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करने तथा विविध प्रकार के समुद्री जीवन को सहारा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

विश्व शरणार्थी दिवस 2024

प्रत्येक वर्ष 20 जून को दुनिया भर के लोग विश्व शरणार्थी दिवस मनाने के लिए एक साथ आते हैं ।

विश्व शरणार्थी दिवस 2024 का थीम है "एक ऐसी दुनिया जहां शरणार्थियों का स्वागत किया जाता है (For a World Where Refugees Are Welcomed)।"

विश्व शरणार्थी दिवस दुनिया भर के शरणार्थियों को समर्पित है। यह दिवस पहली बार 20 जून 2001 को शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित 1951 के कन्वेंशन की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए वैश्विक स्तर पर मनाया गया था।

दिसंबर 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आधिकारिक तौर पर इसे अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किए जाने से पहले इसे मूल रूप से अफ्रीका शरणार्थी दिवस के रूप में जाना जाता था।

विश्व जल सर्वेक्षण दिवस 2024

प्रत्येक वर्ष 21 जून को, अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफी संगठन (आईएचओ) जल विज्ञान के बारे में जागरूकता बढ़ाने और समुद्रों और महासागरों के बेहतर ज्ञान में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित करने के लिए **विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 2024 (World Hydrography Day)** मनाता है।

वर्ष 2024 के हाइड्रोग्राफी दिवस का विषय "हाइड्रोग्राफी सूचना - समुद्री गतिविधियों में सुरक्षा, दक्षता और स्थिरता को बढ़ाना" ("Hydrographic Information - Enhancing Safety, Efficiency and Sustainability in Marine Activities") है।

अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन के बारे में:

यह एक **अंतर-सरकारी संगठन** है जो यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है कि विश्व के सभी समुद्रों, महासागरों और नौगम्य जल का सर्वेक्षण और मानचित्रण किया जाए।

इसकी **स्थापना 1921 में** हुई थी, यह राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालयों की गतिविधियों का समन्वय करता है। वर्तमान में **इसके 100 सदस्य देश** हैं ।

आईएचओ **सचिवालय मोनाको रियासत (एक संप्रभु देश)** में स्थित है।

भारत 1955 से अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफ़िक संगठन (आईएचओ) का सक्रिय सदस्य रहा है।

भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण विभाग (आईएनएचडी), या पहले भारतीय समुद्री सर्वेक्षण, की स्थापना 1874 में कोलकाता में की गई थी। यह **हाइड्रोग्राफी के लिए नोडल एजेंसी** है और इसके पास स्वदेश निर्मित आधुनिक सर्वेक्षण जहाजों का बेड़ा है।

QuizHat

वन लाइनर

- संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के मध्य "फ्रीडम एज" नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा- **बुसान (दक्षिण कोरिया) में**
- G7 नेताओं का शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून तक आयोजित किया गया है- **इटली के अपुलिया क्षेत्र में बोर्गो एग्नाज़िया (भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए शामिल)**
- अमेरिका में चर्चा में रही मिफेप्रिस्टोन है- **गर्भपात की गोली**
- 2,800 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन के साथ अगले दो वर्षों (2025-26 तक) के लिए शुरू किया जाएगा- **डिजिटल कृषि मिशन**
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए भारत के पड़ोसी सात देश हैं- **बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, मॉरीशस और सेशेल्स**
- यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है- **एंटोनियो कोस्टा को**
- हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है- **कपिल देव को**
- आईसीसी टूर्नामेंट के सभी प्रारूपों के फाइनल में कप्तानी करने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं - **रोहित शर्मा**
- हाल ही में शिमला के चैडविक हाउस में ऐतिहासिक संग्रहालय का उद्घाटन किया है– **गिरी**श चंद्र मुर्मू ने
- हॉकी इंडिया ने ओलंपिक के लिए टीम की घोषणा कर दी है, टीम का कप्तान बनाया गया है- **हरमनप्रीत सिंह**
- हाल ही में मिनी रत्न का दर्जा दिया गया – **सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को**
- भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए हैं - **1.169 मिलियन अमेरिकी डॉलर**
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य बना है – **पैराग्वे**
- उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के अगले महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है- **मार्क रूटे को**
- संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी नामित किया है – **केन्या को**
- हुनर भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी कहां आयोजित की जा रही है – **दुबई**
- रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक मनोज यादव ने मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया है - **संज्ञान ऐप**
- अफगानिस्तान को हराकर टी20 विश्व कप 2024 के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम है- **दक्षिण अफ्रीका**
- नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस हर साल मनाया जाता है – **26 जून को**
- डीआरडीओ ने हाल ही में मध्यम दूरी का माइक्रोवेव ऑब्स्क्यूरेंट चैफ रॉकेट सौंपा है– **भारतीय नौसेना को**
- नाटककार हेरोल्ड पिंटर की स्मृति में स्थापित पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है- **अरुंधति रॉय को**
- 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है- **ओम बिरला को**
- वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा एनसीआर में वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है- **4.5 करोड़**
- भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ किया गया है- **गुजरात**
- तैराकी में यूनिवर्सलिटी कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालीफाई किया है- **श्रीहरि नटराज और धनिधि देसिंघु**
- हाल ही में हर जिले में 'प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय' स्थापित करने की घोषणा की है- **मध्य प्रदेश ने**
- 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला सांसद हैं- **कोटा (राजस्थान) से**
- राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है- **जगत प्रकाश नड्डा को**
- केरल के शहर को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया है- **कोझीकोड**
- चीनी क्षेत्र के वैश्विक आयोजन 'आईएसओ परिषद बैठक' की मेजबानी कर रहा है- **भारत**
- हाल ही में खबरों में रही नैट्रॉन झील स्थित है- **तंजानिया में**
- विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया- **श्रीनगर को**
- विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी की है- **UNCTAD ने**
- राष्ट्रीय दस्त रोको अभियान 2024 का शुभारंभ किया है- **जेपी नड्डा ने**
- टी20 विश्व कप 2024 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमें हैं- **भारत, अफगानिस्तान, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका**
- 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ली है- **भर्तृहरि महताब ने**
- इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 'फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन - **विश्वसनीय यात्री सुविधा' का उद्घाटन किया है- गृह मंत्री अमित शाह**
- भारत ने हाल ही में ई-मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है- **बांग्लादेश के लिए**
- लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा- **उत्तर प्रदेश में**
- भारत ने एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है- **बांग्लादेश में**
- विश्व शरणार्थी दिवस हर साल मनाया जाता है- **20 जून को**
- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का विषय है- **"स्वयं और समाज के लिए योग"**
- संयुक्त राष्ट्र संगठन ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है- **UNHCR का**
- विश्व संगीत दिवस हर साल मनाया जाता है- **21 जून को**

- भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं- **एशियाई विकास बैंक के साथ**
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में हिस्सा लिया- **श्रीनगर में**
- ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किया गया है- **रूस में**
- विश्व शरणार्थी दिवस 2024 का विषय है- **'एक ऐसी दुनिया के लिए जहां शरणार्थियों का स्वागत किया जाता है'**
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी है, यह किस राज्य में बनाया जाएगा- **महाराष्ट्र**
- हाल ही में प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक का निधन हो गया- **पी. थंकप्पन नायर**
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया- **बिहार में**
- पावो नूरमी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है- **नीरज चोपड़ा ने**
- मंत्रालयों ने कृषि सखी प्रमाणन कार्यक्रम के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए- **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय**
- हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान है - **176वां**
- बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास 'तरंग शक्ति' की मेजबानी करेगा- **भारत**
- टी20 विश्व कप मैच में चारों मेडन ओवर फेंकने वाले पहले गेंदबाज हैं- **लॉकी फर्ग्यूसन**
- कंचनजंगा एक्सप्रेस रेल दुर्घटना राज्य में हुई - **पश्चिम बंगाल में**
- भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का पहला ट्रायल रन पूरा किया - **चिनाब नदी पर**
- बिनसर वन्यजीव अभयारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए MI17 हेलीकॉप्टर को तैनात किया - **भारतीय वायु सेना ने**
- गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य हाल ही में खबरों में था, यह स्थित है - **मध्य प्रदेश ने**
- हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उद्घाटन किया - **पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा**
- दक्षिण अफ्रीकी संसद द्वारा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया - **सिरिल रामफोसा को**
- द्विपक्षीय जापान-भारत समुद्री अभ्यास, 2024 (JIMEX 24) का आठवाँ संस्करण आयोजित किया गया है- **जापान के योकोसुका में**
- अमेरिका में अभ्यास 'रेड फ्लैग 2024' का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया - **एयेल्सन एयर फोर्स बेस, अलास्का में**
- हाल ही में एक बार फिर देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है- **अजीत डोभाल को**
- विश्व रक्तदाता दिवस हर साल मनाया जाता है- **14 जून को**
- भारत ने आपदाग्रस्त पापुआ न्यू गिनी को मानवीय सहायता भेजी है- **1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की**
- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है- **डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा को**
- अजीत डोभाल बसे लंबे समय तक सेवा करने वाले व्यक्ति हैं- **राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर**
- ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान है - **129 वां**
- हाल ही में कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2024 जारी किया गया- **विश्व आर्थिक मंच द्वारा**
- अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर एक क्रेटर का नाम रखा है- **प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर**
- नासा भारत में बहुऔषधि प्रतिरोधी रोगजनकों पर शोध कर रहा है- **आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर**
- पेमा खांडू ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है- **अरुणाचल प्रदेश के**
- ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में पहला स्थान हासिल किया है- **आइसलैंड ने**
- कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2024 में विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी ने स्थान हासिल किया है – **18वां**
- भारतीय सेना के अगले प्रमुख के रूप में नामित किया गया है- **लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी**
- ओडिशा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है- **मोहन चरण माझी ने**
- आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है- **चंद्रबाबू नायडू ने**
- सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य हाल ही में चर्चा में है, यह स्थित है- **उत्तर प्रदेश ने**
- एफआईएच हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा- **भारत में**
- फ्रेंच ओपन 2024 का खिताब जीता है- **कार्लोस अल्काराज़ (स्पेन)**
- ओडिशा के उपमुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है- **कनक वर्धन सिंह देव और पार्वती परिदा**
- प्रेम सिंह तमांग ने हाल ही में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है- **सिक्किम राज्य के**
- नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के पीएम के रूप में शपथ ली, उन्होंने लोकसभा क्षेत्र से जीत हासिल की- **वाराणसी से**
- इस बार मोदी कैबिनेट में पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं- **6**
- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में शामिल किया है- **इजरायल को**
- फ्रेंच ओपन 2024 महिला खिताब जीतने वाली इगा स्वियाटेक खिलाड़ी हैं- **पोलैंड की**
- हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को मोदी कैबिनेट 2024 में मंत्रालय दिया गया है- **ऊर्जा मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय**
- केंद्रीय मंत्रिमंडल 2024 में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है- **पीएम नरेंद्र मोदी के पास**
- हाल ही में राज्य के दो वेटलैंड्स को 'रामसर साइट्स' की सूची में शामिल किया है- **बिहार**
- विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल मनाया जाता है - **7 जून को**

- हाल ही में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रीसाइक्लिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया- **सिक्किम में**
- मोबाइल ऐप 'सारथी 2.0' हाल ही में लॉन्च किया गया - **सेबी द्वारा**
- अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं- **रोहित शर्मा**
- लोकसभा चुनाव 2024 में नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े- **इंदौर (मध्य प्रदेश)**
- हाल ही में खबरों में रही 'स्पर्श' सेवा मंत्रालय से संबंधित है- **रक्षा मंत्रालय**
- हाल ही में फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है- **स्लोवेनिया ने**
- हाल ही में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं- **हरियाणा ने**
- कुवैत के अमीर ने नया क्राउन प्रिंस नियुक्त किया है- **शेख सबाह को**
- एनपीसीआई इंटरनेशनल ने हाल ही में यूपीआई भुगतान के लिए समझौता किया है- **पेरू के साथ**
- रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए एक समर्पित टेली मानस सेल स्थापित करने के लिए हाथ मिलाया है- **केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**
- हाल ही में आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है- **दक्षिण कोरिया ने**
- विश्व पर्यावरण दिवस हर साल मनाया जाता है- **5 जून को**
- क्लाउडिया शिनबाम पहली महिला निर्वाचित राष्ट्रपति बनी हैं- **मेक्सिको की**
- हाल ही में नीली चींटी की एक नई प्रजाति खोजी गई है- **अरुणाचल प्रदेश में**
- हाल ही में इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है- **मालदीव ने**
- 2024 के लोकसभा चुनाव में कितने करोड़ भारतीय मतदान करके विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे? - **64.2 करोड़**
- 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटों पर मतदान होगा - **543**
- संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुईं - **रुचिरा कंबोज**
- हाल ही में आईआईएम की स्थापना के लिए केंद्रीय मंजूरी मिली है - **असम में**
- अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की अगली वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा - **भारत**
- हाल ही में चंद्रमा पर चांग'ई-6 मिशन भेजा है - **चीन ने**
- प्रसिद्ध भारतीय वन्यजीव जीवविज्ञानी और अग्रणी संरक्षणवादी, जिनका निधन हो गया है- **असीर जवाहर थॉमस जॉनसिंह (एजेटी जॉनसिंह)**

QuizHat

महत्वपूर्ण शब्दावली

ग्लोबल साउथ

ग्लोबल साउथ का तात्पर्य एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और ओशिनिया के देशों से है। इनमें से अधिकांश देश, जहाँ दुनिया की 88 प्रतिशत आबादी रहती है, ने औपनिवेशिक शासन का अनुभव किया है और ऐतिहासिक रूप से औद्योगीकरण के पर्याप्त स्तर को प्राप्त करने में पिछड़े हुए हैं। दूसरी ओर, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के विकसित देशों को अक्सर ग्लोबल नॉर्थ के नाम से जाना जाता है। इन देशों का साम्राज्यवादी नीतियों को अपनाने का इतिहास रहा है।

एंजल टैक्स

यह टैक्स तब लगाया जाता है, जब कोई गैर-सूचीबद्ध कंपनी किसी निवेशक को उसके उचित बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर शेयर जारी करती है। पहले, यह केवल घरेलू निवेशक (resident investor) द्वारा किए गए निवेश पर लगाया जाता था। हालाँकि वित्त अधिनियम 2023 में 1 अप्रैल, 2024 से गैर-निवासी निवेशकों पर भी एंजेल टैक्स लागू करने का प्रस्ताव है।

एंजेल टैक्स पहली बार 2012 में लागू किया गया था, ताकि किसी निजी स्वामित्व वाली कंपनी के शेयरों को उस कंपनी के शेयरों के उचित बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर खरीदकर बेहिसाब धन के सृजन और उपयोग को रोका जा सके।

पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2002-2016) के अनुसार, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की सीमाओं के 10 किलोमीटर के भीतर की भूमि को पारिस्थितिक रूप से सुभेद्य क्षेत्र या पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) के रूप में अधिसूचित किया जाता है। 10 किलोमीटर से परे के क्षेत्रों को भी केंद्र सरकार द्वारा ईएसजेड के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है, अगर वे पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण "संवेदनशील गलियारे" रखते हैं।

QuizHat

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

1. निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए:
   1. चीन
   2. जापान
   3. यूएसए
   4. फ्रांस
   5. इटली
   6. कनाडा

उपर्युक्त देशों में से कितने देश G7 का हिस्सा हैं?

A. केवल दो
B. केवल तीन
C. केवल चार
D. केवल पाँच

उत्तर: (D)

1. एन्जेल टैक्स के बारे में कौन-सा कथन सही है?

A. यह कर सूचीबद्ध कंपनियों पर लगाया जाता है जब वे शेयरों के उचित बाजार मूल्य से अधिक शेयरों के निर्गमन के माध्यम से अतिरिक्त पूंजी जुटाती हैं।
B. यह गैर-सूचीबद्ध कंपनियों पर लगाया जाने वाला कर है, जब वे शेयरों के उचित बाजार मूल्य से अधिक शेयरों के निर्गमन के माध्यम से अतिरिक्त पूंजी जुटाती हैं।
C. यह पांच वर्ष से कम पुराने स्टार्टअप में निवेश करने वाली उद्यम पूंजी पर लगाया जाने वाला कर है।
D. यह दस वर्ष की अवधि में किसी स्टार्टअप में निवेश करने के लिए उद्यम पूंजी पर लगाया गया कर है।

उत्तर: (B)

3. पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह सर्वेक्षण नीति आयोग द्वारा आयोजित किया जाता है।

2. इस सर्वेक्षण का उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं की घरेलू खपत पर आंकड़े एकत्र करना है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 व 2 दोनों
D. न तो 1 न ही 2
E.

उत्तर: (B)

4. निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही है?

1. सिम्बेक्स- भारत और सिंगापुर

2. समुद्र शक्ति- भारत और इंडोनेशिया

3. जिमेक्स- भारत और जापान

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2 और 3

उत्तर: (D)

5. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संविधान में प्रोटेम स्पीकर के पद का उल्लेख नहीं है।

2. प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

3. नये सांसदों को शपथ दिलाना प्रोटेम स्पीकर का प्राथमिक कर्तव्य है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2 और 3

उत्तर: (D)

6. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. कन्नौज के हर्षवर्धन नालन्दा महाविहार के उल्लेखनीय संरक्षक थे।
2. ह्वेनसांग ने 7वीं शताब्दी ई. में नालंदा का दौरा किया था और महाविहार के मठाधीश शीलभद्र के अधीन अध्ययन किया था।
3. चीनी यात्री फ़ा हियान ने अपने यात्रा वृतांत में नालंदा महाविहार का उल्लेख नहीं किया है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सत्य हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी तीनों
D. कोई नहीं

उत्तर: (C)

7. तीस्ता नदी के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. तीस्ता नदी का स्रोत ब्रह्मपुत्र नदी के समान ही है।

2. रंगीत नदी तीस्ता की सहायक नदी है।

3. तीस्ता नदी भारत में असम और पश्चिम बंगाल में बहती है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 और 3
B. केवल 2
C. केवल 2 और 3
D. 1, 2 और 3

उत्तर: (B)

8. निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए:

1. भारत

2. रूस

3. चीन

4. जर्मनी

5. सऊदी अरब

उपर्युक्त देशों में से कितने देश FATF के सदस्य हैं?

A. केवल दो
B. केवल तीन
C. केवल चार
D. सभी पाँच

उत्तर: (C)

9. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. संविधान की दूसरी अनुसूची में संसदीय शपथ का उल्लेख है।

2. लोकसभा सांसद का पांच वर्ष का कार्यकाल भारत के चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के परिणाम घोषित करने के साथ ही शुरू हो जाता है।

3. राष्ट्रपति अस्थायी अध्यक्ष को शपथ दिलाते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1,2 और 3

उत्तर: (D)

10. निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है?

1. मैसूर

2. मलप्पुरम

3. जयपुर

4. श्रीनगर

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1,2 और 3
D. 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (D)

11. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. विपक्ष के नेता की स्थिति भारत के संविधान में वर्णित है।

2. विपक्ष का नेता प्रमुख पदों पर नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समितियों में विपक्ष का प्रतिनिधि होता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 न ही 2

उत्तर: (B)

12. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्यकाल सात वर्षों का होता है।

2. नेशनल असेंबली का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है जो सभी घरेलू नीतिगत निर्णयों के लिए जिम्मेदार होता है।

निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 व 2 दोनों
D. न तो 1 न ही 2

उत्तर: (D)

13. निम्नलिखित में से कौन-सा भारत के कुछ भागों में पीने के पानी में प्रदूषक के रूप में पाया जा सकता है?

1. आर्सेनिक

2. सोर्बिटोल

3. फ्लोराइड

4. फॉर्मेल्डिहाइड

5. यूरेनियम

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए।

A. केवल 1 और 3
B. केवल 2, 4 और 5
C. केवल 1, 3 और 5
D. 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर : (C)

15. डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना (DHIS) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. इस योजना को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) द्वारा शुरू किया गया था।

2. इसे 2018 में लॉन्च किया गया था।

3. यह योजना केवल सार्वजनिक अस्पतालों पर लागू है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. केवल तीन
D. कोई भी नहीं

उत्तर: (A)

16. कावली पुरस्कार निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में प्रदान किये जाते हैं?

1. खगोल भौतिकी

2. नैनोविज्ञान

3. तंत्रिका विज्ञान

4. जैव रसायन

5. बाह्य अंतरिक्ष

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

A. केवल 1 और 2
B. केवल 1, 2 और 3
C. केवल 1, 2, 3 और 4
D. 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर: (B)

17. हाल ही में खबरों में रहा 'थिस्मिया मलायाना' क्या है?

A.पौधे की एक नई प्रजाति

B.जंगली बिल्ली की एक प्रजाति

C.समुद्री शैवाल की एक नई प्रजाति

D.हाल ही में खोजा गया सरीसृप का एक जीवाश्म

उत्तर (A)

18. H5N2 वायरस, किस बीमारी से संबंधित है?

A. स्वाइन फ्लू
B. बर्ड फ्लू
C. निपाह वायरस
D. मंकी वायरस

उत्तर (B)

19. विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस (World Food Safety Day) किस दिन मनाया जाता है?

A. 5 जून
B. 6 जून
C. 7 जून
D. 8 जून

उत्तर (C)

20. किस संस्था ने हाल ही में 'सारथी 2.O' मोबाइल ऐप लॉन्च किया है?

A. सिडबी
B. आरबीआई
C. आईसीएमआर
D. सेबी

उत्तर (D)

QuizHat

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के रूप में वैश्विक दक्षिण के उदय ने बदलती वैश्विक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया है। टिप्पणी कीजिए।

वैश्विक दक्षिण का उदय आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के रूप में एक महत्वपूर्ण घटना है जो बदलती वैश्विक व्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। इसके कुछ मुख्य पहलू निम्नलिखित हैं:

1. आर्थिक विकास: वैश्विक दक्षिण के देशों, जैसे कि चीन, भारत, ब्राज़ील, और दक्षिण अफ्रीका, ने पिछले दशकों में तीव्र आर्थिक विकास किया है। ये देश अब वैश्विक व्यापार, निवेश, और उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। विशेष रूप से चीन और भारत ने विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं।

2. राजनीतिक प्रभाव: वैश्विक दक्षिण के देश अब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अधिक प्रभावशाली भूमिका निभा रहे हैं। ब्रिक्स (BRICS) जैसे संगठनों का उदय इस परिवर्तन का प्रतीक है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। ये देश अब संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन (WTO), और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) जैसे संस्थानों में अधिक प्रभाव डाल रहे हैं।

3. संसाधनों का उपयोग: वैश्विक दक्षिण के देशों में प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर मात्रा है, जिससे ये देश वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण बन गए हैं। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में खनिज, तेल, और गैस के विशाल भंडार हैं, जो इन क्षेत्रों की आर्थिक महत्वता को बढ़ाते हैं।

4. विकासशील देशों के साथ सहयोग: वैश्विक दक्षिण के देश आपस में सहयोग बढ़ा रहे हैं, जो दक्षिण-दक्षिण सहयोग (South-South Cooperation) के रूप में जाना जाता है। यह सहयोग आर्थिक, तकनीकी, और सांस्कृतिक क्षेत्रों में हो रहा है, जिससे विकासशील देशों के बीच सहयोग और एकजुटता बढ़ रही है।

5. बदलती वैश्विक व्यवस्था: वैश्विक दक्षिण के उदय ने पश्चिमी देशों की परंपरागत वैश्विक प्रभुत्व को चुनौती दी है। इससे एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय हो रहा है, जहां कई देशों और क्षेत्रों का प्रभाव बढ़ रहा है। यह परिवर्तन वैश्विक शक्ति संतुलन में महत्वपूर्ण बदलाव ला रहा है।

वैश्विक दक्षिण का यह उदय एक नई वैश्विक व्यवस्था की दिशा में संकेत करता है, जहां अधिक समावेशी और विविधतापूर्ण शक्ति संरचना हो सकती है। इस प्रक्रिया में चुनौतियाँ भी हैं, जैसे कि गरीबी, असमानता, और पर्यावरणीय समस्याएँ, जिन्हें सामूहिक प्रयासों से सुलझाना आवश्यक होगा।

प्रश्न 2. अनियंत्रित और बिना सोचे-समझे किया गया शहरी विस्तार दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में लगातार शहरी बाढ़ कारण बनता जा रहा है। चर्चा कीजिये।

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में शहरी बाढ़ की समस्या का एक प्रमुख कारण अनियंत्रित और बिना सोचे-समझे किया गया शहरी विस्तार है। इस समस्या के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हैं:

1. अनियोजित शहरीकरण

अनियोजित शहरीकरण के कारण कई क्षेत्रों में प्राकृतिक जल निकासी प्रणालियों का विनाश हो गया है। जल निकासी चैनल, नदियाँ, और झीलें जो बारिश के पानी को अवशोषित और निपटाने का काम करती थीं, अब कंक्रीट के जंगलों में बदल गई हैं।

2. अपर्याप्त जल निकासी व्यवस्था

दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में जल निकासी की व्यवस्था पुरानी और अपर्याप्त है। बारिश के पानी को जल्दी से निकालने के लिए नई और बेहतर जल निकासी प्रणालियों की आवश्यकता है। पुराने नालों और सीवर सिस्टम की क्षमता कम हो गई है और यह बारिश के मौसम में भारी जलभराव का कारण बनते हैं।

3. कंक्रीटीकरण और हरित क्षेत्रों की कमी

हरित क्षेत्रों, पार्कों, और खुली जमीन का कंक्रीटीकरण से घटाव हो गया है। पेड़ और अन्य वनस्पतियाँ बारिश के पानी को अवशोषित करने में मदद करती हैं, लेकिन कंक्रीट की सड़कों और इमारतों के चलते पानी का जमीन में समाना मुश्किल हो जाता है, जिससे जलभराव बढ़ता है।

4. भूमि के अनुचित उपयोग

भूमि उपयोग योजना में अनियमितता और कृषि भूमि का आवासीय और व्यावसायिक उपयोग में बदलना भी बाढ़ का प्रमुख कारण है। अनियंत्रित निर्माण गतिविधियों के चलते प्राकृतिक जल निकासी मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं।

5. जलवायु परिवर्तन

जलवायु परिवर्तन के चलते बारिश के पैटर्न में भी परिवर्तन आ रहा है। भारी बारिश की घटनाएं अधिक हो रही हैं, जिससे अचानक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है।

समाधान:

1. सख्त नियोजन और विनियम: भूमि उपयोग योजना और निर्माण गतिविधियों के लिए सख्त नियमन लागू करना।

2. जल निकासी प्रणाली का आधुनिकीकरण: पुराने जल निकासी प्रणालियों का पुनर्निर्माण और नई तकनीकों का उपयोग।

3. हरित क्षेत्रों का संरक्षण: शहरी क्षेत्रों में अधिक से अधिक हरित स्थानों का संरक्षण और विकास।

4. वर्षा जल संचयन: वर्षा जल को संग्रहित करने और उपयोग करने की प्रणाली विकसित करना।

5. सार्वजनिक जागरूकता: लोगों को शहरी बाढ़ और इसके प्रभावों के प्रति जागरूक करना और उन्हें समाधान में सहभागी बनाना।

इन कदमों को उठाने से दिल्ली और एनसीआर में शहरी बाढ़ की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

प्रश्न3. बच्चे को दुलारने की जगह अब मोबाइल फोन ने ले ली है। बच्चों के समाजीकरण पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए।

मोबाइल फोन के उपयोग ने बच्चों के समाजीकरण पर कई महत्वपूर्ण प्रभाव डाले हैं। इनमें से कुछ सकारात्मक हो सकते हैं, जबकि कई नकारात्मक भी हो सकते हैं।

सकारात्मक प्रभाव:

1. सूचना का अधिक पहुंच: बच्चे इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जानकारी और शैक्षिक सामग्री तक पहुंच सकते हैं।

2. समाज से जुड़ाव: सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म बच्चों को दुनिया भर के दोस्तों और परिवार के साथ जुड़ने का मौका देते हैं।

नकारात्मक प्रभाव:

1. सीमित व्यक्तिगत संपर्क: मोबाइल फोन का अत्यधिक उपयोग बच्चों के व्यक्तिगत संपर्क को कम कर सकता है, जिससे उनके सामाजिक कौशल में कमी आ सकती है।

2. वास्तविक समाजीकरण की कमी: वर्चुअल दुनिया में अधिक समय बिताने से बच्चों में वास्तविक समाजीकरण की कमी हो सकती है, जिससे उनकी सामाजिक क्षमताओं और अनुभवों में कमी आ सकती है।

3. स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं: बच्चों में मोबाइल फोन के अत्यधिक उपयोग से आंखों की समस्याएं, नींद में कमी और शारीरिक गतिविधियों में कमी जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

4. ध्यान और एकाग्रता की समस्या: मोबाइल फोन का अत्यधिक उपयोग बच्चों की ध्यान केंद्रित करने और एकाग्रता की क्षमता को प्रभावित कर सकता है।

5. समय प्रबंधन की समस्या: मोबाइल फोन के कारण बच्चे समय प्रबंधन की समस्या का सामना कर सकते हैं, जो उनकी शिक्षा और अन्य गतिविधियों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

समाज और परिवार के स्तर पर यह महत्वपूर्ण है कि बच्चों को मोबाइल फोन के उचित उपयोग के बारे में शिक्षा दी जाए और उन्हें वास्तविक समाजीकरण के महत्व को समझाया जाए। इससे बच्चों का समग्र विकास और समाज में उनकी सकारात्मक भूमिका सुनिश्चित की जा सकती है।

प्रश्न4. जल संरक्षण और जल सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए जल शक्ति अभियान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

जल संरक्षण और जल सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए "जल शक्ति अभियान" की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

जल शक्ति अभियान की मुख्य विशेषताएं-

1. उद्देश्य:

- जल संरक्षण और जल सुरक्षा को बढ़ावा देना।
- जल संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करना।
- सूखा प्रवण और जल संकट ग्रस्त क्षेत्रों में जल आपूर्ति को बढ़ाना।

2. प्रमुख घटक:

- जल संचयन और संरक्षण: गाँवों और शहरों में जल संचयन ढाँचे का निर्माण और पुनर्वास।

QuizHat

- पानी की पुनर्चक्रण: ग्रे वॉटर प्रबंधन और पुनर्चक्रण।

- जल गुणवत्ता सुधार: पीने के पानी की गुणवत्ता में सुधार के लिए उपाय।

- वनीकरण: वनों और पौधारोपण के माध्यम से जल संचयन को बढ़ावा देना।

- बोरवेल पुनर्भरण: बोरवेल और अन्य जल निकायों का पुनर्भरण।

3. अभियान के चरण:

- पहला चरण: 256 जिलों में चयनित 1592 ब्लॉकों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

- दूसरा चरण: 2021 में सभी जिलों में विस्तार किया गया।

4. सामुदायिक भागीदारी:

- ग्राम पंचायतों, नागरिक समाज संगठनों, और अन्य स्थानीय समुदायों को अभियान में शामिल किया गया।

- जन जागरूकता कार्यक्रम और स्वच्छता अभियानों के माध्यम से लोगों को जल संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित किया गया।

5. सरकारी प्रयास:

- केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय।

- विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से अभियान का संचालन।

6. तकनीकी सहयोग:

- सैटेलाइट इमेजिंग, रिमोट सेंसिंग और अन्य तकनीकी उपकरणों का उपयोग।

- डेटा संग्रह और विश्लेषण के माध्यम से जल संसाधनों की स्थिति की निगरानी।

7. जलदूत ऐप:

- जल स्तर की निगरानी के लिए जलदूत ऐप का उपयोग, जो सामुदायिक सदस्यों को जल स्तर की रिपोर्टिंग में शामिल करता है।

जल शक्ति अभियान के लाभ

1. जल संरक्षण:

- पानी की बर्बादी को कम करना और जल संचयन को बढ़ाना।

- खेती और घरेलू उपयोग के लिए पानी की उपलब्धता में वृद्धि।

2. पर्यावरण संरक्षण:

- वनीकरण और पौधारोपण से पर्यावरण की रक्षा।

- भूजल स्तर में सुधार।

3. आर्थिक लाभ:

- कृषि उत्पादन में वृद्धि और किसान आय में सुधार।

- जल प्रबंधन में सुधार से स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव।

4. सामाजिक लाभ:

- सामुदायिक भागीदारी से सामाजिक एकता और जिम्मेदारी में वृद्धि।

- महिलाओं और बच्चों की जल-संबंधित समस्याओं का समाधान।

यह अभियान जल संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इसके सफल कार्यान्वयन से भविष्य में जल संकट की समस्याओं से निपटने में सहायता मिलेगी।

प्रश्न 5 : "पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव के बावजूद, कोयला खनन अभी भी विकास के लिए अपरिहार्य है" । चर्चा कीजिये।

कोयला खनन एक ऐसा विषय है जो विकास और पर्यावरणीय संरक्षण के बीच संतुलन की चुनौती प्रस्तुत करता है। इस संदर्भ में, "पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव के बावजूद, कोयला खनन अभी भी विकास के लिए अपरिहार्य है" इस कथन पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है।

कोयला खनन के पक्ष में तर्क:

1. आर्थिक विकास: कई विकासशील देशों में कोयला खनन से रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और गरीबी उन्मूलन में सहायक होता है।

2. ऊर्जा आपूर्ति: कोयला अभी भी विश्व की प्रमुख ऊर्जा स्रोतों में से एक है। कई देशों में ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा कोयला से आता है, जो उद्योगों और घरों को बिजली प्रदान करता है।

3. तकनीकी सीमाएं: वर्तमान में, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर और पवन ऊर्जा की तकनीक उतनी विकसित नहीं है कि वे पूरी तरह से कोयला की जगह ले सकें। इन स्रोतों की विश्वसनीयता और क्षमता को अभी भी बढ़ाने की आवश्यकता है।

4. आर्थिक मजबूरियां: कोयला की तुलना में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत महंगे हैं, और कुछ देश इन्हें अपनाने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं।

कोयला खनन के विपक्ष में तर्क:

1. पर्यावरणीय प्रभाव: कोयला खनन और इसके जलने से ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जिससे जलवायु परिवर्तन की समस्या बढ़ती है। इसके अलावा, खनन प्रक्रिया से वनों की कटाई, जल प्रदूषण, और भूमि क्षरण भी होता है।

2. स्वास्थ्य समस्याएं: कोयला खनन से उत्पन्न धूल और प्रदूषक स्थानीय समुदायों में स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देते हैं, जैसे कि श्वसन संबंधी बीमारियाँ।

3. नवीकरणीय ऊर्जा की संभावनाएं: नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर और पवन ऊर्जा में तेजी से विकास हो रहा है। इन स्रोतों को अपनाने से पर्यावरणीय क्षति कम होती है और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

4. वैश्विक प्रतिबद्धताएं: कई देश और संगठन जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में कार्बन उत्सर्जन को कम करने की प्रतिबद्धता जता चुके हैं। इस संदर्भ में, कोयला खनन का निरंतर उपयोग इस दिशा में बाधा उत्पन्न करता है।

निष्कर्ष:

"कोयला खनन विकास के लिए अपरिहार्य है" इस कथन में कुछ सच्चाई है, विशेषकर उन देशों के लिए जो विकासशील स्थिति में हैं और जिनके पास वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों में निवेश के साधन सीमित हैं। हालांकि, दीर्घकालिक दृष्टिकोण से, कोयला खनन के पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी नुकसान को कम करके वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को प्राथमिकता देना अधिक लाभकारी हो सकता है।

सरकारों और संगठनों को संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिसमें वे कोयला खनन से होने वाले लाभों और हानियों को ध्यान में रखते हुए सतत विकास की ओर अग्रसर हों।

प्रश्न 6: भारत ग्रेट निकोबार को क्यों विकसित करना चाहता है, और प्रस्तावित ग्रेट निकोबार परियोजना को संरक्षणवादियों, वन्यजीव जीवविज्ञानियों, प्रकृतिवादियों और कुछ स्थानीय जनजातीय परिषदों की ओर से लगातार आलोचना का सामना क्यों करना पड़ रहा है?

भारत द्वारा ग्रेट निकोबार को विकसित करने का उद्देश्य और प्रस्तावित परियोजना को प्राप्त आलोचनाओं का विवरण निम्नलिखित है:

ग्रेट निकोबार को विकसित करने का उद्देश्य:

1. सामरिक महत्व:

- ग्रेट निकोबार द्वीप का भौगोलिक स्थान सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, विशेषकर हिंद महासागर क्षेत्र में। यह स्थानिक सुरक्षा और समुद्री व्यापार मार्गों की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।

2. विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर:

- भारत सरकार द्वीप को विकसित करने के माध्यम से क्षेत्रीय विकास और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहती है। इसमें प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं, जैसे गहरे पानी का बंदरगाह, हवाईअड्डा, और अन्य वाणिज्यिक और आवासीय परियोजनाएं शामिल हैं।

3. पर्यटन:

- ग्रेट निकोबार में पर्यटन को बढ़ावा देने की भी योजना है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाया जा सके।

4. विकास के अन्य पहलू:

- शिक्षा, स्वास्थ्य, और अन्य सामाजिक सेवाओं के विस्तार के माध्यम से क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित करना।

आलोचनाओं के कारण:

1. पर्यावरणीय प्रभाव:

- संरक्षणवादियों और पर्यावरणविदों का मानना है कि इस परियोजना से ग्रेट निकोबार के पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर खतरा है। द्वीप के वन क्षेत्र, मैंग्रोव, और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान हो सकता है, जिससे वन्यजीवों के आवास को भी खतरा होगा।

2. जैव विविधता:

- ग्रेट निकोबार द्वीप जैव विविधता से समृद्ध है और कई दुर्लभ और स्थानिक प्रजातियों का निवास स्थान है। प्रस्तावित विकास परियोजना से इन प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है।

3. स्थानीय जनजातीय समुदाय:

- कुछ स्थानीय जनजातीय परिषदों ने परियोजना का विरोध किया है क्योंकि इससे उनके पारंपरिक जीवन और आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जनजातीय समुदायों का मानना है कि विकास परियोजना से उनके सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना को नुकसान होगा।

4. जलवायु परिवर्तन:

- प्रकृतिवादियों का तर्क है कि परियोजना से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को बढ़ावा मिल सकता है। तटीय क्षेत्रों के विकास से समुद्र के स्तर में वृद्धि और अन्य पर्यावरणीय मुद्दों का जोखिम बढ़ सकता है।

5. कानूनी और नियामक मुद्दे:

- कई संरक्षणवादी समूहों का कहना है कि परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति और आकलन प्रक्रिया में अनियमितताएं हो सकती हैं, और इससे संबंधित कानूनी और नियामक मुद्दों को उचित रूप से संबोधित नहीं किया गया है।

निष्कर्ष:

ग्रेट निकोबार को विकसित करने की योजना भारत के विकास और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन इसे संतुलित तरीके से आगे बढ़ाना आवश्यक है। परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय, सामाजिक, और सांस्कृतिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए एक सतत और समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जिससे सभी संबंधित पक्षों के हितों का संरक्षण हो सके।